वार्षिक रिपोर्ट
1990 – 91

नीपा

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना
और प्रशासन संस्थान

वार्षिक रिपोर्ट
1990-91

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
17-बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-110016

200 प्रतियां

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, 1991

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के लिए कार्यवाहक कुल सचिव, नीपा द्वारा प्रकाशित तथा शगुन कंपोजर्स, 92-बी, कृष्णा नगर, सफदर जंग इन्क्लेव, नई दिल्ली-29 में लेजर टाइप सेट होकर, प्रभात ऑफसेट प्रेस, कूचा चेलान, दरिया गंज, दिल्ली-2 में मुद्रित.

विषय सूची

अध्याय

1.	सिंहावलोकन	1
2.	प्रशिक्षण	9
3.	अनुसंधान	24
4.	परामर्शकारी और अन्य सेवाएं	43
5.	पुस्तकालय, प्रलेखन और प्रकाशन सेवाएं	46
6.	प्रशासन और वित्त	52

अनुबंध

I.	प्रशिक्षण कार्यक्रम/संगोष्ठी/कार्यशिविर	59
II.	प्रशिक्षण सामग्रियों की सूची	69
III.	नीपा विचार मंच	70
IV.	संकाय का अकादमिक योगदान	71

परिशिष्ट

I.	नीपा परिषद के सदस्य	83
II.	कार्यकारी समिति के सदस्य	86
III.	वित्त समिति के सदस्य	88
IV.	कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्य	89
V.	संकाय तथा प्रशासनिक स्टाफ	92
VI.	वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट	97

1990-91

अध्याय 1

सिंहावलोकन

एक स्वायत्त संस्था के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान की स्थापना वर्ष 1970 में की गई थी। पहले इसे राष्ट्रीय स्टाफ कालेज के नाम से जाना जाता था। इस संस्थान का आरंभ वर्ष 1962 से माना जा सकता है, जब भारत सरकार ने यूनेस्को के साथ एक अनुबंध के द्वारा एशिया क्षेत्र के वरिष्ठ शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के प्रशिक्षण के लिए एशियाई शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान की स्थापना की थी।

अपने अस्तित्व के तीन दशकों के दौरान एक शीर्ष संस्था के रूप में नीपा ने शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका अदा की है। अनुसंधान परियोजनाओं समेत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए निम्न अकादमिक एककें हैं : (I) शैक्षिक योजना एकक; (II) शैक्षिक प्रशासन एकक; (III) शैक्षिक वित्त एकक; (IV) शैक्षिक नीति एकक; (V) विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा एकक; (VI) उच्च शिक्षा एकक; (VII) प्रादेशिक प्रणाली एकक, और (VIII) अंतर्राष्ट्रीय एकक।

संस्थान के प्रमुख कार्य निम्न हैं : शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों का प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्शकारी और सलाहकारी सेवाएं, नवाचारों का प्रसार और अन्य देशों, विशेषकर एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों तथा यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना।

इस रिपोर्ट में संस्थान के वर्ष 1990-91 की प्रमुख गतिविधियां शामिल हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशिविर/संगोष्टी/डिप्लोमा पाठ्यक्रम

इस वर्ष संस्थान में 50 प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशिविर/संगोष्ठियां और 2 डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोजित किए गए।

भागीदारी

इस वर्ष भागीदारों की कुल संख्या 1060 थी। भागीदार विभिन्न संवर्गों से थे। इनमें राज्यों/संघीय राज्यों से 856 भागीदार शामिल हुए। भारत सरकार, योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विभिन्न विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय स्तर के संगठनों से 116 अधिकारी शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य देशों से 88 भागीदार आए।

क्षेत्रवार भागीदारी में उत्तरी क्षेत्र के सबसे अधिक 318 भागीदार थे। इसके बाद दक्षिण क्षेत्र के 207, पूर्वी क्षेत्र के 184 और पश्चिमी क्षेत्र के 147 भागीदार शामिल हुए।

राज्यवार भागीदारी में सर्वोच्च स्थान राजस्थान (116) का था। इसके बाद क्रमशः आंध्रप्रदेश (102), दिल्ली (72), गुजरात (67), उत्तर प्रदेश (52), मध्यप्रदेश (41), तमिलनाडु (39) और महाराष्ट्र (33) थे।

शैक्षिक रूप से पिछड़े 10 राज्यों से 432 अधिकारी शामिल हुए जो कि कुल भागीदारी का 50.47% है।

1990-91

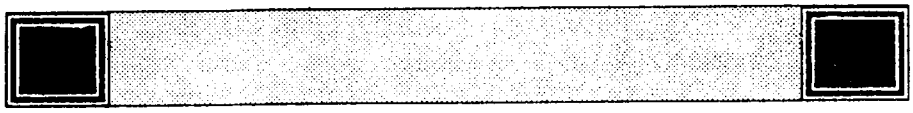

डिप्लोमा पाठ्यक्रम

(अ) राष्ट्रीय डिप्लोमा : दसवां डिप्लोमा पाठ्यक्रम के तीसरे चरण से संबंधित परियोजना रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण का कार्य जुलाई 1990 में संपन्न हुआ। सफल भागीदारों को डिप्लोमा की उपाधियां प्रदान की गईं। ग्यारहवां डिप्लोमा कार्यक्रम नवंबर 1990 में शुरू हुआ। इसमें 8 राज्यों—असम, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मिज़ोरम, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और संघीय राज्य दिल्ली के अधिकारी शामिल हुए।

(ब) अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा : छठवां चालू अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम जो वर्ष 1989-90 में शुरू हुआ था, संपन्न हुआ। सातवां अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू हुआ जिसमें 14 देशों—अफगानिस्तान, क्यूबा, गांबिया, केन्या, मालावी, मॉरिशस, नामीबिया, नाइजीरिया, सेनेगल, श्रीलंका, उगांडा, जांबिया और जिंबाबवे के अधिकारी शामिल हुए।

संस्थान के नियमित कार्यक्रमों में निम्न शामिल थे :

(I) जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के योजना और प्रबंध संभाग के अकादमिक अधिकारियों के लिए दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम,

(II) महिला प्रशासकों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में दो सप्ताह का अभिविन्यास कार्यक्रम,

(III) वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासकों के लिए तीन सप्ताह का अभिविन्यास कार्यक्रम,

(IV) कालेज के प्राचार्यों के लिए तीन सप्ताह का अभिविन्यास कार्यक्रम,

(V) प्रौढ़ शिक्षा की योजना और प्रबंध पर छः सप्ताह का अभिविन्यास कार्यक्रम

वर्ष के अन्य विषयक कार्यक्रम

वर्ष 1990-91 के दौरान विभिन्न विषयक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इनमें प्रमुख थे— समष्टि स्तरीय योजना, विद्यालय मानचित्रण, सांस्थानिक योजना अनौपचारिक व प्रौढ़ शिक्षा, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों की योजना और प्रबंध और दूरवर्ती शिक्षा।

शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के लिए पर्यावरण शिक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसे यूनेस्को-यू.एन.इ.पी. ने प्रायोजित किया था।

अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय और सूचना परामर्श केंद्र के सहयोग से पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए सूचीकरण, सारांशीकरण और पुनःप्राप्ति विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।

चीन और श्रीलंका के प्रतिनिधियों के लिए भ्रमण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

प्रशिक्षण प्रविधि

सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर-शास्त्रीय प्रवृत्ति के थे। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंग थे—प्रायोगिक कार्य, सामूहिक कार्य, केस अध्ययन, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, संगणक, फिल्म, वीडियो और प्रोजेक्टर का प्रयोग।

मूल्यांकन

प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन किया जाता है। जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए छःमाही डिप्लोमा कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा जैसे लम्बी अवधि के कार्यक्रमों का सतत् मूल्यांकन किया जाता है।

1990-91

प्रशिक्षण सामग्री

प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रयोग और व्यापक प्रसार के लिए शैक्षिक योजना और प्रबंध से संबंधित लगभग 23 माड्यूल, आलेख और सांख्यिकीय आंकड़े तैयार किए गए।

अनुसंधान

इस वर्ष 10 अनुसंधान अध्ययन पूरे किए गए। 17 अध्ययनों के कार्य जारी हैं। 5 नए अध्ययन स्वीकृत किए गए। इनमें 3 सह-अध्ययन हैं और 2 अध्ययन नीपा सहायता योजना के तहत प्रायोजित अध्ययन हैं।

पूरे किए गए अध्ययन

1. वर्ष 2000 में शिक्षा—दीर्घावधि संप्रेक्ष्य
2. भारत में साक्षरता—क्षेत्रकालिक विश्लेषण (1901-1981)
3. हरियाणा के गुड़गांव जिले के पुनहांना प्रखंड में शैक्षिक योजना और प्रशासन तथा प्रौढ़ और प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण में रणनीतियों के क्रियान्वयन का अध्ययन के लिए क्रियात्मक अनुसंधान (तीसरा चरण)
4. महाराष्ट्र की शिक्षा और विकास पर मोनोग्राफ
5. महिला कालेजों के प्रशासकों के प्रशिक्षण की जरूरत की शिनाख्त (नीपा—एस.एन.डी.टी. विश्वविद्यालय) (सह-अध्ययन)
6. उच्च शिक्षा में विद्यमान सुविधाओं/संसाधनों के प्रभावी उपयोग का अध्ययन
7. जिला शैक्षिक प्रशासकों का कार्यवृत्त—राष्ट्रीय अध्ययन
8. जि. शि.अ. के डिप्लोमा पाठ्यक्रम की पुनर्रचना के संदर्भ में वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासकों और जिला शिक्षा अधिकारियों के दृष्टिकोणों का अध्ययन
9. दूरवर्ती शिक्षा की कक्षावार लागत का अध्ययन (नीपा सहायता योजना के अंतर्गत)
10. औपचारिक विश्वविद्यालयों के ढांचे के तहत दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली के गठन और संकाय की संरचना का अध्ययन (नीपा सहायता योजना के अंतर्गत)

जारी अध्ययन

1. कालेजों के प्रभावी कार्य और विकास : एक क्रियात्मक अनुसंधान अध्ययन (दूसरा चरण)
2. विद्यालय मानचित्रण पर परियोजना
3. द्वितीय अखिल भारतीय शैक्षिक प्रशासन सर्वेक्षण
4. लैटिन अमरीका में अनौपचारिक शिक्षा की योजना और प्रबंध का अध्ययन : निहितार्थ और भारत के लिए सबक
5. भारत में अनुसूचित जातियों और गैर अनुसूचित जातियों के साक्षरता स्तर के बीच की विषमताओं का जिलेवार विश्लेषण
6. शैक्षिक संस्थानों में स्वायत्तता का प्रबंध : स्वायत्त कालेजों का अध्ययन
7. संगणकीकृत योजना और प्रारंभिक शिक्षा (शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित)
8. जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए संचारेक्षण सूचना प्रणाली (शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित)
9. भारत के शैक्षिक विकास में क्षेत्रीय विषमताएं — आधारभूत स्तर पर सामाजिक कल्याण के संदर्भ में शैक्षिक विषमताओं की जांच-पड़ताल
10. शिक्षा में संसाधनों का प्रभावी उपयोग — एक केस अध्ययन

1990-91

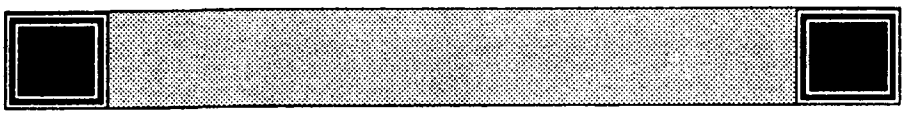

11. आदिवासी और उप-योजना क्षेत्र के शैक्षिक विकास का अध्ययन
12. कालेजों के विकास में कालेज विकास परिषदों की भूमिका का अध्ययन : चुने हुए 10 कालेज विकास परिषदों का गहन अध्ययन
13. बेसिक शिक्षा सेवा की गुणवत्ता (नीपा—आई.आई. इ.पी.) (सह अध्ययन)
14. भारतीय विश्वविद्यालयों का वित्तीय प्रबंध (नीपा सहायता योजना के अंतर्गत)
15. भारत के वर्तमान पत्राचार संस्थानों में शिक्षण और अधिगम के प्रबंध के लिए अपनाई जाने वाली मूल्यांकन प्रणाली का आलोचनात्मक मूल्यांकन (नीपा सहायता योजना के अंतर्गत)
16. तमिलनाडु में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रबंध (नीपा सहायता योजना के अंतर्गत)
17. भारत में कृषि स्नातकों के रोजगार के अवसर : राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर का लाभ-लागत अध्ययन (नीपा सहायता योजना के अंतर्गत)

स्वीकृत नए अध्ययन

1. प्रारंभिक शिक्षा के संचारेक्षण का अध्ययन (शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित)
2. शैक्षिक सांख्यिकी में प्रतिदर्श सर्वेक्षण तकनीकों का प्रयोग
3. उत्तरप्रदेश में सबके लिए बेसिक शिक्षा (विश्व बैंक परियोजना)
4. मूल्यगत दृष्टिकोण और पहाड़ी बोंडा की भागीदारी
5. मेघालय और मिज़ोरम की साक्षरता स्थिति में योगदान करने वाले कारकों का पायलट अध्ययन

प्राथमिकता वाले प्रशिक्षण के क्षेत्र

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, जैसे — सबके लिए शिक्षा, व्यष्टि स्तरीय योजना, विद्यालय मानचित्रण, सांस्थानिक योजना और मूल्यांकन, अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा, सामुदायिक भागीदारी, लैब-एरिया प्रणाली, जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थानों की योजना और प्रबंध, पिछड़े व सुविधा वंचित वर्ग, विकलांग बच्चे, पर्यावरण शिक्षा और अकादमिक स्टाफ कालेजों के विकास आदि पर विशेष बल दिया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से संबंधित अनेक विषयों पर अनुसंधान कार्य शुरू किए गए।

नीपा विचारमंच

नीपा विचारमंच शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मसलों पर विचारों के आदान-प्रदान का एक व्यावसायिक मंच है। इससे संकाय के सदस्यों को शिक्षा के आधारभूत मसलों और लक्ष्यों से संबंधित संकल्पनाओं और सैद्धांतिक आधारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है तथा इससे उनके सोच और समझ में व्यापक विकास होता है। इस वर्ष के दौरान 6 विचारमंच आयोजित किए गए जिनमें प्रमुख विद्वानों, जैसे—श्री हेडपाल अहमद, निदेशक, यूनेस्को कार्यालय, बैंकाक और प्रो.पी.जी.अल्टबाख, निदेशक, तुलनात्मक शिक्षा केंद्र, न्यूयार्क ने अपने विचार रखे।

विचारमंच के विषयों की सूची अनुबंध - III में दी गई है।

शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों का राष्ट्रीय रजिस्टर

संस्थान ने अभ्यास के तौर पर शैक्षिक योजना और प्रबंध से संबद्ध संसाधन व्यक्तियों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने का कार्य शुरू किया है।

1990-91

विशेषज्ञ समिति के सलाह पर राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने के उद्देश्य से जरूरी सूचनाएं एकत्र करने के लिए एक प्रपत्र विकसित किया गया था। कुछ राष्ट्रीय अखबारों में इसकी अधिसूचना भी जारी की गई थी।

अधिसूचना के जवाब में पूर्ण रूप से भरे हुए 1200 प्रपत्र प्राप्त हुए जिन्हें संगणक में संगृहीत किया जा रहा है और राष्ट्रीय रजिस्टर का एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है।

प्रकाशन

संस्थान ने निम्नांकित प्रकाशन निकाले :

प्रकाशित

1. स्कूल एंड रूरल ट्रांसफार्मेशन—मुनिस रज़ा और एच. रामचंद्रन (मूल्य रु. 100/- विकास पब्लिशिंग हाउस)

2. इनवायर्मेंटल एजुकेशन हैंड बुक फार एजुकेशनल प्लानर्स—सत्यभूषण, आर. गोविंद और ए मंगलागिरि (मूल्य रहित)

3. स्कूल एजुकेशन इन इंडिया : द रिजनल डायमेंशन — मुनिस रज़ा, ए. अहमद और एस.सी.नूना (मूल्य रहित)

4. मिनिस्ट्री आफ एजुकेशन — एन आर्गेनाइजेशनल हिस्ट्री — ए मैथ्यू (मूल्य रहित)

5. वोमेन एंड डेवलपमेंट — एस.सी. नूना (मूल्य रहित)

6. डेवलपमेंट आफ एजुकेशन इन इंडिया 1989-90 : नेशनल रिपोर्ट आफ इंडिया फार आई.सी.ई. (मूल्य रहित)

जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन

निम्नांकित विषयों पर जर्नल के विशेषांक प्रकाशित किए गए :

1. प्लानिंग एंड मैनेजमेंट आफ एजुकेशन इन थर्ड वर्ल्ड
2. एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन
3. एजुकेशन आफ द वर्किंग चिल्ड्रेन

4-5 जर्नल का हिंदी रूपांतरण — दूरवर्ती शिक्षा विशेषांक और तीसरी दुनिया में शिक्षा की योजना और प्रबंध विशेषांक

प्रेस में

निम्नांकित प्रकाशन प्रेस में हैं :

1. एजुकेशन फार आल : ए ग्राफिक प्रजेंटेशन

2. रिपोर्ट आफ द इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेमिनार ऑन इनवायर्मेंटल एजुकेशन फार एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स (22-26 अप्रैल, 1990)

मिमियोग्राफ प्रकाशन

संस्थान ने अनेक अनुसंधान अध्ययनों, आकस्मिक पत्रों और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रिपोर्टों के मिमियोग्राफ प्रकाशित किए।

पुस्तकालय

संस्थान के पुस्तकालय में छुट्टियों समेत पूरे वर्ष विद्वानों, छात्रों और प्रशिक्षुओं को पर्याप्त रूप में पुस्तकालय और प्रलेखन सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों

1990-91

और सम्मेलनों की रिपोर्टों के अलावा संस्थान में वर्तमान में 44, 578 पुस्तकों का संग्रह है। शैक्षिक योजना प्रशासन और प्रबंध तथा संबंधित अन्य दूसरे क्षेत्रों से संबंधित क्षेत्रों की 350 पत्रिकाएं पुस्तकालय में मंगाई जाती हैं। वर्तमान में प्रलेखन केंद्र में राज्य और जिला स्तर की शैक्षिक योजना और प्रशासन से संबंधित 12,000 दस्तावेजों का संग्रह है।

संगणक केंद्र

संस्थान का संगणक केंद्र विभिन्न प्रकार के आई. बी. एम. संगणकों से सुसज्जित है। संगणक केंद्र में 4 पी. सी. -ए.टी. 12 पी.सी.-एक्स. टी., एक पी.सी./ए.टी.-386 प्रणाली और एक लेजर प्रिंटर तथा 8 प्रिंटर हैं।

इसके अलावा संगणक केंद्र में प्रोग्रामिंग के लिए नवीनतम पी. सी. आधारित साफ्टवेअर पैकेज, जैसे-लोट्स 1-2-3 (Rel. 3) (डी. बेस IV, एस. पी. एस. एस पीसी+ (Ver. 3) और वर्डस्टार (Rel. 6) भी उपलब्ध हैं। फारहन और पासकल के भाषा संकलन भी प्रयोग में लाए जाते हैं।

कार्मिक

संस्थान में काडर योजना नीति का पालन किया गया। अकादमिक क्षमता में विकास करना तथा प्रशासनिक काडर को कम करना इस नीति का उद्देश्य है। दिनांक 31 मार्च, 1991 को संस्थान में कार्मिकों की कुलसंख्या 178 थी। इसके अलावा परियोजनाओं के लिए निर्धारित अवधि की नियुक्ति के तहत 50 परियोजना स्टाफ भी थे।

परिसर विकास

दिल्ली अग्नि शमक सेवा की सलाह के अनुसार संस्थान के भवन और नीपा अतिथि गृह में अग्नि शमन की सुविधाएं बढ़ाई गईं।

टाइप IV के आठ क्वार्टरों का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है।

वित्त

इस वर्ष सरकारी अनुदान से कुल 191.40 लाख रुपये (योजना और योजनेतर दोनों ही) खर्च हुए जबकि 1989-90 के दौरान यह खर्च 144 लाख रुपए था। इसके अलावा अन्य संगठनों द्वारा प्राप्त सहायता राशि के कार्यक्रमों और अध्ययनों पर 35.63 लाख रुपए खर्च हुए। अतः इस वर्ष सरकारी अनुदान और अन्य संगठनों से प्राप्त सहायता राशि से कुल 227.53 लाख रुपए खर्च हुए।

सलाहकारी, परामर्शकारी और समर्थन सेवाएं

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कार्यवाही योजना और नीति कार्यान्वयन की तैयारी के दौरान संस्थान को इस महत्वपूर्ण कार्य से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों और विभिन्न अधिकरणों के साथ अपने-अपने अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए एक सुनहरा अवसर मिला।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संकल्प फा. सं. 1-6/90-पी. एन(डी-1) दिनांक 7.5. 1990 द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में गठित समीक्षा समिति को संस्थान ने अकादमिक और अन्य जरूरी सेवाएं प्रदान किए।

संस्थान ने निम्न की स्थापना के लिए मार्गदर्शिकाएं तैयार किए : राज्य शिक्षा सलाहकार समिति, जिला शिक्षा परिषद, ग्रामीण शिक्षा समिति, राज्य शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान और नवोदय विद्यालय। संस्थान ने व्यष्टि स्तरीय योजना, विद्यालय मानचित्रण, विद्यालय संघटन और ग्रामीण शिक्षा समिति के लिए भी मार्गदर्शिकाएं तैयार किए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्यान्वयन योजनाओं के निर्माण में संस्थान ने राज्यों को व्यावसायिक सेवाएं मुहैया की। मानव

1990-91

संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग), योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालयों को प्राथमिकता वाली उनकी विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में संस्थान ने अपनी व्यावसायिक सेवाएं प्रदान किए।

इसके अलावा संस्थान में संकाय के सदस्यों ने प्रशिक्षण और अनुसंधानात्मक गतिविधियों में अन्य दूसरे अकादमिक और व्यावसायिक निकायों को उनके अकादमिक समितियों/प्रतिनिधि मंडलों के सदस्य के रूप में तथा अपने प्रकाशित अनुसंधानात्मक आंकड़े और विशेष क्षेत्रों में प्रकाशित पुस्तकों के माध्यम से अकादमिक सहयोग दिए।

नीपा की गतिविधियों की समीक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) ने नीपा के कार्य और प्रगति की समीक्षा के लिए दिनांक 15.3.1989 को समीक्षा समिति का गठन किया था। समिति ने अपना कार्य पूरा करके 6 सितंबर, 1989 को केंद्रीय शिक्षा सचिव को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी।

समीक्षा समिति की संस्तुतियों की समीक्षा साधिकारी समिति ने की। इसका गठन उक्त कार्य के लिए ही किया गया था। साधिकारी समिति के निर्णयों पर भारत सरकार के अनुमोदन के बाद जनवरी, 1991 को यह रिपोर्ट नीपा को प्राप्त हुई।

लक्ष्यों के संदर्भ में नीपा के कार्यों पर समीक्षा समिति के कुछ महत्वपूर्ण परीक्षण निम्न हैं :

> शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न क्रियाकलापों के लिए संस्थान ने व्यापक सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया है। इनमें रणनीति निर्धारण करने वाले कार्मिकों जैसे—जिला शिक्षा अधिकारियों, प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों तथा वरिष्ठ विश्वविद्यालय कार्मिकों को शामिल किया गया है। केवल शैक्षिक योजनाकारों, और प्रशासकों के विभिन्न वर्ग तक ही प्रशिक्षण कार्यक्रम सीमित नहीं हैं बल्कि इनमें सभी क्षेत्रों, राज्यों और संघीय राज्यों की भागीदारी हुई है। यह उल्लेखनीय है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सभी राज्यों, संघीय राज्यों की भागीदारी हुई है और कुछ भागीदारों से प्राप्त पुनर्निशेन और विचार-विमर्श से प्रतिभागियों को लाभ हुआ है । . . .

नीपा के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन भागीदारों ने किया है और स्वतंत्र रूप से भी कराया गया है। यह सामान्य निष्कर्ष निकला हैं कि कार्यक्रमों के अधिकतम लक्ष्यों को पूर्ति हुई है। अतः मूल्यांकन के नतीजे उत्साहवर्धक हैं। नीपा द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने काफी सराहा है।...

नीपा ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण सामग्रियां व माड्यूल तैयार किए हैं और इस क्षेत्र में प्रशंसनीय कदम उठाए हैं। अतः इसके लिए नीपा को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। इससे जाहिर होता है कि प्रशिक्षण के क्षेत्र में नीपा एक अग्रणी संस्थान की भूमिका की ओर लगातार बढ़ रहा है।...

हाल के वर्षों में शुरू किए गए अनुसंधान अध्ययनों और अनेक अध्ययनों पर संस्थान ने विशेष ध्यान दिया है। यह देखने में आया है कि यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसे शीर्षस्थ संस्थानों ने इन प्रयासों के लिए योगदान दिया है। इससे संस्थान का आत्मबल बढ़ा है और जाहिर है कि यह संस्थान उक्त चोटी के संस्थानों की तरह अग्रगामी हो गया है।...

राष्ट्रीय शिक्षक आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग, राज्य सरकारों राज्य लोक प्रशासन संस्थानों और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों को अकादमिक और व्यावसायिक समर्थन सेवाएं प्रदान करने में नीपा पूरी तरह सक्षम है। एक दूसरा महत्वपूर्ण विकास यह है कि शैक्षिक योजना और प्रशासन

1990-91

के क्षेत्र में नीपा को एक व्यावसायिक संस्थान के रूप में मान्यता मिल रही है और राज्य सरकारें अन्य व्यावसायिक व अकादमिक संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसकी परामर्शकारी सेवाएं ले रहे हैं।...

अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तार संबंधी सूचनाओं और विचारों के संशोधन गृह के रूप में नीपा का संतत विकास हो रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नीपा "शैक्षिक योजना और प्रशासन" नामक जर्नल का हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशन कर रहा है। अपने विषय से संबंधित अनेक मसलों पर संस्थान ने अनेक दस्तावेज निकाले हैं। शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में नीपा के कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन विद्वानों और अकादमिक विशेषज्ञों को आकृष्ट किए हैं ...

संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किए हैं। यह बहुत सराहनीय है कि नीपा एशिया, प्रशांत क्षेत्र और मध्यपूर्वी तथा अफ्रीकी देशों के कार्मिकों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। इन कार्यक्रमों की अंतर्राष्ट्रीय निकायों ने सराहना की है और इन्हें उच्च कोटि का माना है।...

अंततः राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में नीपा के अमूल्य योगदान से समिति बहुत प्रभावित हुई है। वास्तव में इस कार्य में संस्थान के विशेष अकादमिक योगदान की क्षमता अपूर्व सिद्ध हुई है और संस्थान के संकाय, जिन पर भारत सरकार ने इस कार्य की जिम्मेवारी सौंपी थी... समिति का विचार है कि संस्थान अपने निदेशकों की उत्तम कोटि के नेतृत्व और संकाय तथा स्टाफ के प्रतिबद्ध प्रयास से अपने लक्ष्यों की व्यापक पूर्ति में सफल रहा है। यद्यपि गतिविधियों के कई व्यक्तिगत क्षेत्रों में पुनः विकास कार्य अपेक्षित है फिर भी समग्र रूप से अपने क्षेत्र में नीपा का योगदान उल्लेखनीय है। इसके कार्यों की महत्ता सिर्फ केंद्रीय सरकार व राज्य सरकारों और अभिकरणों ने ही नहीं स्वीकार किए हैं बल्कि देश और विदेश में स्थित सहयोगी अकादमिक संस्थानों ने भी इसके कार्यों को मान्यता दी है।...

नीपा के पिछले पांच वर्षों की गतिविधियों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रशिक्षण, अनुसंधान और सलाहकारी सेवाओं के लक्ष्यों की पूर्ति में संस्थान सफल रहा है और इनमें प्रशिक्षण को वरीयता दी गई है। समिति ने नीपा को निम्नांकित चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने के लिए सुझाव दिया है : "शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में एक समृद्ध 'संसाधन केंद्र' और 'विचार भंडार' के रूप में विकास करना, प्रायोगिक तथा मौलिक अध्ययन शुरू करना, अन्य संगठनों के साथ परस्पर सहयोग और विचारों के आदान-प्रदान से विकास करना, शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों की क्षमताएं बढ़ाने के लिए संकाय द्वारा किए गए नवाचारों और शोध अध्ययनों का प्रचार-प्रसार करना, संकाय के एक सदस्य के बजाए तीन सदस्यों को शामिल करके नीपा परिषद के आकार में वृद्धि करना, निम्न को शामिल करके कार्यकारिणी समिति मजबूत बनाना (1) राज्य सरकार का एक निदेशक और राज्य शिक्षा संस्थान का एक निदेशक, (ii) नीपा के निदेशक की मदद के लिए नीपा परिषद में संकाय के तीन सदस्यों में से दो की कार्यकारिणी में शामिल करना, नीपा के मामलों के प्रबंध में संकाय की भागीदारी बढ़ाना, कार्यक्रम सलाहकारी समिति को योजना और कार्यक्रम समिति के रूप में नया नाम देना जो कि संस्थान के विभिन्न कार्यक्रमों की स्वीकृति देगी और अंतिम रूप से उनका मूल्यांकन करेगी, संकाय और कार्यकारिणी के बीच संपर्क बनाने के साथ-साथ यह समिति संकाय के लिए "विचार भंडार" का कार्य भी करेगी यह समिति छोटी और लंबी अवधि की अकादमिक योजनाएं और संप्रेक्ष्य भी तय करेगी, संकाय द्वारा आयोजित किए गए अनुसंधानों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण सामग्रियों का वार्षिक संकलन तैयार करना और उसका अध्ययन करके कार्य के क्षेत्र और कमियां प्रकाश में लाना।

समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

1990-91

अध्याय 2

प्रशिक्षण

अपनी गतिविधियों में प्रमुख रूप से विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों की क्षमता का विकास करते हुए नीपा ने प्रशिक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पच्चीस वर्षों से नीपा शिक्षाकर्मियों के प्रशिक्षण का कार्य कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए संस्थान अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ सहयोग करता है। निम्नांकित प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है :

(i) शैक्षिक योजना के बदलते हुए परिप्रेक्ष्य से प्रतिभागियों को उनकी भूमिका तथा उनके कार्यों से अवगत कराना।

(ii) अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों/वरिष्ठ स्तरीय प्रशासकों/नीति योजनाकारों के साथ अनुभवों तथा नए विकासों का आदान प्रदान करना।

(iii) केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा चलायी गयी विशिष्ट योजनाओं के लिए शैक्षिक योजना और प्रबंध में अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करना।

(iv) शिक्षा की योजना तथा प्रशासन की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए उसकी सुविधा के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में प्रणालीकृत पाठ्यक्रमों को आयोजित करना।

(v) संस्थान के संकायों द्वारा प्रशिक्षण गतिविधियों को अनुसंधान, विस्तार तथा परामर्शकारी सेवाओं से लैस करना।

(vi) शैक्षिक योजना और प्रबंध से संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा के विश्वविद्यालयीय विभागों और राज्य तथा क्षेत्रीय स्तर के संस्थाओं के साथ नेटवर्क स्थापना।

प्रत्येक वर्ष, विभिन्न राज्य सरकारों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राज्य शिक्षा संस्थान, मंडल शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान तथा शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं के मूल्यांकन के लिए नीपा व्यापक अभ्यास करता है। राज्य सरकार तथा अन्य अभिकरणों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

सभी प्रशिक्षण कार्य नीपा में ही आयोजित किए जाते हैं। किंतु यदि आवश्यकता पड़ी तो अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर राज्य विषयक पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। नीपा की प्रशिक्षण रणनीति के अंतर्गत प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की तरफ अधिक ध्यान दिया जाता है। काफी संख्या में आत्म अधिगम माड्यूल तैयार किए गए हैं जिनका उपयोग राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान अथवा इसकी समाप्ति पर प्रतिभागियों से प्राप्त औपचारिक तथा अनौपचारिक सूचनाओं का भी विशेष महत्व है।

वर्ष के दौरान किए गए पुनरीक्षण से पता चला है कि संस्थान ने 52 प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशिविर/तथा विभिन्न अवधियों की संगोष्ठियां आयोजित की हैं। संस्थान द्वारा आयोजित डिप्लोमा कार्यक्रम का महत्व अभी भी जारी है और वर्ष के दौरान दो ऐसे कार्यक्रम (एक राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए) शुरू

1990-91

किए गए। इसके अलावा पिछले वर्ष शुरू किए गए दो डिप्लोमा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किए गए। वर्ष के दौरान 1060 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। इन 1060 प्रतिभागियों में 856 राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश कैडर के हैं। भारत सरकार के विभिन्न विभागों संगठनों के 116 प्रतिभागी हैं और शेष 88 अन्य देशों के हैं।

भागीदारी

अनुबंध I में, कार्यक्रमों की सूची, अवधि तथा प्रत्येक कार्यक्रम के भागीदारों की संख्या का पूरा विवरण दिया गया है। तालिका 1 में इसका संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

(अ) राष्ट्रीय

तालिका 2, 3 और 4 में क्रमानुसार राज्यवार, क्षेत्रवार तथा स्तरवार भागीदारी से संबंधित विवरण दिया गया है। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि :

- संस्थान के विभिन्न कार्यक्रमों में देश के सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश ने हिस्सा लिया।
- 50% से भी अधिक भागीदार शैक्षिक रूप से पिछड़े दस राज्यों विशेषतया आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल से है।
- क्षेत्रवार, उत्तरी क्षेत्र की भागीदारी (318) सबसे अधिक थी, इसके बाद दक्षिणी क्षेत्र (208), पूर्वी क्षेत्र (184) और पश्चिमी क्षेत्र (147) थे।
- राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशों के अतिरिक्त, भारत सरकार तथा अन्य राष्ट्रीय संस्था जैसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय से 116 अधिकारियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

तालिका 1

कार्यक्रमों का वर्गीकरण

कार्यक्रमों का वर्गीकरण	कार्यक्रमों की संख्या	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रम व्यक्ति दिन
I. डिप्लोमा कार्यक्रम				
राष्ट्रीय डिप्लोमा	1	185	38*	2696
अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा	1	182	43*	3724

1990-91

कार्यक्रमों का वर्गीकरण	कार्यक्रमों की संख्या	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रम व्यक्ति दिन
II. विषयक कार्यक्रम				
विद्यालय प्रधानाचार्य के लिए कार्यक्रम	6	23	133	531
जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की योजना और प्रबंध	4	48	117	1529
विद्यालय शिक्षा की योजना और प्रबंध	7	43	166	817
सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा और व्यष्टि स्तरीय योजना	4	14	83	266
विद्यालय मानचित्रण	2	6	19	57
अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा	3	51	90	1900
उच्च शिक्षा	4	31	106	930
वित्त प्रबंध	2	10	19	95
संगणक प्रयोग	3	51	42	502
परिमाणात्मक तकनीक	1	12	2	24
दीर्घावधि योजना/स्थानीय योजना	3	10	71	237
रोजगार योजना और व्यावसायिक शिक्षा योजना	2	7	19	69

1990-91

कार्यक्रमों का वर्गीकरण	कार्यक्रमों की संख्या	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रम व्यक्ति दिन
वंचित वर्ग/विकलांग/महिलाओं के लिए शिक्षा की योजना और प्रबंध	3	19	31	274
अखिल भारतीय सर्वेक्षण	2	5	21	57
पर्यावरण शिक्षा की योजना	1	5	17	85
दूरवर्ती शिक्षा	1	4	10	40
पुस्तकालय और सूचना प्रबंध	1	6	28	168
अन्य	1	5	5	25
कुल योग	**52**	**717**	**1060**	**14026**

* इस सूची में पहले से चल रहे एक राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम शामिल नहीं किए गए हैं।

तालिका 2

राष्ट्रीय भागीदारी

क्र.सं.	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश/अन्य संगठन	भागीदारी
1.	आंध्र प्रदेश @	102
2.	अरुणाचल प्रदेश @	5
3.	असम @	31

1990-91

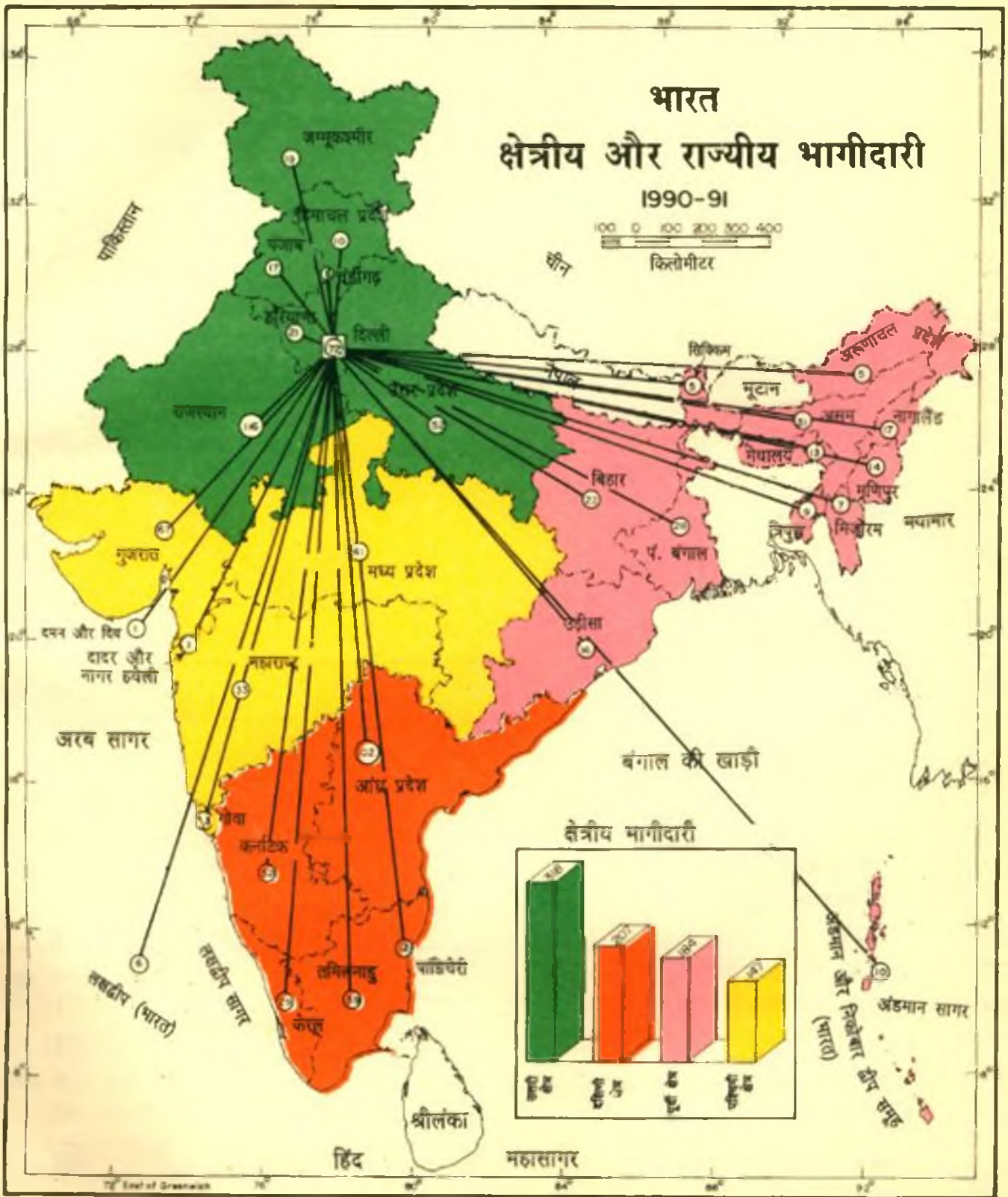

NIEPA/P. N. Tyagi/92

1990-91

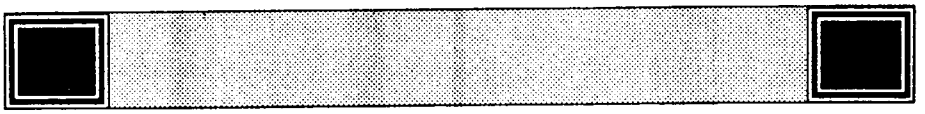

क्र.सं.	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश/अन्य संगठन	भागीदारी
4.	बिहार @	22
5.	गुजरात	67
6.	गोवा	3
7.	हरियाणा	21
8.	हिमाचल प्रदेश	10
9.	जम्मू और कश्मीर @	19
10.	कर्नाटक	32
11.	केरल	29
12.	मध्यप्रदेश @	41
13.	महाराष्ट्र	33
14.	मणिपुर	14
15.	मेघालय	13
16.	मिज़ोरम	7
17.	नागालैंड	17
18.	उड़ीसा @	16
19.	पंजाब	17
20.	राजस्थान @	116
21.	सिक्किम	5
22.	तमिलनाडु	39
23.	त्रिपुरा	9
24.	उत्तर प्रदेश @	52
25.	पश्चिम बंगाल @	28
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10
27.	चंडीगढ़	6
28.	दादरा और नागर हवेली	1
29.	दिमन और दिव	1
30.	दिल्ली	72
31.	लक्षद्वीप	6
32.	पांडिचेरी	12
	योग	**856**

भारत सरकार तथा अन्य संगठन	116
कुल योग	**972**

@ शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्य

तालिका 3

क्षेत्रवार भागीदारी

क्षेत्र	**भागीदारी**
उत्तरी क्षेत्र	318
दक्षिणी क्षेत्र	207
पूर्वी क्षेत्र	184
पश्चिमी क्षेत्र	147
योग	**856**
भारत सरकार तथा अन्य	116
कुल योग	**972**

तालिका 4

स्तरवार भागीदारी

स्तर	**भागीदारी**
विद्यालय प्रधानाध्यापक	127
जिला शिक्षा अधिकारी	28
अन्य विद्यालय कार्मिक	371
प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी	41

अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी 1990-91

NIEPA/P.N.Tyagi/[illegible]

स्तर	भागीदारी
वित्त अधिकारी	6
सांख्यिकी अधिकारी	19
कालेज प्राचार्य	55
अन्य विश्वविद्यालय कार्मिक	106
भारत सरकार और अन्य संगठनों के कार्मिक	219
योग	**972**

ब. अंतर्राष्ट्रीय

संस्थान के विभिन्न कार्यक्रमों में 26 देशों से कुल 73 भागीदार शामिल हुए। इनमें छठवें और सातवें डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के सभी 43 भागीदार शामिल हैं। नीपा द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में पांच अंतर्राष्ट्रीय संगठनों—आई.सी.ए.ई., आई.आई.इ. पी., यूनेस्को, यूनीसेफ और विश्व बैंक से 15 विशेषज्ञ भी शामिल हुए। तालिका 5 में देशवार अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी संबंधी विवरण दिया गया है।

तालिका 5

अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी

देश व अंतर्राष्ट्रीय निकायों के नाम	भागीदारों की संख्या
अफगानिस्तान	1
चीन	4
क्यूबा	1
गांबिया	1
जर्मनी	1
ईरान	12
केन्या	1
लाओस गणराज्य	4
मलेशिया	3
मालावी	1
मॉरिशस	2
मंगोलिया	2

1990-91

देश व अंतर्राष्ट्रीय निकायों के नाम	भागीदारों की संख्या
नामीबिया	3
नेपाल	2
नाईजीरिया	2
फिलीपाइंस	1
सनेगल	2
श्रीलंका	7
सीयरालिओन	2
सीशल्स	1
तंजानिया	4
थाइलैंड	1
अमरीका	1
उगांडा	9
जांबिया	1
जिम्बाबवे	4
योग	**73**
अंतर्राष्ट्रीय निकाय	
यूनेस्को	1
यूनीसेफ	1
अंतर्राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद, कनाडा	1
अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान	1
विश्व बैंक	11
योग	**15**
कुल योग	**88**

डिप्लोमा कार्यक्रम

इस वर्ष दो डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किए गए थे :

शैक्षिक योजना और प्रशासन में डिप्लोमा

संस्थान ने जुलाई, 1983 में शैक्षिक योजना और प्रशासन विषय में डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया था। इस वर्ष संस्थान में दसवें डिप्लोमा पाठ्यक्रम के दूसरे और तीसरे चरण पूरे हुए। नवंबर, 1990 में ग्यारहवां डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू हुआ। इसका तीन महीने का पहला चरण जनवरी, 1991 में पूरा हुआ और दूसरा चरण अप्रैल 1991 तक चलेगा। दसवें और ग्यारहवें डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 18 राज्यों और संघीय राज्यों तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण

परिषदों तथा जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थानों के जिला शिक्षा अधिकारियों और कार्मिकों सहित 38 प्रशिक्षार्थी शामिल हुए। तालिका 6 में डिप्लोमा पाठ्यक्रम संबंधी राज्यवार भागीदारी प्रदर्शित है।

तालिका 6

डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में राज्यवार भागीदारी

राज्य/संघीय राज्य	दसवां डिप्लोमा	ग्यारहवां डिप्लोमा	योग
आंध्र प्रदेश	4	-	4
असम	3	1	4
हिमाचल प्रदेश	1	-	1
जम्मू और कश्मीर	-	2	2
कर्नाटक	2	2	4
केरल	2	-	2
मध्यप्रदेश	1	-	1
महाराष्ट्र	1	-	1
मणिपुर	2	-	2
मेघालय	1	1	2
नागालैंड	1	-	1
पंजाब	1	-	1
राजस्थान	1	1	2
तमिलनाडु	1	-	1
त्रिपुरा	-	1	1
उत्तरप्रदेश	1	2	3
पश्चिम बंगाल	1	1	2
दिल्ली	3	1	4
योग	**26**	**12**	**38**

तीन चरणों में आयोजित डिप्लोमा कार्यक्रम 25 श्रेयांक का होता है। इसका पहला चरण तीन महीने का होता है जिसका श्रेयांक 15 होता है। इस चरण में पाठ्यचर्चा का गहन अध्ययन किया जाता है। तीन महीने के दूसरे चरण में पर्यवेक्षणाधीन परियोजना कार्य शामिल है। तीसरा चरण 4-6 दिन का होता है। इसमें प्रशिक्षणार्थी के परियोजना कार्य का मूल्यांकन किया जाता है और एक साथ बैठकर विचारों का आदान-प्रदान होता है। भागीदारों से प्राप्त पुनर्निवेशन और बदलते परिवेश में उनके कार्यकलापों के मूल्यांकन के आधार पर डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण प्रणाली की पुनर्रचना की गई। विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रबंध कौशल तथा परियोजना और कार्ययोजना बनाने

1990-91

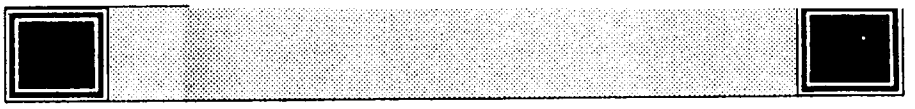

के लिए अपेक्षित कौशलों में वृद्धि पर विशेष बल दिया गया। डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में सांस्थानिक योजना, विद्यालय मानचित्रण, विद्यालय संघटन, मात्रात्मक तकनीक, संकट की चुनौतियों का सामना करने के लिए संकल्प, सामुदायिक भागीदारी इत्यादि पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। डिप्लोमा की प्रशिक्षण प्रणाली विभिन्न विषयों पर व्याख्यान-चर्चा, पैनल परिचर्चा, केस अध्ययन, सामूहिक कार्य, सामूहिक अभ्यास, भूमिका प्रदर्शन, इन-बास्केट विधि और सामूहिक परिचर्चा पर आधारित थी। प्रायोगिक अभ्यास, पुस्तकालय आधारित कार्य और कुछ महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थानों के दौरे पर भी पर्याप्त समय दिया गया।

भागीदारों को विद्यालय शिक्षा और समुदाय के क्षेत्र में किए गए प्रायोगिक नवाचारों से अवगत कराने के लिए राजस्थान के उदयपुर जिले का एक सप्ताह का क्षेत्रीय दौरा आयोजित किया गया।

शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा

संस्थान में पहला अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम जनवरी 1985 में शुरू किया गया। छठवां अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम जनवरी 1990 में शुरू हुआ और इस वर्ष के अंदर ही पूरा हो गया। सातवां अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा जनवरी 1991 में शुरू हुआ। इस कार्यक्रम की बढ़ती लोकप्रियता के कारण प्रवेश के लिए अधिक संख्या में नामित पत्र प्राप्त हुए। छठवें डिप्लोमा में 9 देशों से 17 भागीदार, और सातवें डिप्लोमा में 14 देशों के 26 भागीदार शामिल हुए। तालिका 7 में देशवार भागीदारी का विवरण प्रदर्शित है।

तालिका 7

अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रमों में देशवार भागीदारी

देश का नाम/अंतर्राष्ट्रीय संगठन	भागीदारों की संख्या		योग
	छठवां अं. डि.	सातवां अं. डि.	
अफगानिस्तान	-	1	1
क्यूबा	-	1	1
गांबिया	-	1	1
ईरान	6	-	6
केन्या	-	1	1
लाओस	2	-	2
मलएशिया	1	1	2
मालावी	-	1	1
मॉरिशस	-	2	2
मंगोलिया	1	-	1
नामीबिया	-	3	3

देश का नाम/अंतर्राष्ट्रीय संगठन	भागीदारों की संख्या		योग
	छठवां अं. डि.	सातवां अं. डि.	
नेपाल	1	-	1
नाईजीरिया	-	2	2
सेनेगल	-	2	2
सीयरा लिओन	1	-	1
सीशल्स	1	-	1
श्रीलंका	-	1	1
तंजानिया	2	-	2
उगांडा	2	5	7
जांबिया	-	1	1
जिंबाबवे	-	4	4
योग	**17**	**26**	**43**

अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा दो चरणों में पूरा होता है। प्रत्येक चरण तीन महीने का होता है। पहले चरण में पाठ्यचर्या पर गहन अध्ययन कार्य किया जाता है। दूसरे चरण में प्रशिक्षणार्थी अपने देश में परियोजना कार्य करते हैं। पाठ्यक्रम दो भागों में विभाजित है। पहला भाग बेसिक और केंद्रिक पाठ्यक्रम का होता है। दूसरा भाग विशेष पाठ्यक्रम का होता हैं। केंद्रिक पाठ्यक्रम में शैक्षिक योजना और प्रशासन की मूल अवधारणाओं और तकनीकों की जानकारी दी जाती है जबकि दूसरा भाग प्रशिक्षणार्थी द्वारा चुने गए विशेष क्षेत्र में व्यापक कार्य के विशेष कौशल पर आधारित होता है। इस पाठ्यक्रम में निम्न विषय शामिल हैं– तीसरी दुनिया में शिक्षा की योजना और प्रबंध, शैक्षिक प्रौद्योगिकी और दूरवर्ती शिक्षा, संगणकों के उपयोग के लिए प्रशिक्षण आदि। नीपा में क्षेत्र संलग्न कार्यक्रम इस पाठ्यक्रम का पूरक है।

सातवें डिप्लोमा कार्यक्रम के दौरान संस्थान ने निम्नांकित संस्थानों के दौरे आयोजित किए : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय और नवोदय विद्यालय समिति के मुख्यालय तथा जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान। इसके अलावा भागीदारों ने महाराष्ट्र, गोवा और राजस्थान के उच्च स्तरीय शैक्षिक संस्थानों और विद्यालयों के दौरे भी किए। इन राज्यों में दौरे वाले संस्थान और विद्यालय निम्न थे – बंबई विश्वविद्यालय और उसके कुछ कालेज, एस.एन.डी.टी. विश्वविद्यालय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, पुणे, महाराष्ट्र पाठ्य पुस्तक निर्माण और अनुसंधान ब्यूरो, पुणे, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा, केंद्रीय विद्यालय, गोवा और जयपुर के कुछ संस्थान और सांस्कृतिक केंद्र।

वित्तीय सहायता देने वाले विभिन्न अभिकरणों की ओर से औपचारिक और अनौपचारिक रूप से संस्थान को सकारात्मक पुनर्निवेशन प्राप्त हो रहे हैं।

प्रशिक्षण और अभिविन्यास कार्यक्रम

इस वर्ष विशिष्ट विषयों और काडर विशेष 19 प्रशिक्षण/अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें 378 भागीदार शामिल हुए। इसके अलावा विभिन्न विषयों पर 31 कार्यशिविर/संगोष्ठी/सम्मेलन/गोष्ठी आयोजित किए गए जिनमें विभिन्न क्षेत्रों से कुल 601 भागीदार शामिल हुए।

1990-91

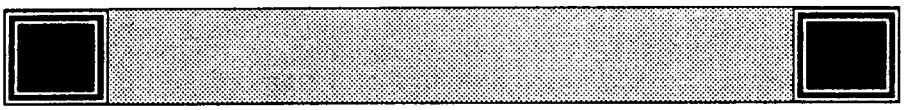

विशिष्ट विषय के कार्यक्रम

संस्थान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दी गई वरीयताएं वाले जिन विशिष्ट विषयों पर प्रशिक्षण/अभिविन्यास कार्यक्रम/ संगोष्ठी/कार्यशिविर आयोजित किए गए थे, वे विषय इस प्रकार हैं – व्यष्टि स्तरीय योजना, विद्यालय मानचित्रण, सांस्थानिक योजना, अनौपचारिक व प्रौढ़ शिक्षा, जि. शै.प्र. सं. की योजना और प्रबंध तथा दूरवर्ती शिक्षा।

विद्यालय शिक्षा

विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अभिविन्यास कार्यक्रम और कार्यशिविर आयोजित किए गए। ऐसे कुल 17 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें विद्यालय स्तर के 416 कार्मिकों ने भाग लिया इनमें रा.शै.अ.प्र.प., रा.शि.सं., जि.शै.प्र.सं. के विद्यालय स्तर के कार्मिक व विद्यालय स्तर के वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासक के तथा केंद्रीय विद्यालयों के प्राचार्य थे। इन 17 कार्यक्रमों में से 3 तीन कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली, भारत पेट्रो केमिकल लिमिटेड और जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर के सहयोग से आयोजित किए गए।

इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण और व्यष्टि स्तरीय योजना पर 4 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 83 भागीदार शामिल हुए। नागालैंड के राज्य शिक्षा विभाग के अनुरोध पर कोहिमा में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय मानचित्रण पर दो कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें 15 भागीदार शामिल हुए। इन दो कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम अंडमान और निकोबार प्रशासन के अनुरोध पर पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया।

अनौपचारिक शिक्षा

अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में 3 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 90 भागीदार शामिल हुए। आंध्रप्रदेश सरकार के अनुरोध पर हैदराबाद में अनौपचारिक शिक्षा पर क्षेत्र आधारित एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के प्रौढ़ शिक्षा केंद्र और प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के सहयोग से योजना और प्रबंध पर छः सप्ताह का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में एक सप्ताह के लिए साक्षरता मिशन के जिलों – देहरादून (उत्तर प्रदेश), मिदनापुर और बर्दवान (पं. बंगाल) के दौरे भी किए गए।

उच्च शिक्षा

विश्वविद्यालय/कालेज स्तर के कार्मिकों के लिए चार कार्यक्रम आयोजित किए गए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुरोध पर कालेज के प्राचार्यों, कालेज विकास परिषदों और अकादमिक स्टाफ कालेज के निदेशकों के लिए तीन कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इसके अलावा वित्तीय प्रबंध पर दो कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 19 भागीदार शामिल हुए।

संगणक अनुप्रयोग/मात्रात्मक तकनीक

संगणक अनुप्रयोग पर तीन और मात्रात्मक तकनीक पर एक कार्यक्रम आयोजित किए गए। संगणक अनुप्रयोग के कार्यक्रमों में कालेजों के प्राचार्यों और राज्य स्तर के संगणक कार्मिकों ने भाग लिया। जबकि मात्रात्मक तकनीक के कार्यक्रम में सांख्यिकी कार्मिक शामिल हुए। इन कार्यक्रमों में विभिन्न स्तरों के 44 कार्मिकों ने भाग लिया।

लंबी अवधि की योजना और रोजगारपरक योजना

लंबी अवधि की योजना के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्रीय योजना, रोजगारपरक योजना और व्यावसायिक शिक्षा योजना के क्षेत्र में 5 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 90 भागीदार शामिल हुए।

1990-91

सुविधावंचित वर्गों/विकलांगों/महिलाओं की शिक्षा के लिए योजना और प्रबंध

सुविधावंचित वर्गों, विकलांग बच्चों और महिला समस्याओं पर महिला प्रशासकों के लिए विशेष रूप से एक-एक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें कुल 31 भागीदार शामिल हुए।

पर्यावरण शिक्षा

शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के लिए पर्यावरण शिक्षा पर यूनेस्को-यू.एन.ई.पी. प्रायोजित एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संगोष्ठी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में 9 देशों—भारत, ईरान, जनलोकतांत्रिक गणराज्य लाओस, मंगोलिया, नेपाल, सीयरालियोन, तंजानिया और उगांडा से 17 भागीदार शामिल हुए।

दूरवर्ती शिक्षा

"दूरवर्ती शिक्षा—सबके लिए शिक्षा" की भावी भूमिका पर संस्थान में एक कार्यशिविर का आयोजन किया गया जिसमें 10 दूरवर्ती शिक्षा संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल हुए।

पुस्तकालय और सूचना प्रबंध

अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय और सूचना परामर्शकारी केंद्र के सहयोग से सूचीकरण, सारांशीकरण और सूचना पुनः प्राप्ति की भूमिका पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न राज्यों और संघीय राज्यों के 28 पुस्तकालयाध्यक्ष शामिल हुए।

अन्य कार्यक्रम

अखिल भारतीय शैक्षिक प्रशासन सर्वेक्षण परियोजना से संबंधित राज्यों की रिपोर्टों के आदर्श रूप और राज्य तथा जिला स्तर के संगठनों के गठन इत्यादि पर विचार-विमर्श के लिए विभिन्न राज्यों के परियोजना निदेशकों के लिए दो कार्यशिविरों का आयोजन किया गया। इन कार्यशिविरों में 21 परियोजना अधिकारियों ने भाग लिया।

इसके अलावा भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीलंका के 5 शिक्षा अधिकारी संस्थान में पधारे थे।

इस वर्ष के प्रशिक्षण/अभिविन्यास/संगोष्ठी/कार्यशिविर/सम्मेलन/डिप्लोमा पाठ्यक्रम/भ्रमण और अन्य कार्यक्रमों की सूची अनुबंध-I में दी गई है।

प्रशिक्षण सामग्री/माड्यूल

शैक्षिक योजना और प्रबंध पर अनेक पत्रों और सांख्यिकी आंकड़ों के अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपयोग और व्यापक प्रसार के लिए संस्थान में 23 माड्यूल तैयार किए गए। इस वर्ष तैयार किए प्रशिक्षण सामग्रियों की सूची अनुबंध-II में दी गई है।

1990-91

अध्याय 3

अनुसंधान

शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में विभिन्न पक्षों पर अध्ययन करना, अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता देना तथा अनुसंधान कार्यों में दूसरे संगठनों, राज्यों और अन्य देशों के साथ सहयोग करना नीपा का प्रमुख उद्देश्य है। इनमें विभिन्न राज्यों और विश्व के अन्य देशों की शैक्षिक योजना और प्रशासन की तकनीकों तथा विधियों का तुलनात्मक अध्ययन भी शामिल हैं।

व्यष्टि और समष्टि स्तरों पर शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में नीतिगत मसलों और क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान से संबंधित अभिज्ञान, प्रासंगिक आंकड़े और पुनर्निवेशन के लिए व्यावहारिक अध्ययन की ओर संस्थान की अनुसंधानात्मक गतिविधियां उन्मुख होती हैं। अनुसंधान अध्ययनों के निष्कर्षों से प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सदैव अद्यतन किया जाता है।

वर्ष 1991 में अनुसंधान पर कुल रु. 14.97 लाख व्यय हुआ। इसमें नीपा सहायता योजना के तहत रु. 1.01 लाख की अनुदान राशि प्रदान की गई और प्रायोजित अध्ययनों के लिए रु. 63.57 लाख की राशि प्राप्त हुई।

इस वर्ष 10 अनुसंधान अध्ययन पूरे हुए। 17 अध्ययनों का कार्य चल रहा है। 5 नए अध्ययनों को आरंभ करने की स्वीकृति दी गई। इनमें से 3 अध्ययन प्रायोजित हैं और 2 अध्ययन नीपा सहायता योजना के अंतर्गत हैं।

पूरे किए गए अध्ययन

1. वर्ष 2000 में शिक्षा–लंबी अवधि का संप्रेक्ष्य

इस परियोजना का पुनर्गठित चरण जून, 1989 में शुरू हुआ। परियोजना दल में निम्न शामिल थे– प्रो. श्रीप्रकाश, परियोजना निदेशक, सुश्री टी. बुड़ागोहाई, सुश्री सुमित्रा चौधरी और सुश्री आभा गुप्ता, परियोजना सहायक। परियोजना के लिए 4.08 लाख रुपए की राशि स्वीकृत थी।

इस पुनर्गठित अध्ययन के मुख्य बिंदु थे– (अ) शैक्षिक व्यय का विश्लेषण, (ब) विद्यालय में पूरे किए गए अध्ययन का औसत वर्ष, (स) शिक्षा के विकास के लिए लंबी अवधि का संप्रेक्ष्य और (द) मध्यम अवधि की परियोजनाएं। अध्ययन के भाग के रूप में निम्नांकित 13 पत्र/प्रलेख निकाले गए :

1. भारत में शैक्षिक व्यय– प्रवृतिमूलक विश्लेषण
2. भारत में शैक्षिक व्यय के निर्धारक : परीक्षित वैकल्पिक संकल्पना
3. भारत में शिक्षा की इकाई लागत : परीक्षित वैकल्पिक संकल्पना
4. प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण– सामान्य संतुलन का नीतिगत प्रारूप
5. शिक्षा की निजी मांग : संभावित माध्यम
6. अंतर उद्योग प्रारूप : शिक्षा का आर्थिक प्रभाव
7. भारत में शैक्षिक संस्थानों का प्रतिमान : क्षेत्रीय और वास्तविक प्रतिमानों के बीच परासरण का अध्ययन
8. शिक्षा और अर्थव्यवस्था की संतुलित महतम संवृद्धि का प्रारूप

9. जनसांख्यिकीय दबाव और प्रवजन : मेघालय का केस अध्ययन
10. अंग के रूप में संवृद्धि के अपघटन का माडल
11. आर्थिक संवृद्धि और साक्षरता : अंतर्राष्ट्रीय व्यय
12. भारत में साक्षरता विकास के निर्धारक : संभावित ढांचे में देशकालिक आयाम
13. संक्रमण, विद्यालय त्याग और विद्यालयी औसत वर्ष

2. भारत में साक्षरता–देशकालिक विश्लेषण (1901-1981)

परियोजना दल में निम्न सदस्य शामिल थे– डॉ. एस. सी. नुना, परियोजना निदेशक, श्री जमालुदीन फारूकी और श्री ओ. डी. त्यागी, परियोजना मानचित्रकार और श्री राजपत राम तथा सुश्री हरिजिंदर कौर, परियोजना सहायक।

परियोजना के लिए रु. 2,23,900/- की राशि स्वीकृत थी।

विकास प्रक्रिया में साक्षरता के महत्व को देखते हुए निरक्षरता दूर करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। इस शताब्दी के आरंभ में इस क्षेत्र में साक्षरता की स्थिति निराशाजनक थी। इसे बहुसंख्यक निरक्षर आबादी के सामने संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। साक्षरता प्रसार की रणनीति बनाने के उद्देश्य से साक्षरता प्रवृतियों और कारकों पर विचार विमर्श के लिए जिला स्तर के आंकड़ों के आधार पर सन् 1901 से भारत में साक्षरता की स्थिति का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया।

इस अध्ययन के तीन भाग हैं : सन् 1901 से साक्षरता प्रतिमानों का विश्लेषण और जिला स्तर पर इसके विस्तार का स्वरूप, जिला स्तर पर द्वितीयक आंकड़ों के उपयोग पर आधारित भारत में साक्षरता के निर्धारक और आधारभूत स्तर पर साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक।

इस अध्ययन में सन् 1901 से विभिन्न दशकीय जनगणना के आधार पर जिला स्तर की साक्षरता संबंधी आंकड़े विकसित किए गए। बारमेर गंगानगर (राजस्थान), रामपुर (उत्तरप्रदेश) बस्तर, (मध्यप्रदेश)ा, औरंगाबाद (महाराष्ट्र), मालापुरम (केरल), कन्याकुमारी (तमिलनाडु) पश्चिम सिक्किम और बारपेटा (असम), जिलों से प्रारंभिक आंकड़े एकत्र किए गए। इस अध्ययन से संकेत मिलता है कि साक्षरता प्रगति के संदर्भ में अधिकांश जिलों में साक्षरता की निराशाजनक तस्वीरें सामने आती हैं। वास्तव में सन् 1981 में 163 जिलों में महिला साक्षरता 11.30 प्रतिशत से भी कम है। यह एक विचारणीय प्रश्न है। यद्यपि यह तथ्य सामने आया है कि साक्षरता की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र भी साक्षरता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। जिलों का एक समूह में साक्षरता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। यह आश्चर्य की बात है कि इन सभी जिलों में तृतीयक क्षेत्रीय विकास हुआ है। इससे साक्षरता व्यापक विकास के एक कारक के रूप में उभर कर सामने आई है। शायद इसका कारण यह भी हो सकता है कि विकास साक्षरता के लिए प्रेरक सिद्ध हुआ है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि परस्पर निर्भरता प्रणाली में विकास के संकेतकों के साथ साक्षरता का धनात्मक संबंध पाया गया है। प्राथमिक आंकड़ों के विश्लेषण से भी ये ही निष्कर्ष सामने आए हैं। यह अध्ययन प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों के क्रियाकलापों पर भी प्रकाश डालता है। यह आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया है कि अधिकांश गांवों को इन केंद्रों के कार्यकलापों की जानकारी नहीं है।

इस अध्ययन के निष्कर्षों से यही संकेत मिलता है कि साक्षरता प्रगति के लिए विकासमूलक ढांचे के तहत रणनीतियां विकसित करने की जरूरत है।

3. हरियाणा के गुड़गांवा जिले के पुनहाना प्रखंड में शैक्षिक योजना और प्रशासन की रणनीतियों के कार्यान्वयन के अध्ययन के लिए क्रियात्मक अनुसंधान (तीसरा चरण)। परियोजना दल के सदस्य थे–प्रो. सत्यभूषण, परियोजना

1990-91

निदेशक, डॉ. आर. गोविंद, परियोजना प्रभारी और डॉ. प्रमिला मेनन, परियोजना संयोजक।

इस परियोजना के लिए रु. 3,46,700/- की राशि स्वीकृत थी।

अनुदेशकों/स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। तीसरे चरण के लिए चुने गए तीन गांवों छडोदा, पाटूका और सराय के नवसाक्षरों को प्रमाणपत्र दिए गए। प्रमाण पत्र वितरण समारोह के अवसर पर प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, निरूटैडस, दो स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित प्रखंड शिक्षा अधिकारी और पड़ोस के गांवों के सरपंच तथा जिला स्तर के अधिकारीगण मौजूद थे। अन्य गांवों के लिए यह एक प्रेरणादायी कार्यक्रम साबित हुआ।

प्रौढ़ शिक्षा के मानदंडों के प्रतिमानों के आधार पर प्रौढ़ नवसाक्षरों का मूल्यांकन किया गया। साक्षरता कार्यक्रम को सक्रिय बनाने के लिए कई क्षेत्रीय दौरे आयोजित किए गए।

दो स्वयंसेवी संगठनों— मेवात सोसायटी और शैक्षिक विकास सोसायटी, बिसरू तथा मेवात शैक्षिक सोसायटी छड़ौदा, नूह ने अपने क्षेत्र के 5 गांवों में पूर्णतः निरक्षरता उन्मूलन का दायित्व लिया। नीपा ने प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया से प्रशिक्षण और अधिगम संबंधी सामग्रियां उपलब्ध कराई।

4. महाराष्ट्र में शिक्षा और विकास

परियोजना दल के निम्न सदस्य थे— डॉ. एस. सी. नुना, परियोजना निदेशक, श्री जमालुदीन फारुकी परियोजना मानचित्रकार, और सुश्री मधुमित बंदोपाध्याय और श्री मु. युनूस परियोजना सहायक।

परियोजना के लिए रु. 36,520/- की रकम स्वीकृत थी।

सामान्यतया यह माना जाता है कि विकास गति पर शिक्षा का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। मगर इसे व्यावहारिक रूप से जांचने और परखने की जरूरत है। यह अध्ययन इस दिशा में एक प्रयास था। महाराष्ट्र के जिला स्तर के आंकड़ों के माध्यम से शिक्षा और विकास के अन्य आयामों के बीच संबंध की तलाश करने का प्रयास किया गया। राज्य में विकास प्रक्रिया के संदर्भ में शैक्षिक विकास की व्याख्या करने के लिए महाराष्ट्र के निवेदन पर यह अध्ययन शुरू किया गया। यह अध्ययन जिला स्तर के आंकड़ों पर आधारित है। ये आंकड़े शिक्षा, जनसांख्यिकी, वैवाहिक स्तर, प्रजननता, स्वास्थ्य, आर्थिक गतिविधियां, पीने के साफ पानी की उपलब्धता और सुविधाओं से संबंधित थे। आंकड़ा विश्लेषण के लिए मानचित्रण का प्रयोग किया गया। अध्ययन से संकेत मिलता है कि राज्य की विकास प्रक्रिया में क्षेत्रीय विषमताएं हैं। यह देखा गया है कि जिन क्षेत्रों में परंपरागत विकास होता रहा है उनमें विकास की प्रक्रिया अग्रसर है। इस विकास प्रक्रिया में शिक्षा कोई अपवाद के रूप में सामने नहीं आई है। विकास की अधोगामी प्रक्रिया एक तरफ तटीय क्षेत्रों में जारी है तो दूसरी तरफ नगरीय क्षेत्रों में भी विकास हो रहा है। यह एक रोचक एवं महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है कि विकास के अन्य आयामों और शिक्षा के बीच एक सकारात्मक संबंध है। उदाहरणार्थ, अधिक महिला साक्षरता वाले इलाकों में शिशु मृत्युदर और जन्मदर कम है तथा विवाह की औसत आयु अधिक है। अतः ये निष्कर्ष शैक्षिक विकास के लिए समन्वित विकास प्रक्रिया की जरूरत की ओर संकेत करते हैं।

यह अध्ययन चयनित संकेतकों के लिए जनपदों की क्रमबद्ध श्रेणी सहित जिला स्तर पर विभिन्न संकेतकों से संबंधित आंकड़े भी प्रस्तुत करता है।

1990-91

5. महिला कालेजों के प्रशासकों के प्रशिक्षण की जरूरतों की पहचान (एस. एन. डी. टी. विश्वविद्यालय के सहयोग से)

परियोजना दल में निम्न सदस्य शामिल थे— डॉ. (श्रीमती) जया इंदिरेसन, परियोजना निदेशक, डॉ. जी. डी. शर्मा, डॉ. (श्रीमती) के. सुधाराव (सहयोगी—नीपा) और डॉ. लीना डीसूजा और डॉ. उषा टक्कर (एस. एन. डी. टी. विश्वविद्यालय)

इस परियोजना के लिए रु. 10,000/-की राशि स्वीकृत थी।

देशभर में लगभग 700 महिला कालेज हैं। इन कालेजों के कार्यकलापों को सुगम और प्रभावी बनाने के लिए कालेजों की योजना और प्रबंध से संबद्ध वरिष्ठ प्रशासकों के प्रशिक्षण के लिए अभिविन्यास कार्यक्रमों का प्रस्ताव रखा गया है।

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सार्थक बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण के जरूरी पक्षों की पहचान करने के लिए यह अध्ययन हाथ में लिया गया।

निम्नांकित पक्षों से संबंधित आंकड़े एकत्र करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की गई :

1. सभी कालेजों के प्रशासन से संबंधित योजना और प्रबंध के सामान्य मुद्दे,
2. महिला छात्रों की शिक्षा से संबंधित विशिष्ट मुद्दे,
3. महिला प्रशासकों के संदर्भ में कुछ नाजुक विशेष मुद्दे,
4. महिला प्रशासकों का वैयक्तिक आंकड़ा।

6. उच्च शिक्षा में वर्तमान सुविधाओं और संसाधनों के और अधिक प्रभावी उपयोग का अध्ययन

परियोजना दल में शामिल सदस्य थे— डॉ. जी. डी. शर्मा, परियोजना निदेशक और डॉ. एफ. कमार, परियोजना अध्येता

परियोजना के लिए रु. 56,000/- की रकम स्वीकृत थी।

यह अध्ययन विश्वविद्यालयों और कालेजों में संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर प्रकाश डालता है और वर्तमान सुविधाओं/संसाधनों के और अधिक प्रभावी उपयोग के लिए नए माध्यमों व तरीकों का सुझाव देता है। इस अध्ययन में संसाधनों के प्रति व्यापक दृष्टिकोण रखा गया है और वित्तीय, भौतिक, मानव तथा समय सभी पक्षों को समेटा गया है।

रणनीतिक अवयवों की संपूरकता की कमी, समुचित योजना की कमी, संचारेक्षण और समन्वयन प्रणाली और बाधाओं का अध्ययन इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है।

संसाधनों के प्रभावी उपयोग के कारकों का परीक्षण करने के लिए विभिन्न संकेतकों—उच्च शिक्षा के संस्थानों के आकार और आर्थिक क्षमता, कार्यदिवसों की सूची, मानव संसाधन उपयोग की सूची, प्रशासन का प्रभाव, पुस्तकालय और प्रयोगशाला स्टाफ, भौतिक और आधारभूत सुविधाओं के उपयोग की सूची, निर्धारित क्षमता और वित्तीय प्रशासन की क्षमता के आधार पर समस्या का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया।

7. शैक्षिक योजना और प्रशासन में डिप्लोमा – संस्थान का मूल्यांकनात्मक अध्ययन

डॉ. वाई. पी. अग्रवाल, अध्येता, विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा एकक ने यह अध्ययन संचालित किया।

यह अध्ययन समीक्षा समिति की संस्तुतियों पर की जाने वाली कार्रवाई के एक भाग के रूप में शुरू किया गया। समिति का विचार था कि बदलते शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में जिला शिक्षा अधिकारियों की भूमिकाएं भी बदल रही हैं। अतः प्रशिक्षण कार्यक्रम में बदलती भूमिकाओं को मद्दे नजर रखना जरूरी है।

1990-91

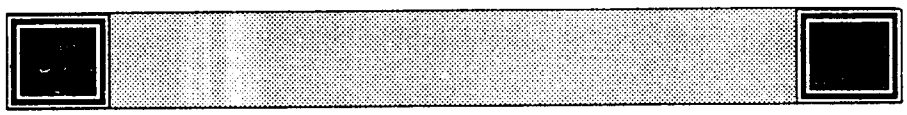

इस अध्ययन में पाठ्यक्रम के विभिन्न पक्षों, उसके प्रभाव और पाठ्यक्रम की प्रभाविता पर भागीदारों के दृष्टिकोणों की समीक्षा की गई।

प्रथम नौ पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित लगभग 180 अधिकारियों को अध्ययन का लक्ष्य बनाया गया। सभी अधिकारियों को एक प्रश्नावली भेजी गई जिनमें से 68 अधिकारियों के जवाब आए।

अध्ययन के मुख्य लक्ष्य निम्न थे :

1. प्रशिक्षणार्थियों के कार्यकलापों में पाठ्यक्रमों के भागों की प्रासंगिकता का परीक्षण करना,
2. प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रशिक्षण के पहले या बाद में शामिल किन्हीं दूसरे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विषय वस्तु की पुनरावृति वाले क्षेत्रों की पहचान करना,
3. एक तरफ आयु, अनुभव प्रशिक्षण तथा दूसरे तरफ कार्यगतिशीलता के आधार पर प्रशिक्षणार्थियों का जीवनवृत्त तैयार करना,
4. प्रशिक्षण के बाद विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षणार्थियों का मूल्यांकन करना ताकि यह पता लग सके कि पाठ्यक्रम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में कहां तक सफल रहे हैं।

सामान्यतः सभी पाठ्यक्रम अपने लक्ष्य पूरा करने में सफल थे। ज्ञान और कौशलों के आदान-प्रदान वाले क्षेत्रों में अन्य के मुकाबले सर्वाधिक सफलता मिली है। उत्तरदाताओं ने पाठ्यक्रम की प्रणाली से भी संतुष्टी जताई थी। जिला शिक्षा अधिकारियों की बदलती भूमिकाओं के आधार पर कार्यक्रम में निम्नांकित क्षेत्रों को प्रकाश में लाने की जरूरत है :

1. शिक्षा में संगणक के अनुप्रयोग की अधिकतम मांग है,
2. व्यावसायिक शिक्षा की योजना और प्रबंध,
3. व्यष्टि स्तरीय योजना, विकेंद्रीकृत योजना, विद्यालय मानचित्रण, विद्यालय संघटन, और शिक्षा में जनता की भागीदारी,
4. जिला स्तर के शैक्षिक कार्यों के दैनंदिन कार्यकलापों पर राजनीतिक और अन्य दूसरे प्रकार के दबावों का प्रबंध,
5. मुकदमेबाजी, कोर्ट के मामले संबंधी कार्य और शैक्षिक संस्थानों से संबंधित कानून पर एक पाठ्यक्रम,
6. प्रशासनिक नियमों, अधिनियमों, और लेखा व्यवहारों पर एक पाठ्यक्रम,
7. तकनीकी शिक्षा और प्रबंध शिक्षा,
8. केंद्रीय रूप से प्रायोजित विभिन्न योजनाओं जैसे प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, आपरेशन ब्लैक बोर्ड, शिशु देखभाल शिक्षा और जनसंख्या शिक्षा की योजना और प्रबंध।

8. जिला स्तर के शैक्षिक प्रशासकों का जीवनवृत्त– राष्ट्रीय अध्ययन

संस्थान की डॉ. (श्रीमती) सुदेश मुखोपाध्याय ने इस अध्ययन का संचालन किया।

शैक्षिक योजना और प्रशासन में नीपा के डिप्लोमा कार्यक्रम की समीक्षा के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों पर की जाने वाली कार्रवाई के एक भाग के रूप में यह अध्ययन शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम को शुरू करने

1990-91

से पहले नीपा ने सन् 1972 में इस विषय पर अध्ययन किया था। उसके बाद 18 वर्ष के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी, नामक अधिकारी के कार्यक्षेत्र और भूमिकाओं के क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ है। इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्न थे :

1. अपनी भूमिकाएं और कार्यकलापों के प्रति जिला स्तर के प्रशासकों के दृष्टिकोणों का अध्ययन करना :
   (अ) शिक्षा के विभिन्न रूपों के क्षेत्रों में,
   (ब) कार्यकलापों के विभिन्न आयामों के साथ।
2. विभिन्न कार्यकलापों के महत्व और दिए गए समय का अध्ययन करना,
3. जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपनी भूमिकाओं और कार्यकलापों के मार्ग में आने वाली समस्याओं की पहचान करना,
4. भर्ती प्रणाली पर उनके दृष्टिकोण का विश्लेषण करना,
5. प्रशिक्षण की जरूरतों के संदर्भ में उनके दृष्टिकोणों का विश्लेषण करना।

यह अध्ययन अखिल भारतीय सर्वेक्षण के आधार पर किया गया। आंकड़ा संग्रह के लिए प्रश्नावली भेजी गई। 65 के जवाब मिले जिनमें से 50 जवाबों का ही विश्लेषण किया गया। इनमें 16 राज्य/संघीय राज्य के जवाब शामिल थे। अध्ययन से पता चला कि वरिष्ठों और कनिष्ठों के दृष्टिकोणों के बीच कोई खास अंतर नहीं है। अर्थात जिला शिक्षा अधिकारी के सामांतर भूमिका निभाने के लिए उपयोग में लाई गई विधियों और सामने आने वाली कठिनाइयों के प्रति कमोबेश सभी के दृष्टिकोण समान थे। वर्ष 1972 के अध्ययन में किए गए अनेक परीक्षणों को भी इस अध्ययन में समर्थन मिला। फिर भी भावी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए निम्नांकित नए क्षेत्र प्रकाश में आये थे :

(अ) दबाव समूह के साथ संपर्क,

(ब) अधिक छात्र वाले विद्यालयों में आवश्यक और उपलब्ध सुविधाओं का प्रबंध,

(स) न्यायालय संबंधित कार्यकलापों का प्रबंध,

(द) समुदाय की भागीदारी,

(य) बढ़े हुए कार्यभार का प्रबंध,

(र) अन्य अभिकरणों की प्रबंध में भागीदारी,

(ल) शिक्षकों की भर्ती व नियुक्ति का प्रबंध,

(ब) वित्तीय संसाधनों का उपयोग।

9. दूरवर्ती शिक्षा संस्थानों की कक्षावार लागत का अध्ययन (नीपा सहायता योजना के अंतर्गत)

फरवरी 1989 में इस अध्ययन के लिए रु. 59.600/- की राशि स्वीकृत की गई। प्रो. रुद्र दत्त, प्राचार्य, विद्यालय पत्राचार पाठ्यक्रम, दिल्ली विश्वविद्यालय ने यह अध्ययन किया।

कुल 33 दूरवर्ती शिक्षा संस्थानों में से 9 संस्थानों को अध्ययन के लिए चुना गया। यह चुनाव यादृच्छिक प्रतिदर्श वर्गीकरण के आधार पर किया गया। संस्थानों के चयन में मुख्यतः दाखिले पर विशेष ध्यान दिया गया।

इस अध्ययन में निम्नलिखित बिंदुओं को प्रकाश में लाया गया है :

1. अनेक दूरवर्ती संस्थान अतिरिक्त राजस्व अर्जित

1990-91

करते हैं और उसका उपयोग या तो आधारभूत ढांचे के निर्माण में करते हैं या विश्वविद्यालय के सामान्य राजस्व में जमा कर देते हैं। यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निर्देश दिया है कि छात्रों के शिक्षा शुल्क से उगाही गई रकम का विश्वविद्यालय द्वारा सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग में खर्च नहीं किया जाना चाहिए। मगर इस पर कहीं भी अमल नहीं किया गया है।

2. यद्यपि यह बात सच है कि संस्थानों में अधिक संख्या में अकादमिक पद बढ़ाने पर भी दूरदर्शी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होता है। इसी के साथ यह भी सत्य है कि बहुत कम संख्या में अकादमिक पद होने पर भी हम दूरवर्ती शिक्षा की गुणवत्ता बनाए नहीं रख सकते हैं। अतः यह जरूरी है कि पाठ्यक्रम शुरू करते समय प्रत्येक विषय के लिए केंद्रिक संकाय की नियुक्ति पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए। चूंकि अध्ययन सामग्री के निर्माण में परिपक्व व्यक्ति की जरूरत होती है। सटीक व्याख्या और अकादमिक कुशाग्रता की परम आवश्यकता होती है। अतः निदेशालयों के संकायों में वरिष्ठ और अनुभवी अकादमिक कर्मियों को ही कार्यभार सौंपना अधिक उपयुक्त रहेगा।

3. दूरवर्ती शिक्षा में कई प्रकार के कार्यों के लिए समर्थनकारी स्टाफ की जरूरत होती है। इसका कार्य औपचारिक शिक्षा के सामान्य कार्यों से अलग किस्म का होता है। उदाहरण के लिए, अध्ययन सामग्री के निर्माण के लिए स्टाफ, पांडुलिपियों के संपादन के लिए संपादक, प्रूफ संशोधक, सज्जाकार इत्यादि की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार दृश्य-श्रव्य कैसेटों के निर्माण के लिए भी स्टाफ की जरूरत पड़ती है। अतः दूरवर्ती शिक्षा में जरूरत के हिसाब से गैर अकादमिक या समर्थनकारी स्टाफ के लिए एक सामान्य मानदंड या समर्थनकारी स्टाफ के लिए एक सामान्य मानदंड विकसित करने की जरूरत है।

4. अगर सिर्फ कम दाखिले वाले दूरवर्ती संस्थानों की लें, तो अनेक दूरवर्ती संस्थानों के साथ प्रति छात्र लागत के संबंध ऋणात्मक और उल्लेखनीय दिखाई पड़ते हैं। चूंकि अवस्नातक स्तर पर परास्नातक स्तर की अपेक्षा लागतें कम हैं। जिन संस्थानों में अवस्नातक स्तर पर अपेक्षाकृत दाखिला संख्या अधिक है, उनमें परास्नातक स्तर की ऊंची लागत की मदद मिलती है और इसके परिणाम-स्वरूप कुल लागत कम हो जाती है। अतः अवस्नातक और परास्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में विवेकपूर्ण तालमेल की जरूरत है ताकि लागत में संतुलन बनाया जा सके।

5. दूरवर्ती शिक्षा संस्थानों में दाखिला और प्रति छात्र लागत के बीच ऋणात्मक संबंध के विपरीत औपचारिक कालेजों में दाखिला और प्रति छात्र लागत के बीच धनात्मक सह-संबंध हैं। औपचारिक कालेजों में एक छात्र को उपलब्ध कराई जाने वाली शिक्षण सामग्री की लागत दूरवर्ती शिक्षा में 6.5 छात्रों को उपलब्ध कराई जाने वाली समान सामग्री की लागतों के बराबर है।

6. औपचारिक शिक्षा की अपेक्षा दूरवर्ती शिक्षा की राज्य से कम सहायता मिलती है। उदाहरण के रूप में, वर्ष 1987-88 में दिल्ली के कालेजों में एक छात्र के लिए राज्य ने रु. 4,744 दिए जबकि दूरवर्ती शिक्षा के एक छात्र के लिए राज्य की ओर से मात्र रु. 328 की मदद मिली।

1990-91

10. दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली के कार्यकलापों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संगठनात्मक और संकाय के ढांचे में औपचारिक विश्वविद्यालयी ढांचे के तहत परिवर्तन लाने के उद्देश्य से दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली के संगठनात्मक और अकादमिक ढांचे का अध्ययन (नीपा सहायता योजना के अंतर्गत)

इस अध्ययन के लिए अगस्त 1989 में 63,600 रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। इस अध्ययन को डॉ. किशोर वालिचा, दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय, बंबई, विश्वविद्यालय ने किया।

इस अध्ययन से संबंधित प्रारंभिक प्रश्न को निम्नांकित शैक्षिक कार्यक्रमों के मद्देनजर रखकर उत्तर ढूंढने की कोशिश की गई : (1) औपचारिक शिक्षा में छात्रों की अनेकता, (2) सामान्य अनौपचारिक शिक्षा, (3) विशिष्ट अनौपचारिक शिक्षा, (4) कार्य अनुभव और (5) शैक्षिक प्रौद्योगिकी

इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष निम्न थे :

1. **सामग्री :** दूरवर्ती शिक्षा बहुत अधिक मुद्रण माध्यम पर निर्भर होती है। अतः अध्ययन सामग्री में संप्रेषण क्षमता बहुत अधिक होनी चाहिए।

2. **प्रौद्योगिकी का प्रयोग :** अनेक देशों में दूरवर्ती शिक्षा अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचने में सफल रही है। इससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महती सफलता मिली है। इसका मुख्य कारण अनुशिक्षण माध्यम के रूप में नई इलेक्ट्रानिक प्रौद्योगिकी जैसे रेडियो, टी. वी. और कंप्यूटर आदि का प्रभावी उपयोग है। मगर हमारे यहां इनका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। संगणकों का उपयोग शिक्षा के बजाए अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में अधिक हो रहा है। अतः हमारे देश में निरक्षरता की स्थिति से निपटने में दृश्य-श्रव्य माध्यम काफी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

3. **शिक्षकों का अभिविन्यास :** आमने-सामने की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अपेक्षा दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली में शिक्षण कार्य के लिए अधिक कुशलता की जरूरत होती है। कारण कि यह शिक्षण कार्य अनुपस्थित और सुदूर अपने कार्यों में व्यस्त छात्रों के लिए करना होता है। अतः दूरवर्ती शिक्षा के शिक्षकों को समय-समय पर अभिविन्यास पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। प्राप्त तथ्यों से पता चलता है कि अनेक निदेशक इसके पक्ष में हैं।

चालू अध्ययन

1. कालेजों का विकास और प्रभावी कार्यकलाप : क्रियात्मक अनुसंधान अध्ययन (दूसरा चरण)

इस अध्ययन दल के सदस्य हैं— डॉ. जी. डी. शर्मा, परियोजना निदेशक, डॉ. एम. एम. रहमान, परियोजना सह अध्येता और डॉ. (श्रीमती) कौसर विजारत/श्री जेम्स जो, परियोजना सहायक

इस अध्ययन के लिए रु. 5,78,410/- की राशि स्वीकृत की गई है।

यह परियोजना कालेजों के कार्यकलापों के अध्ययन के लिए शुरू की गई। अध्ययन के लिए कुछ कालेजों का चयन किया गया। अध्ययन के मुख्य पक्ष थे—अकादमिक और प्रशासन संबंधी सभी पक्ष, समुदाय विकास के लिए संसाधन केंद्र के रूप में कालेजों से समुदाय का संबंध। सामान्य योजना के निर्माण के अभ्यास के एक भाग के रूप में नीपा के परियोजना स्टाफ ने कालेज शिक्षकों के साथ मिलकर सांस्थानिक योजना का एक प्रारूप विकसित किया।

1990-91

अब तक निम्नांकित रपटें तैयार की गई हैं :

(1) कालेजों का प्रभावी कार्यकलाप और विकास : क्रियात्मक अनुसंधान परियोजना (प्रारंभिक रपट—द्रोणाचार्य राजकीय कालेज, गुडगांव)

(2) कालेजों का प्रभावी कार्यकलाप और विकास : क्रियात्मक अनुसंधान परियोजना (एन.बी.जी.एस. एम. कालेज, सोहना पर रपट का प्रारूप)

(3) समुदाय विकास के लिए संसाधन केंद्र के रूप में कालेज : संकल्पनात्मक ढांचा और कार्यान्वयन की प्रक्रिया

(4) हार्सरू गांव की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का विवरण

(5) हार्सरू गांव की शैक्षिक स्थिति का विवरण

(6) ग्रामीण समुदाय के विकास के लिए विज्ञान का अनुप्रयोग : मृदा विश्लेषण की रपट

द्रोणाचार्य राजकीय कालेज और एन. बी. जी. एस. एम. कालेज के शिक्षकों के साथ अनेक बैठकें आयोजित की गईं। समुदाय विकास के लिए संसाधन केंद्र के रूप में कालेज की भूमिका पर एक संकल्पनात्मक पत्र तैयार किया गया। सोहना कालेज की सांस्थानिक योजना का कार्य चल रहा है। सोहना कालेज में शिक्षण प्रविधि पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। द्रोणाचार्य कालेज में मूल्यांकन कार्य किया गया। कालेज में प्रबंध प्रक्रिया विषय पर एक रपट तैयार की जा रही है।

2. विद्यालय मानचित्रण पर परियोजना अध्ययन

परियोजना दल में निम्न शामिल हैं— श्री एम. एम. कपूर, परियोजना निदेशक, प्रो. डी. एन. अब्रॉल, परियोजना अध्येता, श्री आर. के. सौलंकी, वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता, और सुश्री पुष्पा कथूरिया, श्री इरफान अहमद और सुश्री अनिता नुना, परियोजना सहायक

इस परियोजना के लिए रु. 8.83 लाख की राशि स्वीकृत है।

परियोजना के दूसरे चरण में आंकड़ा संग्रह के उपकरण, प्रतिदर्श उपकरण, एक मुश्त योजनाएं, रपटों का प्रारूप और विषयगत पत्र तैयार किए गए। राजस्थान के चुरू जिले में उपकरणों का परीक्षण किया गया और उपकरणों में आवश्यक संशोधन के बाद दूसरे तकनीकी कार्यशिविर में इस पर विचारविमर्श किया गया।

इस परियोजना के एक भाग के रूप में विदिशा जिले में प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण के लिए विद्यालय मानचित्रण और व्यष्टि स्तर की योजना की परियोजना में मध्यप्रदेश को अकादमिक सहायता प्रदान की गई। इस संदर्भ में उनके अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया और उपकरण विकसित किए गए। इसके अलावा कार्यान्वयन संबंधी रणनीतियां भी बनाई गईं।

इस परियोजना में 10 राज्यों के अलावा अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली को भी शामिल किया गया। राज्य सरकार के अनुरोध पर अरुणाचलप्रदेश को शामिल किया गया, जबकि नगरीय क्षेत्रों में विद्यालय मानचित्रण की समस्याओं के अध्ययन के लिए कार्यक्रम सलाहकार समिति की सलाह पर दिल्ली की भी शामिल किया गया।

इस वर्ष प्रश्नावलियां तैयार की गईं और उन्हें संबंधित तेरह राज्यों में वितरित किया गया। एक तीन दिवसीय तकनीकी कार्यशिविर आयोजित किया गया जिसमें सर्वेक्षण के लिए मार्गदर्शिकाएं तैयार की गईं। आंकड़ा, संकलन, और मूल्यांकन तथा प्रखंडकीय योजनाएं तैयार करने में राज्य स्तर के परियोजना स्टाफ की मदद के लिए असम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिज़ोरम, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रीय दौरे किए गए। एक संदर्भ सूची भी तैयार की गईं।

विभिन्न राज्यों से प्राप्त रपटों पर जरूरी संशोधन के लिए विचार विमर्श किया गया।

3. द्वितीय अखिल भारतीय शैक्षिक प्रशासन सर्वेक्षण

परियोजना दल के सदस्य हैं — श्री एम. एम. कपूर, परियोजना निदेशक, डॉ. जे. सी. गोयल, परियोजना अध्येता, श्री आर. एस. त्यागी, परियोजना सह अध्येता, श्री वी. एन. आलोक और श्री ए. के. सिन्हा परियोजना सहायक और श्री भारत भूषण, परियोजना मानचित्रकार

इस परियोजना के लिए रु. 17.04 लाख की राशि स्वीकृत है।

सभी राज्यों/संघीय राज्यों में सर्वेक्षण कार्य संचालित करने के लिए प्रत्येक राज्य/संघीय राज्य के शिक्षा सचिव को राज्य स्तर के परियोजना निदेशक संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के लिए अनुरोध किया गया। राज्यों/संघीय राज्यों से अधिकारियों के नाम प्राप्त हुए। सर्वेक्षण कार्य के संचालन के लिए अनुदान राशि भी प्रदान कर दी गई। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को छोड़कर सभी स्तरों की शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों जैसे राज्य स्तर, क्षेत्र स्तर और सांस्थानिक स्तर की तीन प्रश्नावलियों के प्रारूप तैयार किए गए। राज्य स्तर के परियोजना निदेशकों के लिए राष्ट्रीय स्तर के दो तकनीकी कार्यशिविर आयोजित किए गए। इन कार्यशिविरों में प्रतिदर्श डिजाइन, सर्वेक्षण उपकरण और इस परियोजना से संबंधित राज्य स्तर की कार्यात्मक योजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया और राष्ट्रीय सलाहकार समिति के समक्ष पेश करने के लिए इन्हें अंतिम रूप से तैयार किया। इस परियोजना की डिजाइन, क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, सर्वेक्षण उपकरण, कार्य प्रणाली और वर्तमान स्थिति पर विचार-विमर्श के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति की बैठक हुई। समिति ने कुछ संशोधन के साथ सर्वेक्षण की प्रश्नावलियों और कार्यात्मक रणनीतियों के मसौदों का अनुमोदन किया। राष्ट्रीय सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर सर्वेक्षण उपकरणों को अंतिम रूप देकर मुद्रण के लिए भेज दिया गया।

अनेक मुद्रित प्रश्नावलियां आंकड़ा संग्रह के लिए राज्य परियोजना निदेशकों के पास भेज दी गईं। सचिवालय, निदेशालय और निरीक्षणालय इत्यादि संगठनात्मक ढांचे की तैयारी के लिए मार्गदर्शिकाएं अंतिम रूप से तैयार की गईं और परियोजना निदेशकों के नाम मंगवाए गए। राज्यों के विवरण विकसित करने की योजना शुरू की गई। 13-15 सितंबर, 1990 के दौरान राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यशिविर आयोजित किया गया जिसमें आंकड़ों को तालिका रूप में संयोजित करने और रपट लेखन पर विचार-विमर्श किया गया।

कुछ राज्यों से रपटों के मसौदे प्राप्त हुए जिन पर संशोधन की दृष्टि से विचार-विमर्श किया गया। रपट में सम्मिलित अनेक तालिकाओं को अंतिम रूप दिया गया। राज्य स्तर की सलाहकारी समिति की बैठकें भी आयोजित की गईं। दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, बिहार, त्रिपुरा, केरल, और मिज़ोरम के केस अध्ययन तैयार किए गए। एक संदर्भ सूची भी तैयार की गई।

4. लैटिन अमरीका में अनौपचारिक शिक्षा की योजना और प्रबंध का अध्ययन-भारत के लिए निहितार्थ और सीख

यह अध्ययन डॉ.(श्रीमती) अंजना मंगलागिरि कर रही हैं।

इसके लिए 1,46,200 रुपए की राशि स्वीकृत है। परियोजना के प्रथम चरण में लैटिन अमरीका के एक्वाडोर और कोलेबिया क्षेत्र में शैक्षिक विकास संबंधी उपलब्ध सूचनाएं एकत्र करने का प्रयास किया गया। उसी के अनुसार एक संदर्भ सूची तैयार की गई। इन क्षेत्रों के शैक्षिक विकास से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े एकत्र किए गए और उन्हें संकलित किया गया। दुनिया के इस भाग में इन दो क्षेत्रों की अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित सूचनाएं बहुत दुर्लभ हैं।

1990-91

ऐसी सामग्री एकत्र करने के लिए अमरीका, नीदरलैंड और फ्रांस के विश्वविद्यालयों के विभागों, संबद्ध संगठनों और व्यक्तियों से पत्राचार शुरू किया गया। इसके अलावा इन देशों के संस्थानों, संगठनों और विद्वानों से भी संपर्क करने का प्रयास किया गया, क्योंकि यहां के विद्वान लैटिन अमरीका में अनौपचारिक शिक्षा की स्थिति पर कार्य कर रहे हैं। ये संगठन थे—फ्लोरिडा स्टेट विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय/अंतर सांस्कृतिक विकास शिक्षा कार्यक्रम, तीसरी दुनिया केंद्र, नोजमंगान और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान, पेरिस।

इस अध्ययन से संबंधित सामग्री एकत्र करने के लिए अनेक बाह्य संगठनों से संपर्क किया गया। अधिकांश सामग्रियां विदेश स्थित अभिकरणों के पास थीं, इसलिए उन्हें प्राप्त करने के लिए पत्राचार माध्यम का सहारा लेना पड़ा। आशा है कि अंतिम रूप से रपट का मसौदा तैयार करने से पहले और अधिक सूचनाएं प्राप्त हो जाएंगी।

5. भारत में अनुसूचित जातियों और गैर अनुसूचित जातियों के साक्षरता स्तरों के बीच विषमताओं का जिलेवार विश्लेषण करना

इस परियोजना दल में निम्न शामिल हैं— डॉ. वाई. पी. अग्रवाल, परियोजना निदेशक और सुश्री सारिका सिबु, परियोजना सहायक। इस अध्ययन के लिए रु. 1,44,396.30 की राशि स्वीकृत की गई है।

इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं— अनुसूचित जातियों और गैर जातियों के साक्षरता स्तरों के बीच की असमानताओं को बढ़ावा देने वाले कारकों के मूल स्रोतों की पड़ताल करना, अनुसूचित जाति की आबादी के विभिन्न खंडों के बीच साक्षरता प्रसार के क्षेत्रीय प्रतिमानों की पहचान करना, और गैर अनुसूचित जातियों की आबादी के बीच की समानताओं विषमताओं की समीक्षा करना, साक्षरता स्तरों के बीच की खाई को मापने के लिए एक सुगम प्रणाली का विकास करना, साक्षरता दरों, असमानताओं और सामाजिक-आर्थिक विषमताओं के बीच के परस्पर संबंध के स्वरूप की समीक्षा करना और शिक्षा प्रणाली में इस प्रकार की असमानताओं को कम करने के लिए क्षेत्र विशेष नीतियों का विकास करना।

साक्षरता के स्तरों और अनुसूचित जाति की आबादी के लिए कार्यबल की भागीदारी संबंधी जिलेवार आंकड़ों का कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा किया गया। परियोजना सलाहकार समिति की बैठक बुलाई गई जिसमें भावी कार्ययोजना पर विचार विमर्श किया गया। आबादी वर्गीकरण, साक्षरतादर, कार्यबल वितरण और साक्षरता दरों की असमानताओं से संबंधित जिलेवार आंकड़ों का विश्लेषण कार्य पूरा किया गया। निम्नांकित अध्यायों की तैयारी शुरू कर दी गई है— (1) अनुसूचित जाति की आबादी के क्षेत्रीय वर्गीकरण के प्रतिमान और (2) साक्षरता विवरण और असमानताओं का विश्लेषण।

6. शैक्षिक संस्थानों में स्वायत्तता का प्रबंध : स्वायत्त कालेजों का अध्ययन

इस परियोजना दल के सदस्य हैं— डॉ. (श्रीमती) के. सुधा राव, परियोजना निदेशक और श्री जार्ज मैथ्यू, परियोजना सहायक

इस अध्ययन के लिए रु. 1,52,100/- की राशि स्वीकृत की गई है।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं— स्वायत्तता प्राप्त संस्थानों में स्वायत्तता के इस्तेमाल के रास्ते का अध्ययन करना, स्वायत्त कालेजों के ढांचेगत और कार्यगत मसलों का विश्लेषण करना, स्वायत्तता के संबंध में छात्रों और शिक्षकों के दृष्टिकोणों का पता लगाना, कार्यनिष्पादन की गुणवत्ता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े कार्यों की पहचान करना, शिक्षा की

गुणवत्तता के सुधार में स्वायत्तता के प्रभाव का अध्ययन करना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जरूरी परिवर्तनों को लागू करने में स्वायत्त कालेजों के सामने आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना, उच्च शिक्षा के संस्थानों में स्वायत्तता की प्रभाविता को मजबूत बनाने के लिए जरूरी प्रबंध कौशल की पहचान करना।

इस अध्ययन में सोद्देश्यात्मक प्रतिदर्श विधि का प्रयोग किया गया। दस्तावेज विश्लेषण तकनीक के माध्यम से प्रबंध विशेषज्ञों, उच्च शिक्षा के निदेशकों, उपकुलपतियों, संस्थाप्रमुखों, स्वायत्त और गैरस्वायत्त संस्थाओं के शिक्षकों और छात्रों से बातचीत करके आंकड़े एकत्र किए गए। स्वायत्तता के विभिन्न पक्षों के अध्ययन के लिए प्रश्नावली विश्लेषण की विधि अपनाई जाएगी।

आंकड़ा संग्रह का कार्य शुरू हुआ। अध्ययन से संबंधी साहित्यों की समीक्षा की गई। स्वायत्त कालेजों के विस्तृत केस अध्ययनों के लिए रूपरेखा तैयार की गई। आंध्रप्रदेश के 8 कालेजों और तमिलनाडु के 13 कालेजों से आंकड़े एकत्र किए गए। एकत्र आंकड़ों की तालिकाओं में संकलित किया गया। विश्लेषण कार्य चल रहा है। रपट के मसौदे की योजना को अंतिमरूप दिया जा रहा है।

7. आदिवासी और उपयोजना क्षेत्रों के शैक्षिक विकास का अध्ययन

यह अध्ययन डॉ. सुजाता कर रही हैं।

इस अध्ययन के लिए रु. 1,15000/- की राशि स्वीकृत है।

इसके मुख्य उद्देश्य निम्न हैं— विद्यालयों की गुणवत्ता, मात्रा तथा प्रभाव क्षेत्र समेत उपयोजना क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं के वितरण के वर्तमान प्रतिमान का अध्ययन करना, छात्र-शिक्षक अनुपात, शिक्षकों की योग्यता और विद्यालय में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं के सापेक्ष गुणवत्ता को मापा गया है। शिक्षकों की सामाजिक-भाषायी पृष्ठभूमि और आदिवासियों और छात्रों के प्रति उनके दृष्टिकोणों का अध्ययन करना, दाखिले का विस्तार, विद्यालय त्याग और सफलता पूर्वक पूरी की गई शिक्षा का अध्ययन, विभिन्न मदों के अनुसार शिक्षा प्रति इकाई लागत की समीक्षा करना और आदिवासियों की शैक्षिक प्रगति में कार्यप्रणाली की प्रभाविता को समझने के लिए शिक्षा के विशेष संदर्भ में प्रतिदर्श इलाके में कृषि, स्वास्थ्य इत्यादि अंतरविभागीय समन्वयन के स्वरूप का पता लगाना और आदिवासी क्षेत्रों में शैक्षिक विकास के लिए व्यष्टि स्तरीय योजना के तहत कार्य योजना बनाना।

अध्ययन के लिए आंकड़ा संग्रह, संकलन और विश्लेषण संबंधी कार्य जून, 1990 में पूरे किए गए। रिपोर्ट लिखी जा रही है।

8. कालेजों के विकास में कालेज विकास परिषदों की भूमिका का अध्ययन करना : 10 चयनित कालेज विकास परिषदों का गहन अध्ययन

परियोजना दल में निम्न शामिल हैं— डॉ. (श्रीमती) जया इंदिरेसन, परियोजना निदेशक, सुश्री एम. तुलसी और सुश्री एम. कागदियाल, परियोजना सहायक।

इस अध्ययन के लिए रु. 1,26,800/- की राशि स्वीकृत है।

अध्ययन के मुख्य उद्देश्य हैं— कालेजों के विकास में का. वि. प. के योगदान के कार्यकलापों में सुविधाओं और बाधाओं के कारकों की पहचान करना और अगर जरूरी हुआ तो कालेजों के विकास में का. वि. प. की भूमिका को मजबूत बनाने के लिए सुझाव पेश करना।

इस दृष्टिकोण से अध्ययन को अखिल भारतीय स्वरूप देने के उद्देश्य से देश के सभी क्षेत्रों से कालेज विकास परिषदों

1990-91

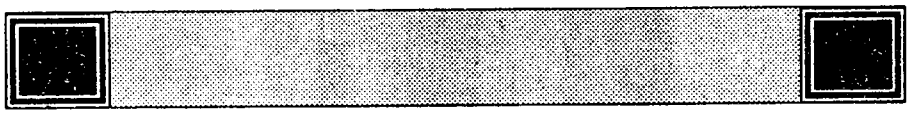

का चयन किया गया। यह अध्ययन विशेष रूप से साक्षात्कार और बातचीत पर आधारित था, इसलिए का. वि. प. के निदेशकों, संबद्ध विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और अन्य अधिकारियों से विस्तृत रूप से बातचीत की गई। का. वि. प. के कार्यकलापों पर प्राचार्यों की प्रतिक्रियाएं जानने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से भी बातचीत की गई। इसके अलावा 20 का. वि. प. की गतिविधियों और उपलब्धियों से संबंधित दस्तावेज और रपटें भी प्राप्त हुई हैं।

का. वि. प. की प्रमुख चार भूमिकाओं—अकादमिक नेतृत्वकारी भूमिका, संचारेक्षण और कार्यान्वयन भूमिका, संचालन भूमिका और योजनागत भूमिका और का. वि. प. की भूमिकाओं की प्रभाविता के अध्ययन के लिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है।

मैसूर के का. वि. प. और अनेक कालेजों से आंकड़े एकत्र किए गए। केस अध्ययन तैयार किए गए। विभिन्न कालेज विकास परिषदों और कालेजों से एकत्र सूचनाओं का विश्लेषण किया गया। रपट के मसौदे और केस अध्ययनों को अंतिम रूप देने का कार्य चल रहा है।

9. बेसिक शिक्षा सेवा की गुणवत्ता (नीपा–अ. शै. यो. सं. पेरिस सह-अध्ययन)

इस परियोजना दल में निम्न शामिल हैं— डॉ. आर. गोविंद, परियोजना निदेशक, डॉ. एन. वी. वर्गीज, परियोजना संयोजक और आर. पी. कथूरिया, परियोजना संयोजक (क्षेत्रीय कार्य)

इस अध्ययन के लिए रु. 6,64,900/- की राशि स्वीकृत है।

बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता और बेसिक शिक्षा के कार्यकलापों के संचारेक्षण में प्राप्त सुधार के लिए जरूरी रणनीतियों के प्रतिपादन के लिए बेसिक शिक्षा संस्थाओं के कार्यकलापों और संसाधनों का विश्लेषण करना ही इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है।

हिंदी और गणित विषयों के संप्राप्ति परीक्षण प्रश्नपत्र तैयार किए गए। कोडीकरण की योजनाएं विकसित की गईं। मध्यप्रदेश के 5 परियोजना क्षेत्रों के चुने गए विद्यालयों के 2100 छात्रों के विभिन्न परीक्षण किए गए। विभिन्न प्रश्नावलियों (प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों के लिए) की आंकड़ा फाइलें और उपलब्धि परिणाम तैयार किए गए और उन्हें अं. शै. यो. सं, पेरिस भेज दिया गया। आंकड़े का प्रारंभिक विश्लेषण, आंकड़ा विश्लेषण के ढांचे का विकास और रपट के मानदंड की योजना बनाई गई और एक कार्यशिविर में इन पर चर्चा की गई। इसमें अं. शै. यो. सं., पेरिस के श्री टा. नागेक चाऊ भी उपस्थित थे।

इस अध्ययन की रिपोर्ट के मसौदे का कार्य अंतिम चरण में है।

10. शिक्षा की संगणकीकृत योजना (शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित)

इस परियोजना दल में निम्न शामिल हैं— श्रीमती अनिता चोपड़ा, श्री पी. रघु राम राव, मु. अहमद अंसारी और श्री अरूप बनर्जी।

इस परियोजना के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा रु. 10,22,534/-की राशि स्वीकृत की गई है।

प्रारंभिक शिक्षा के लिए कोप के वतर्ज निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया गया। यहां कोप का तात्पर्य शिक्षा की संगणकीकृत योजना से है। (अतः आगे हम इसे कोप/नि. सं. प्र. के नाम से ही व्यक्त करेंगे।)

1990-91

इस परियोजना के सभी 7 पायलट जिलों—ग्वालियर, मोरैना, शिवपुरी, भिंड, गुना, दतिया और अलीगढ़ में प्रणाली का परीक्षण किया गया।

इन जिलों में निम्नांकित कार्य पूरे किए गए :

'उपयोग में आ सकने वाली अधिकतम सूचनाओं' में से 'उपयोगी सूचनाएं' छाटने की प्रक्रिया का क्षेत्रीय अध्ययन किया गया।

प्रधानाचार्यों और आंकड़ा प्रविष्टि संचालकों के लिए सरल आंकड़ा संग्रह प्रपत्र तैयार किया गया। साल में एक बार भरा जाने वाला ग्यारह पेज का एक प्रपत्र विकसित किया गया। वर्तमान संप्रेषण तकनीकों के माध्यम से आंकड़ा संग्रह कार्य के लिए प्रशिक्षण दिया गया। प्रपत्रों में आम प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया गया और कार्य को और आसान बनाने के लिए स्थानीय शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया।

कोप के पायलट जिलों के लिए नियुक्त दो क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ काम कर चुके तीन व्यक्तियों के एक समूह ने साफ्टवेअर विकसित किया।

अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में साफ्टवेअर का विकास किया जा रहा है।

कोप/नि. स. प्र. साफ्टवेअर का हिंदी अनुवाद कराने का निर्णय लिया गया था। अतः भाग 2 का हिंदी अनुवाद किया जा रहा है। मध्यप्रदेश के दतिया जिले का आंकड़ा पूरी तरह संगणक में संसाधित कर दिया गया और उसे उपयोग में लाने योग्य बना दिया गया। अब जिला शिक्षा अधिकारी को नियमित रूप से क्षेत्र की रिपोर्टें मिलती हैं।

मध्यप्रदेश के 54 जिलों और राजस्थान तथा बिहार के तीन-तीन जिलों में कोप/नि. स. प्र. कार्य प्रणाली स्थापित करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है।

भोपाल में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्षेत्रीय केंद्र भोपाल में नवनियुक्त कार्मिकों के लिए नीपा में एक माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में संगणक लगाए गए। निम्नांकित जिलों में आंकड़ा प्रविष्टि प्रक्रिया शुरू की गई— जबलपुर, बालाघाट, मांडला, सेवनी, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमतरा और कावासर्धा। इनमें अधिकांश जिलों में आंकड़ा आधार का कार्य पूरा हुआ। 17 जिले आंकड़ा आधार बनाने में समर्थ हो गए हैं

इस परियोजना को उत्तर प्रदेश में भी शुरू किया गया और इटावा को पायलट जिला बनाया गया। उत्तरप्रदेश के अधिकारियों की कोप/नि. स. प्र. में प्रशिक्षित किया गया। इटावा में एक क्षेत्रीय अधिकारी नियुक्त किया गया। वर्तमान संगणक प्रणाली के लिए व्यष्टि योजना का सरल माड्यूल तैयार किया जा रहा है।

11. जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए संचारेक्षण सूचना प्रणाली (शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित)

परियोजना दल में निम्न शामिल हैं : सुश्री सुषमा पोपली और श्री रघु राम राव।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग ने इस अध्ययन के लिए रु. 7,23,300/- की राशि स्वीकृत की है।

आधारभूत स्तर के प्रयोक्ताओं के लिए बिल्कुल सरल साफ्टवेअर का विकास किया गया है। इसमें शामिल हैं— (अ) अनौपचारिक शिक्षा केंद्र विश्लेषण (ब) अनुदेशक विश्लेषण, (स) पर्यवेक्षक विश्लेषण (द) छात्र दाखिला विश्लेषण (य) छात्र उपस्थिति विश्लेषण (र) अनौपचारिक शिक्षा केंद्र आंकड़ा आधार (ल) अपवाद सूची चयन और (व) वित्तीय लेखा। अब यह साफ्टवेयर हिंदी में भी उपलब्ध है।

1990-91

हिंदी और अंग्रेजी में प्रयोक्ता मार्गदर्शिका प्रकाशनाधीन है।

इस बात पर विशेष बल दिया गया कि कोप/अनो. शि. साफ्टवेअर योजना मध्यप्रदेश में तीन चरणों में लागू की जाएगी। पहले दो चरण पूरे हो गए हैं। तीसरा चरण जल्द ही शुरू किया जाएगा। प्रस्तावित क्षेत्रीय केंद्र भोपाल में स्थापित किया गया है।

शिक्षा सचिव के साथ 27 मार्च, 1990 को एक बैठक आयोजित की गई जिसमें अनौपचारिक शिक्षा और निर्णय समर्थन प्रणाली को संघटित करने का निर्णय लिया गया। अतः यह अध्ययन कोप के साथ शामिल कर दिया जाएगा।

12. भारत के शैक्षिक विकास में क्षेत्रीय असमानताएं : आधारभूत स्तर पर समाज कल्याण के संदर्भ में शैक्षिक असमानताओं की जांच पड़ताल

इस अध्ययन के लिए रु. 3,48,840/- राशि की अनुमानित लागत स्वीकृत की गई है। इस परियोजना दल में निम्न शामिल हैं— डॉ. एस. सी. नुना, परियोजना निदेशक, सुश्री बासोबी सरकार, परियोजना सहायक और श्री जमालुद्दीन फारुकी, परियोजना मानचित्रकार।

अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं— विद्यालय स्तर पर शैक्षिक विकास में असमानताओं का विश्लेषण करना और असमानताओं को कम करने के लिए व्याख्यात्मक प्रणाली का विकास करना, विकास के अन्य आयामों के साथ शिक्षा के अंतःसंबंधों का विश्लेषण करना और आधारभूत स्तरों पर संघटित योजना के ढांचे का विकास करने के उद्देश्य से विकास की वर्तमान प्रणाली का विकास करना।

आंकड़ा संग्रह की योजना विकसित की गई। प्राथमिक शिक्षा संबंधित अभिवृद्धि के आंकड़े एकत्र करके संगणक में संसाधित किया गया। परियोजना का एक भाग के रूप में पंचवर्षीय योजनाओं के तहत संघटित योजना नामक पत्र विकसित किया गया। सभी जिलों के दाखिले संबंधी आंकड़े 'पांचवां अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण' से एकत्र किए गए और संगणक में उनका संसाधन भी किया गया। आंकड़ों को तालिका में समायोजित किया जा रहा है।

13. भारत में संसाधनों का प्रभावी उपयोग –केस अध्ययन

इस अध्ययन के लिए रु. 1,19,100.00/-की अनुमानित राशि स्वीकृत की गई है। डॉ. जे. बी. जी. तिलक इसके परियोजना निदेशक हैं।

इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं : संस्थागत लागत और निर्गत के आधार पर शिक्षा की लागत प्रभाविता का विश्लेषण करना, समय-समय पर विभिन्न कार्यकलापों के लिए विद्यालयों में संसाधन जुटाने और उसका उपयोग करने में अपनाए जाने वाले प्रतिमानों का विश्लेषण करना और संसाधन जुटाने/उपयोग करने के प्रतिमानों में विभिन्नता लाने वाले कारकों की समीक्षा करना।

यह अध्ययन एक जिले के प्रारंभिक प्रतिदर्श आंकड़े पर आधारित है।

इस क्षेत्र के नए साहित्यों का अध्ययन किया गया। प्रश्नावली को अंतिम रूप दिया गया। आंकड़ा संग्रह की योजना बनाई गई। परियोजना का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।

14. भारतीय विश्वविद्यालयों का वित्तीय प्रबंध (नीपा सहायता योजना के अंतर्गत)

इस अध्ययन के लिए दिसंबर 1988 में रु. 48,000/- की राशि स्वीकृत की गई है। यह अध्ययन डॉ. मालती सोमैया, भारतीय प्रबंध संस्थान, बैंगलौर, कर रही हैं। मैसूर विश्वविद्यालय मैसूर और कृषि विश्वविद्यालय धारवाड़ के साथ विचार-विमर्श के पश्चात अध्ययन के उपकरण तैयार किए गए। साहित्यों की समीक्षा पूरी की गई। प्रश्नावली

तैयार की गई और आंकड़ा संग्रह का कार्य चल रहा है। रिपोर्ट का मसौदा बनाया जा रहा है। दो विश्वविद्यालयों से आंकड़ा एकत्र करके संगणक में संसाधित किया गया। रिपोर्ट लिखी जा रही है।

15. भारत के वर्तमान पत्राचार संस्थानों में शिक्षण और अधिगम के प्रबंध की प्रणालियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन (नीपा सहायता योजना के अंतर्गत)

इस अध्ययन के लिए जुलाई, 1989 में रु. 72,300/- की राशि स्वीकृत की गई है। डॉ. एस. सी. एस. राथौड़, प्रवक्ता, शिक्षा विभाग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, यह अध्ययन कर रहे हैं।

इस अध्ययन के लक्ष्य हैं (अ) निम्नांकित के संदर्भ में अनुशिक्षण और अधिगम के प्रबंध के लिए वर्तमान में अपनाई जाने वाली प्रणालियों का अध्ययन करना (1) अधिगम सामग्रियों का विकास, (2) अधिगम सामग्रियों का वितरण, (3) पुनर्निवेशन (4) अध्ययन केंद्र और (5) परीक्षाएं/छात्र मूल्यांकन और (ब) एक लक्ष्य के तहत अध्ययन पक्षों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। आंकड़ा संग्रह कार्य पूरा किया गया। कालेजों से एकत्र आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और रिपोर्ट लेखन कार्य चल रहा है।

16. तमिलनाडु में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रबंध (नीपा सहायता योजना के अंतर्गत)

इस अध्ययन के लिए अगस्त, 1989 में रु. 63,000/- की राशि स्वीकृत की गई है। यह अध्ययन मदुरई कामराज विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष प्रो. डॉ. सी. सुब्रह्मण्यम पिल्लई कर रहे हैं।

अध्ययन के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं : तमिलनाडु में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो, टी. वी. और वीडियो प्रौद्योगिकी के हार्डवेअर और साफ्टवेअर संबंधी पक्षों के संदर्भ में अब तक की प्रगति की समीक्षा करना, यह पता लगाना कि ये प्रौद्योगिकियां कितनी उपयोगी हैं और संकाय के सदस्यों ने इनका कितना उपयोग किया है, इन प्रौद्योगिकियों में अगर किसी प्रकार की कमी हो तो उनको प्रकाश में लाना और शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अध्ययन के प्रभावी प्रबंध के लिए समुचित सलाह देना।

संबंधित साहित्यों की समीक्षा पूरी की गई। 25 जून, 1990 को एक दिन का कार्यशिविर आयोजित किया गया जिसमें अध्ययन के लिए विकसित किए गए उपकरणों पर गहराई से विचार विमर्श किया गया और उनमें जरूरी संशोधन भी किया गया। प्रश्नावलियों को अंतिम रूप देकर मुद्रित किया गया। उच्च शिक्षा के संस्थानों और संकाय के सदस्यों से आंकड़ा एकत्र किया गया। आंकड़े को तालिकाबद्ध किया जा रहा है। साथ ही प्रथम अध्याय के मसौदे पर भी कार्य हो रहा है।

17. भारत में कृषि स्नातकों के रोजगार के अवसर : राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर का लागत-लाभ अध्ययन (नीपा सहायता योजना के अंतर्गत)

इस अध्ययन के लिए रु. 61,200/- की अनुमानित राशि स्वीकृत की गई है। डॉ. बी. सी. मेहता, प्रोफेसर (अर्थशास्त्र) सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर यह अध्ययन कर रहे हैं।

अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं : राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के स्नातकों के रोजगार के संबंध में विस्तृत मात्रात्मक विश्लेषण करना ताकि कृषि शिक्षा नीति में सुधार के लिए सुझाव दिया जा सके, कृषि शिक्षा की मांग और आपूर्ति का अध्ययन करना, कृषि शिक्षा की लागत प्रभाविता का अध्ययन करना और कृषि शिक्षा के वित्तीय और उत्पादकता संबंधी पक्षों का अध्ययन करना, कृषि स्नातकों की क्षैतिज और उर्ध्व गतिशीलता का अध्ययन करना, मौजूदा

1990-91

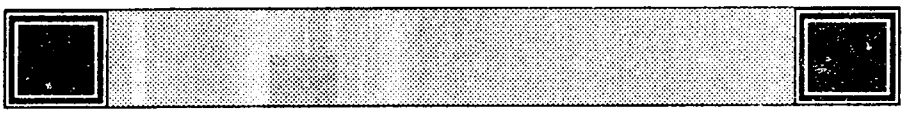

वर्ष में सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण करना ताकि प्रवेश नीति और भारत में आर्थिक विकास के सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के निहितार्थों का मूल्यांकन किया जा सके और यह पड़ताल करना कि क्या कृषि शिक्षा के अभिविन्यास से सामाजिक निर्गतों में वृद्धि की जा सकती है।

पशुविज्ञान कालेज, बीकानेर और क्षेत्रीय कृषि कालेज, उदयपुर से द्वितीयक आंकड़े एकत्र किए गए। कालेजों की स्थापना से अब तक दाखिल छात्रों की सूची तैयार की गई और प्रतिदर्श के चुनाव में यादृच्छ प्रणाली प्रयोग में लाई गयी। शिक्षा के निर्गतों का अध्ययन करने के लिए इन दोनों प्रतिदर्श कालेजों के कृषि स्नातकों को प्रश्नावली भेजी गई। इसके अलावा निजी लागत का अध्ययन करने के लिए इन दोनों प्रतिदर्श कालेजों के अंतिम वर्ष के छात्रों से निजी संपर्क करके प्रश्नावलियां भरवाई गईं। एकत्र सूचनाओं की तालिकाएं बनाई जा रही हैं।

स्वीकृत नए अध्ययन

1. पर्वतीय वोंडा जाति के मूल्य, दृष्टिकोण और भागीदारी (नीपा सहायता योजना के अंतर्गत)

प्रो. एल. के. महापात्रा, अध्यक्ष सामाजिक अनुसंधान और कार्य परिसंघ, मुदुलीपाडा, कोरापुट, उड़ीसा—764043 यह अनुसंधान अध्ययन संचालित कर रहे हैं। इस अध्ययन के लिए 18 महीने की अवधि तय की गई है तथा इसको पूरा करने के लिए रु. 50,000/-की अनुमानित राशि स्वीकृत की गई है। अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

1. यह पता लगाना कि क्या विद्यालय जाने वाले छात्रों के माता-पिता छात्रों को अपनी शिक्षा ठीक प्रकार से पूरी करने के लिए विद्यालय में उनका पढ़ना पसंद करते हैं।
2. यह पता करना कि क्या विद्यालय जाने वाले छात्र अपने परिवार व गांव के लिए घर तथा बस्ती के कृषि और वन संबंधी कार्यों में हाथ बंटाते हैं।
3. 20 वोंडा लड़के और लड़कियों पर एक साल की पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रायोगिक परीक्षण करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन बच्चों पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है।
4. जीवन और शिक्षा की बदलती भूमिका के संबंध में वोंडा के दृष्टिकोण और मूल्यांकन प्रकाश में लाना जिसमें बच्चों के संबंध में उनके विचार भी हों।
5. यह पता लगाना कि आवासीय आश्रम विद्यालय और आवासीय सेवाश्रम विद्यालयों की वर्तमान सुविधाओं से वोंडा किस हद तक लाभान्वित हो सकते हैं।
6. विद्यालय छोड़ने वाले या कभी विद्यालय न जाने वाले बच्चों की गतिविधियों के आर्थिक मूल्य का पता लगाना।

2. प्रारंभिक शिक्षा में प्रगति का संचारेक्षण–प्रतिदर्श अध्ययन (शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित)

परियोजना दल में निम्न शामिल हैं— श्री एम. एम. कपूर, परियोजना निदेशक, डॉ. डी. एन ॲब्रोल, परियोजना संयोजक और डॉ. डी. बी. दामले, परियोजना सहायक

इस अध्ययन के लिए रु. 10,000,00/- की राशि स्वीकृत की गई है।

1990-91

प्रतिदर्श चयन : दिसंबर, 1990 की बैठक में अनुपस्थित राज्यों में से बिहार और पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य सभी राज्यों से प्रतिदर्श चयन का कार्य पूरा हो गया। उक्त दो राज्यों में प्रखंड और नगर स्तर पर प्रथम चरण का प्रतिदर्श चयन कार्य ही हो सका।

प्रपत्रों का वितरण : जिन राज्यों में प्रपत्र वितरित नहीं किए गए थे, उनमें दिसंबर, 1990 में प्रपत्र वितरित किए गए।

आंकड़ा संग्रह : अधिकांश राज्यों और संघीय राज्यों में आंकड़ा संग्रह कार्य काफी तेजी से हुआ। सिर्फ आंध्रप्रदेश, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कार्य की स्थिति संतोषजनक है। अधिकांश राज्यों/संघीय राज्यों में आंकड़ा संग्रह का कार्य लगभग पूरा हो गया है और अब आंकड़ों की छानबीन की जा रही है।

क्षेत्रीय दौरे : इस वर्ष परियोजना स्टाफ ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ के दौरे किए। इससे कार्य की गति तेज करने में मदद मिली।

आंकड़े का संगणकीय संसाधन : आंकड़ा संसाधन के लिए भरोसे की संस्था का चयन किया जा चुका है। करार संबंधी शर्तों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

3. शैक्षिक सांख्यिकी में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण तकनीकों का उपयोग

परियोजना दल में निम्न सदस्य शामिल हैं— प्रो. श्रीप्रकाश, परियोजना निदेशक, डॉ. अरुण सी. मेहता, डॉ. सुश्री रंजना श्रीवास्तव, डॉ. एस. एम. आई. ए. जैदी और सुश्री तरुज्योति बुड़ागोहाई, सुश्री सुमित्रा चौधरी और सुश्री आभा अग्रवाल, परियोजना सहायिकाएं।

इस अध्ययन के लिए 20,000/-अमरीकी डालर की राशि स्वीकृत है।

(अ) संस्थानों में वितरण के लिए एक विस्तृत प्रश्नावली विकसित की गई है। इस संबंध में निम्नांकित राज्यों से विचार-विमर्श किया गया है :
(1) उत्तर प्रदेश, (2) गुजरात, (3) हरियाणा, (4) राजस्थान

परिवारों के बीच वितरित करने के लिए भी एक प्रश्नावली विकसित की गई है।

(ब) इन प्रश्नावलियों का क्षेत्रविशेष में पूर्व परीक्षण किया जा रहा है।

(स) निम्नांकित वर्तमान आंकड़ा आधार की समीक्षा के लिए व्यापक अभ्यास भी किया गया है— (1) राष्ट्रीय, (2) क्षेत्रीय स्तर, (3) उप-क्षेत्रीय स्तर। इसके अलावा निम्नांकित प्रकाशनों के आधार पर राष्ट्रीय स्तर की आंकड़ा प्रणाली से संबंधित अभ्यास का एक भाग भी पूरा किया जा चुका है : (1) एन. एस. एस. ओ. (2) सी. एस. ओ. (3) शिक्षा विभाग (भारत सरकार), (4) महा पंजीयक अधिकारी, भारत सरकार।

(द) लखनऊ और रोहतक के दौरे किये जा चुके हैं। अप्रैल, 1991 के अंतिम दो सप्ताहों में गांधीनगर, जयपुर, बीकानेर और बारमेर के दौरे भी किए जाएंगे। जबकि मई, 1991 के अंत में रोहतक के संस्थानों और गांव स्तर के क्षेत्रों के दौरे भी पूरे कर लिए जाएंगे।

4. मिज़ोरम और मेघालय की साक्षरता स्थिति पर प्रभाव डालने वाले कारकों का पायलट अध्ययन (नीपा सहायता योजना के अंतर्गत)

इस क्षेत्र में जनवरी 1991 से छः महीने के एक पायलट अध्ययन की मंजूरी मिली है। इसके लिए रु. 32,500/- की

1990-91

राशि स्वीकृत की गई है। इस अध्ययन दल में निम्न शामिल हैं— डॉ. बिलोरीस लिंडेन लासो और एस. होम चौधरी, नेहू, शिलांग। अध्ययन के मुख्य उद्देश्य हैं :

1. साक्षरता में वृद्धि और असमानताओं के विशेष संदर्भ में दोनों राज्यों की प्रखंडवार साक्षरता दरों का तुलनात्मक विश्लेषण करना,

2. इन दो राज्यों— मिज़ोरम और मेघालय में शिक्षा के प्रथम स्तर पर संवृद्धि के प्रतिमान का अध्ययन और विश्लेषण करना,

3. जिलेवार आबादी वृद्धिदर के साथ संबंधित साक्षरतादर का अध्ययन करना।

5. उत्तरप्रदेश में सबके लिए बेसिक शिक्षा

इस अध्ययन दल में निम्न शामिल हैं— श्री एस. सी. बेहर, भा. प्र. से. , सलाहकार, सुश्री सुनीता और सुश्री दीपा खरवाल, परियोजना सहायिकाएं।

'सबके लिए शिक्षा' परियोजना के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं :

(1) बेसिक शिक्षा में समता का विकास करना और डी. डी. यू. तथा महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि करना,

(2) बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता में विकास करना,

(3) उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा प्रणाली के प्रशासन और प्रबंध की क्षमता में वृद्धि करना।

विश्वबैंक के अनुदान से संचालित उत्तर प्रदेश के 10-15 जिलों में 'सबके लिए शिक्षा' परियोजना के दस्तावेज की तैयारी में उत्तर प्रदेश सरकार की मदद करना भी इस परियोजना का एक उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें आयोजित की गईं और परियोजना दस्तावेज की तैयारी में अन्य दूसरे व्यक्ति भी शामिल हुए।

विश्वबैंक को पेश किए जाने वाले परियोजना प्रस्ताव पर नीपा में दो दिन की बैठक आयोजित की गई और प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। इस बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (शिक्षा विभाग) विश्व बैंक, उत्तर प्रदेश सरकार और नीपा के अधिकारी शामिल हुए।

1990-91

अध्याय 4

परामर्शकारी और अन्य सेवाएं

भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में परामर्शकारी और समर्थनकारी सेवाएं प्रदान करना संस्थान के प्रमुख कार्यों में से एक है। इनसे संबंधित इस वर्ष की महत्वपूर्ण गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया है।

कार्यक्रम

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए 31 कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें नागालैंड के वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों के लिए एक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए एक कार्यक्रम समेत व्यष्टि स्तरीय योजना और विद्यालय मानचित्रण पर 5 कार्यक्रम, राजस्थान के लिए सांस्थानिक योजना और मूल्यांकन पर दो कार्यक्रम, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के लिए लैब क्षेत्रीय माध्यम पर एक कार्यक्रम समेत 4 कार्यक्रम, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा पर तीन कार्यक्रम, केंद्रीय विद्यालय संगठन के वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासकों के लिए दो कार्यक्रम, पिछड़े व सुविधावंचित वर्गों के लिए दो कार्यक्रम और अकादमिक स्टाफ कालेज के लिए एक कार्यक्रम शामिल हैं।

अनुसंधान अध्ययन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन से संबंधित निम्नांकित अनुसंधान अध्ययन शुरू किए गए :

(1) वर्ष 2000 ई. में शिक्षा—दूरगामी संप्रेक्ष्य

(2) भारत में साक्षरता—क्षेत्र कालिक विश्लेषण (1901-1981)

(3) कालेजों के प्रभावी कार्यकलाप और विकास : क्रियात्मक अनुसंधान अध्ययन

(4) आदिवासी और उप-योजना क्षेत्रों के शैक्षिक विकास का अध्ययन

(5) विद्यालय मानचित्रण पर परियोजना

(6) द्वितीय अखिल भारतीय शैक्षिक प्रशासन सर्वेक्षण

(7) भारत में अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जाति की आबादी के साक्षरता स्तरों के बीच असमानताओं का जिलेवार सर्वेक्षण

(8) शैक्षिक संस्थानों की स्वायत्तता का प्रबंध

(9) प्रारंभिक शिक्षा का संगणकीकृत योजना (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित)

(10) उच्च शिक्षा में वर्तमान सुविधाओं और संसाधनों की और अधिक उपयोगिता का अध्ययन (योजना आयोग द्वारा प्रायोजित)

विशेष जरूरत के कार्यक्रम

राज्यों, संघीय राज्यों और राष्ट्रीय स्तर के संगठनों के अनुरोध/सहयोग से खास जरूरतों को पूरा करने के लिए

1990-91

संस्थान ने 23 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशिविर और संगोष्ठियां आयोजित किए। इनमें निम्न कार्यक्रम शामिल थे – नवोदय विद्यालय समिति के लिए दो कार्यक्रम, केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए एक कार्यक्रम, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के लिए तीन कार्यक्रम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुरोध पर अकादमिक स्टाफ कालेज के लिए एक कार्यक्रम, राजस्थान और अंडमान निकोबार राज्य सरकारों के अनुरोध पर प्रत्येक के लिए एक-एक कार्यक्रम।

वार्षिक योजना चर्चा

संस्थान ने योजना आयोग में विभिन्न राज्यों/संघीय राज्यों के शिक्षा क्षेत्रों के कार्यदलों में भाग लिया।

अध्ययन/परियोजनाएं

सहयोगी/प्रायोजित अध्ययन/परियोजनाएं

संस्थान ने निम्नांकित सहयोगी/प्रायोजित अनुसंधान अध्ययन/परियोजनाएं शुरू किए :

(1) बेसिक शिक्षा सेवाओं की गुणवत्ता (नीपा – आई. आई. इ. पी) (सहयोगी अध्ययन)

(2) महिला कालेज के प्रशासकों के प्रशिक्षण की जरूरतों की पहचान (नीपा–एस.एन.डी.टी. विश्वविद्यालय) (सहयोगी अध्ययन)

(3) प्रारंभिक शिक्षा का संगणकीकृत योजना (शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित और अनुदान प्राप्त)

(4) उच्च शिक्षा में वर्तमान सुविधाओं और संसाधनों की प्रभावी उपयोगिता का अध्ययन करना (योजना द्वारा प्रायोजित और अनुदान प्राप्त)

(5) प्रारंभिक शिक्षा में प्रगति कीं उपलब्धि का संचारेक्षण (शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)

(6) शैक्षिक सांख्यिकी में प्रतिदर्श सर्वेक्षण तकनीकों का प्रयोग (यूनेस्को द्वारा प्रायोजित)

(7) उत्तर प्रदेश में सबके लिए शिक्षा (विश्व बैंक परियोजना)

राज्यों के अनुरोध पर अध्ययन/परियोजनाएं

आंध्र प्रदेश, राज्य सरकार के अनुरोध पर संस्थान ने आंध्रप्रदेश में शिक्षा और विकास पर एक मोनोग्राफ तैयार किया। महाराष्ट्र के अनुरोध पर संस्थान ने महाराष्ट्र की शिक्षा और विकास पर एक मोनोग्राफ विकसित करने का कार्य शुरू किया है।

विशेष मसलों पर व्यावसायिक समर्थन सेवा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना के मूल्यांकन और संचारेक्षण के लिए संस्थान ने एक योजना बनाई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि वैज्ञानिकों की भर्ती प्रणाली के पुनर्गठन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए पाठ्यचर्या के विकास में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नागालैंड को संस्थान ने व्यावसायिक सेवाएं प्रदान कीं।

परामर्शकारी सेवा

प्रस्तावित परियोजना–'लोक जुंबिश' की तैयारी में डॉ. जे. बी. सी. तिलक ने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) को विशेषज्ञ के रूप में सेवा प्रदान की।

1990-91

'अधिगम के न्यूनतम स्तर' नामक सामग्री के विकास में डॉ. आर. गोविंद ने विशेषज्ञ के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग को सेवा प्रदान की।

विशेष क्षेत्रों में संकाय का अकादमिक योगदान

व्यावसायिक निकायों समेत अन्य शैक्षिक संस्थानों तथा प्रतिष्ठानों के प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यों में संस्थान के संकायों ने अकादमिक और सरकारी समितियों/प्रतिनिधि मंडलों के सदस्य के रूप में और विशेष क्षेत्र में प्रकाशित अपने अनुसंधान पत्रों और पुस्तकों के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान कीं।

देश के विभिन्न राज्य सरकारों, संघीय प्रशासनों, विश्वविद्यालयों, कालेजों, विद्यालय शिक्षा परिषदों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों, राज्य लोक प्रशासन संस्थानों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, योजना आयोग, अकादमिक स्टाफ कालेजों और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय को संस्थान ने अकादमिक सेवाएं प्रदान कीं।

संस्थान के संकायों द्वारा किए गए ऐसे अकादमिक योगदानों का संक्षिप्त विवरण अनुबंध–IV में दिया गया है।

1990-91

अध्याय 5

पुस्तकालय, प्रलेखन और प्रकाशन सेवाएं

संस्थान के विविध प्रकार के अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अनुसंधानों और अन्य अकादमिक गतिविधियों में पुस्तकालय, प्रलेखन और प्रकाशन विभागों की मदद ली जाती है। इनसे शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में नवाचारी अनुभवों और सूचनाओं के प्रचार प्रसार में मदद मिलती है।

इनकी कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

पुस्तकालय/प्रलेखन केंद्र

पुस्तकालय

संस्थान के पुस्तकालय में शैक्षिक योजना, प्रशासन और अंतरशास्त्रीय विषयों से संबंधित पुस्तकों का बहुत बढ़िया संग्रह है। यह पुस्तकालय वर्षों से शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों, विद्वानों, छात्रों और प्रशिक्षणार्थियों को किसी प्रकार की विघ्न बाधा के बगैर पुस्तकालय और प्रलेखन सेवाएं मुहैया कर रहा है। पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र भौतिक सुविधाओं से पूर्णतः सुसज्जित हैं तथा अध्ययन के लिए बढ़िया वातावरण भी उपलब्ध है।

वर्ष 1990-91 के दौरान 912 पुस्तकों के अलावा विभिन्न प्रलेख भी संग्रहीत किए गए। यू. एन. ओ., यूनेस्को, ओ. इ. सी. डी., आइ. एल. ओ., यूनीसेफ आदि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों की रिपोर्टों के समृद्ध संग्रह के अलावा वर्तमान में पुस्तकालय में कुल 44,578 पुस्तकें हैं।

जर्नल

पुस्तकालय में शैक्षिक योजना, प्रशासन, प्रबंध तथा अन्य सहायक क्षेत्रों से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुल 350 जर्नल आते हैं। इनमें प्रकाशित महत्वपूर्ण आलेखों का सूचीकरण किया जाता है। इस वर्ष इन जर्नलों से 2001 आलेखों को सूचीबद्ध किया गया।

समाचार पत्रों की कतरनें

पुस्तकों और जर्नलों के अलावा समाचारपत्रों में शैक्षिक योजना और प्रशासन से संबंधित प्रकाशित आलेखों/समाचारों के कतरनों का भी पुस्तकालय में संग्रह किया जाता है। वर्तमान में पुस्तकालय में 150 विषयों के कतरनों की फाइलें मौजूद हैं।

अमुद्रित सामग्री

वर्ष 1986 में पुस्तकालय को आधुनिक बनाने और बहु-माध्यमीय संचार केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से वीडियो कैसेट, आडियो कैसेट, फिल्में, माइक्रो फिल्में मंगाई जा रही हैं। इस वर्ष के दौरान 1 वीडियो कैसेट और 10 माइक्रो फिल्मों का संग्रह किया गया। पुस्तकालय के वर्तमान संग्रह में 6 फिल्में, 34 वीडियो कैसेट, 80 आडियो कैसेट, 54 माइक्रो फिल्में और 58 माइक्रोफिचेज हैं।

1990-91

पुस्तकों का वितरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के भागीदारों, संकाय तथा अन्य संस्थाओं को अंतर-पुस्तकालय ऋण के तहत कुल 61019 दस्तावेज जारी किए गए। पुस्तकालय में शोधार्थियों ने 91, 810 दस्तावेजों का उपयोग किया।

समसामयिक जानकारी सेवा

शैक्षिक जर्नल : प्राप्त शीर्षक और उनकी विषय वस्तु

पाठकों को शैक्षिक जर्नलों की विषय वस्तु की समसामयिक जानकारी देने के उद्देश्य से एक पक्ष में प्राप्त सभी जर्नलों पर आधारित 'शैक्षिक जर्नल : शीर्षक और उनकी विषयवस्तु' नाम से पुस्तकालय ने नियमित रूप से पाक्षिक मिमियोग्राफ निकाले।

नीपा पुस्तकालय प्राप्तियां

प्रलेखों, नई पुस्तकों और रुचिकर आलेखों से पाठकों को नियमित रूप से अवगत कराने के लिए पुस्तकालय में शामिल किए गए नए दस्तावेजों, पुस्तकों और आलेखों की संगणकीकृत मासिक सूची भी तैयार की गई।

चुनी हुई सूचनाओं का प्रचार-प्रसार

पुस्तकालय ने विभिन्न स्रोतों से प्राप्त नई सूचनाओं का संस्थान की अकादमिक एककों और अनुसंधान परियोजना दलों में प्रचार-प्रसार किया। उन्होंने अपनी रुचि के अनुरूप उन सूचनाओं का इस्तेमाल किया।

संदर्भ सूची

समीक्षाधीन वर्ष में संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए पुस्तकालय ने संदर्भ सूचियां तैयार कीं।

क्षेत्रीय सूचनाओं की पुनः प्राप्ति

बैंकाक स्थित यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रकाशित जर्नल "एशिया और प्रशांत में शिक्षा; समीक्षाएं, रिपोर्टें और टिप्पणियां" में पुस्कालय ने "एशियाई प्रलेखों की टिप्पणियां" शीर्षक से भारतीय प्रलेखों की विषयवस्तु-सारांश प्रस्तुत किया।

नीपा प्रलेखन सेवाएं

शैक्षिक नीति, योजना, प्रशासन और प्रबंध के क्षेत्र में कार्यरत, व्यक्तियों और विद्वानों दोनों के लिए नीपा प्रलेखन केंद्र में समसामयिक जानकारी सेवा की एक शृंखला तैयार की गई है। इस शृंखला के तहत संदर्भ सूचियां, पुस्तक समीक्षाएं, अनुसंधान अध्ययन और राज्यों की रिपोर्टें इत्यादि तैयार करने का प्रस्ताव है।

इसका पहला अंक इस वर्ष निकाला गया जो कि कार्मिक विकास पर केंद्रित था। इसका दूसरा अंक 'शिक्षा पर जे.पी. नायक' पर आधारित है। इसमें जे.पी. नायक की पुस्तकें और आलेखों का विषय-सारांश प्रस्तुत किया गया है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

सूचना संसाधन और पुनः प्राप्ति के महत्व और जरूरत को देखते हुए नीपा पुस्तकालय ने अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय और सूचना परामर्श केंद्र के सहयोग से 'सूचना पुनः प्राप्ति में सूचीकरण और सारांशीकरण की भूमिका' विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें विभिन्न राज्यों और संघीय राज्यों से कुल 28 पुस्तकालयाध्यक्ष शामिल हुए।

प्रलेखन केंद्र

संस्थान के कार्यक्रमों के लिए प्रभावी सूचना आधार विशेषकर राज्यों और संघीय राज्यों की जरूरतों से संबंधित सूचना

1990-91

आधार प्रदान करने के लिए, प्रलेखन केंद्र शैक्षिक योजना और प्रशासन और शिक्षा संबंधी दस्तावेजों का संग्रह करता है। ये दस्तावेज प्रायः राज्यों/संघीय राज्यों के शिक्षा विभागों, जिला प्राधिकरणों तथा प्रादेशिक स्तर के संस्थानों द्वारा प्रकाशित होते हैं। केंद्र का प्रमुख कार्य जिला स्तर तक की सूचनाओं का संग्रह करना और उनका प्रचार-प्रसार करना है ताकि संस्थान सूचनाओं और दस्तावेजों को शुद्ध रूप से प्रतिपादित करने में सक्षम हो सके।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रलेखन केंद्र में 1000 दस्तावेज़ शामिल किए गए। केंद्र के पास 12000 दस्तावेज़ हैं। इनमें मुख्य दस्तावेज़ निम्न हैं : राज्य गजट, राज्य जनगणना हैंडबुक, शैक्षिक सर्वेक्षण, राज्य शैक्षिक योजना, पंचवर्षीय योजना, बजट, राज्य विश्वविद्यालय पुस्तिका, आधारभूत संदर्भ ग्रंथ और संदर्भ ग्रंथ सूची, प्रेस कतरनें, राज्य शैक्षिक संहिता अधिनियम, नियम और विनियम, प्रौद्योगिक आर्थिक और प्रतिदर्श सर्वेक्षण, जिला गजट, जिला जनगणना पुस्तिका, वार्षिक योजना, शैक्षिक योजना, जिला क्रय योजना, लीड बैंक रिपोर्ट, जिला प्रतिदर्श सर्वेक्षण, जिला शैक्षिक सर्वेक्षण, जिला सांख्यिकी पुस्तिका, ग्राम और प्रखंड स्तरीय योजना तथा अध्ययन, अनुसंधान और परियोजना अध्ययन, संसाधन सूची अध्ययन, प्रौद्योगिक–आर्थिक सर्वेक्षण। शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में नवाचारी अनुभवों से संबंधित सूचनाओं का प्रसार प्रलेखन केंद्र निम्नांकित माध्यमों से करता है :

(1) शोधकर्ताओं तथा संकाय के सदस्यों के लिए चयनित सूचना प्रसार सेवा (च. सू. प्र.से.),

(2) मासिक 'भारत में शिक्षा' और प्रेस कतरन सेवा,

(3) प्रलेखन सूची,

(4) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए संदर्भ ग्रंथों का संकलन

प्रकाशन

संस्थान की विभिन्न रिपोर्टों आदि के प्रकाशन में जरूरी सभी सुविधाएं प्रकाशन एकक प्रदान करता है। इसके अलावा एक मुख्य पत्राचार सूची की मदद से विभिन्न संस्थानों और संगठनों में प्रकाशित सामग्रियों का प्रचार-प्रसार भी प्रकाशन एकक ही करता है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नांकित प्रकाशन निकाले गए :

विद्यालय शिक्षा और ग्रामीण रूपांतरण–मुनिस रज़ा और एच. रामचंद्रन (मूल्य : 100 रुपए, विकास पब्लिशिंग हाउस)

शिक्षा अनिवार्य रूप से अन्य सामाजिक-आर्थिक पक्षों से संबद्ध है। यह एक व्यापक प्रणाली की उपप्रणाली है जो एक दूसरे पर परस्पर निर्भर है।

शिक्षा सामाजिक विकास का अभिकरण और उत्पाद दोनों ही है। आमतौर पर विकासशील समाजों में औपचारिक शिक्षा के व्यय को वास्तविक व्यय माना जाता है और इसमें काफी रियायत दी जाती है। पिछले दो दशकों में इस क्षेत्र में अनुसंधान की अभिरुचि में काफी वृद्धि हुई है। इस पुस्तक में विभिन्न समुदायों और सामाजिक समूहों के सापेक्ष विकास के विविध पक्षों पर औपचारिक शिक्षा के प्रभाव को तलाशने का प्रयास किया गया है।

यह पुस्तक एक अनुसंधान परियोजना पर आधारित है। इसमें एक पिछड़े जिले के व्यापक प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आंकड़ों (30,000 परिवारों) का उपयोग किया गया है। यह शिक्षा और मानव संसाधन विकास के बीच के संबंध की शिनाख्त करने का एक अग्रणी प्रयास है।

यह पुस्तक निम्न आठ अध्यायों में विभाजित है : (1)

1990-91

सैद्धांतिक ढांचा, (2) अध्ययन क्षेत्र, आंकड़ा आधार, और प्रविधि; (3) विशेषीकरण और विद्यालयी शिक्षा : परंपरागत असमानताएं; (4) पीढ़ी-दर-पीढ़ी विद्यालयी शिक्षा : विकास और समता; (5) विद्यालयी शिक्षा और जनसांख्यिकीय व्यवहार; (6) विद्यालयी शिक्षा और कृषि का आधुनिकीकरण; (7) विद्यालय शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता और (8) अंतःदृष्टि और निष्कर्ष

शैक्षिक योजनाकारों के लिए पर्यावरण शिक्षा हस्तपुस्तिका- सत्यभूषण, आर. गोविंद और ए. मंगलागिरि (मूल्य रहित)

पर्यावरण शिक्षा की छोटी और लंबी अवधि की योजना, आधारभूत स्तर पर व्यक्तिगत भूमिका प्रबंध प्रणाली और पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के लिए संबंधित संचारेक्षण और मूल्यांकन प्रणाली को प्रकाश में लाते हुए इस पुस्तक में पर्यावरण शिक्षा की व्यापक नीति प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया है। इस पुस्तक की विषय वस्तु शैक्षिक योजनाकारों को इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए एक व्यापक रूप रेखा प्रदान करती है। इसमें उन दिशाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है जिनमें कोई भी व्यक्ति पर्यावरण शिक्षा की भावी प्रभावी प्रणाली निर्मित करने के लिए आगे आ सकता है। पर्यावरण शिक्षा की चालू गतिविधियों को मजबूत बनाने में भी शैक्षिक योजनाकारों को इस पुस्तिका से मदद मिल सकती है। समुचित संशोधन और कार्यान्वियन के द्वारा पर्यावरण शिक्षा को समेकित करने के लिए वर्तमान शैक्षिक प्रबंधों की पुनर्गठित करने में यह पुस्तक मार्गदर्शिका का कार्य करती है। यह दिखाई पड़ता है कि यह पुस्तिका यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के तहत निकाली गई प्रकाशन शृंखला में एक सहायक पुस्तिका सिद्ध होगी।

भारत में विद्यालय शिक्षा : क्षेत्रीय आयाम – मुनिस रज़ा, ए. अहमद और शील चंद नुना (मूल्य रहित)

भारत में व्यष्टिस्तरीय योजना के प्रयोग कार्य से संबद्ध शैक्षिक योजनाकारों के लिए प्रमाणित सामग्री की जरूरत की पूर्ति में यह पुस्तक एक संदर्भ ग्रंथ के रूप में उपयोग में लाई जा सकती है। इस पुस्तक के तथ्य ऐच्छिक पथ-प्रेक्षेपित शैक्षिक विकास के स्वरूप के अनुरूप हैं। विद्यालय प्रणाली की प्रभाविता के लिए आवश्यक शर्त समुचित आयुवर्ग के बच्चों के लिए विद्यालय की उपलब्धता के साथ-साथ भौगोलिक उपगमता से संबंधित है। इस आवश्यक शर्त की पूर्ति के आधार पर कोई भी पर्याप्त शर्तों की पहचान की ओर बढ़ जाता है। प्रणाली के मात्रात्मक विस्तार और उसमें गुणवत्ता सुधार, दोनों को ही बराबर का महत्व देना चाहिए। चूंकि अनुसूचित जाति /गैर अनुसूचित जाति, नगरीय/ग्रामीण और पुरुष/महिला के सापेक्ष विद्यालय शिक्षा में बहुत अधिक असमानताएं हैं। इनसे सिर्फ पिछड़ा वर्ग ही कमजोर नहीं हो रहा है बल्कि यह पूरी प्रणाली को ही खा रहा है। अतः प्रणाली को स्वस्थ बनाने के लिए समता के पथ- प्रक्षेपकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी बहु-स्तरीय प्रणाली का छात्र संक्रमण शैक्षिक पिरामिड के निम्न स्तर से उच्चतम स्तर की ओर होता है। अतः इसमें स्वीकृत नियामक प्रतिदर्श के संदर्भ में नियमन किया जाना चाहिए। इस मामले में क्षैतिज अंतरसंबद्धता का होना एक महत्वपूर्ण पथ-प्रक्षेपक को व्यक्त करता है। अंत में कुछ हद तक महत्वपूर्ण दृष्टि से विद्यालय शिक्षा से केवल 'अच्छा' उत्पाद होना ही काफी नहीं है बल्कि इसका एक पथ-प्रक्षेपक 'उपयोगी' नागरिक बनाना होना चाहिए। ज्ञान के संसार और कार्य के संसार के बीच की खाई को पाट कर ही इस पथ-प्रक्षेपक को कार्यरूप दिया जा सकता है। इससे कार्यबल में विद्यालय निर्गत आगत भी बन जाता है।

भूमिका और निष्कर्ष के अलावा यह पुस्तक सात खंडों में विभाजित है। प्रत्येक खंड में निम्नांकित अंग हैं :

(1) पाठ्य सामग्री के साथ-साथ मानचित्र से भी क्षेत्रीय प्रतिमानों की व्याख्या की गई है जिसमें उस दिशा की ओर संकेत भी जिसमें क्षेत्रीय ढांचे की तलाश की जा सकती है,

1990-91

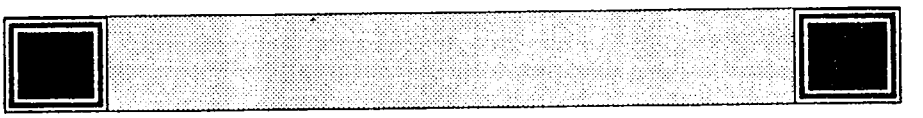

(2) प्रत्येक पथ-प्रक्षेपक के चयनित संकेतकों के क्षेत्रीय मानदंडों को चित्रित करनेवाले मानचित्रों का एक समुच्चय,

(3) चुने गए चरों के विश्लेषण के लिए विकसित वर्गीकरण के पदों में विभिन्न वर्ग के विभिन्न जिलों के बारंबारता की परिशिष्टियां।

संदर्भ ग्रंथ सूची और पूर्व सूची परिशिष्ट में दी गई हैं।

शिक्षा मंत्रालय : संगठनात्मक इतिहास – ए. मैथ्यू (मूल्य रहित)

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जिसे अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जानते हैं, संगठनात्मक और प्रशासनात्मक दृष्टि से भारत में शैक्षिक कार्यक्रम का एक शीर्ष है। परामर्शकारी और सलाहकारी निकायों, स्वायत्त संगठनों तथा राष्ट्रीय स्तर के व्यावसायिक मंचों से पूरी तरह लैस होने के बावजूद इसका बहुत अधिक महत्व है। शिक्षा नीति के प्रतिपादन और विभिन्न स्तरों तथा परिधियों में शैक्षिक विकास के लिए राज्य सरकारों को प्रेरित करने में इसकी अग्रणी भूमिका होती है। यह प्रकाशन 'शिक्षा मंत्रालय : संगठनात्मक इतिहास' इसके दो पक्षों पर प्रकाश डालता है। इसमें एक तरफ शैक्षिक विकास में इसकी भूमिका की पड़ताल की गई है तो दूसरी तरफ विकास प्रक्रिया के तहत इसके स्वयं के रूपांतरण और संगठनात्मक संवृद्धि पर भी प्रकाश डाला गया है।

यह पुस्तक नौ अध्यायों में विभक्त है। इनमें ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा की ढुलमुल नीति, विद्यालय शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा जैसे राज्य सरकार के मामलों में शिक्षामंत्रालय की अवधारणात्मक नेतृत्वकारी भूमिका और केंद्रीय सूची के मामलों, जैसे– उच्च शिक्षा और अनुसंधान या तकनीकी शिक्षा में अवमूल्यन तथा मार्गदर्शन से संबंधी उसकी व्यावसायिक भूमिका के हस्तगन के सिद्धांत पर गहराई के साथ प्रकाश डाला गया है। समवर्ती सूची के मामलों, जैसे-भौतिक शिक्षा, खेल-कूद, संस्कृति और युवा सेवाओं में मंत्रालय की भागीदारी में सहयोग, समन्वयन और प्रगति तथा परस्पर संबंध ही प्रमुख समायोजक माध्यम हैं। भागीदारी के इन विभिन्न माध्यमों के विकास और साथ ही सांगठनिक विकास से ही मंत्रालय की भूमिका के दृष्टिकोण और कार्यनिष्पादन की भूमिका के अनोखे स्वरूप का पता चलता है।

महिला और विकास –शील चंद नुना (मूल्य रहित)

यह रिपोर्ट जिला स्तर के आंकड़े पर आधारित है। इसमें शिक्षा के विविध पक्षों, जनसांख्यिकी, वैवाहिकता, प्रजननता, स्वास्थ्य, आर्थिक गतिविधियां, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, पीने के साफ पानी की उपलब्धता और राजनीतिक भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण पक्षों को समाहित किया गया है।

इस रिपोर्ट के मुख्यतः तीन भाग हैं। प्रथम भाग में एक तरफ महिला विकास के सामान्य स्वरूप को प्रस्तुत किया गया है तो दूसरी तरफ महिला विकास के विविध पक्षों के साथ दूसरे पक्षों के परस्पर संबंधों को दर्शाया गया है। दूसरे भाग में महिला विकास के विविध पक्षों से संबंधित आरेख और मानचित्र हैं। तीसरे भाग में दुनिया के चुने हुए देशों के लिए विविध संकेतकों पर आधारित आंकड़ों के सेट प्रदर्शित किए गए हैं। इस भाग में भारत के राज्यों और सभी जिलों के आंकड़े भी शामिल किए गए हैं।

इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष निम्न हैं :

(1) इस रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि यद्यपि महिला विकास के क्षेत्र में देश ने काफी तरक्की की है फिर भी इसे इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करना है। भारत में महिला विकास के स्तरों में व्याप्त क्षेत्रीय असमानताओं के संदर्भ में इस क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

1990-91

(2) इस पुस्तक में महिला विकास के विविध आयाम परस्पर निर्भरता प्रणाली के तहत अंतःसंबंधित हैं। इसमें सह-संबंध का प्रयोग किया गया है जिससे संकेत मिलता है कि शिक्षा, विवाह, स्वास्थ्य, जन्म, मृत्यु सभी एक समान ढांचे में परस्पर गुथे हुए हैं। अतः महिला और विकास के क्षेत्र में किसी भी प्रयास में एक समेकित प्रणाली अपनाई जानी चाहिए।

(3) भारत में महिला समाज कल्याण के स्तरों को मापने के लिए इस अध्ययन में एक संयुक्त सूची विकसित की गई है जिसमें 26 संकेतकों को शामिल किया गया है।

(4) 5 राज्यों के 144 जिलों में से 122 पिछड़े जिले हैं। ये राज्य हैं—आंध्रप्रदेश (15), बिहार (28), मध्यप्रदेश (26), राजस्थान (24) और उत्तर प्रदेश (29) सर्वाधिक पिछड़े जिले हैं— निजामाबाद (आंध्र प्रदेश), सीवान (बिहार), ओर जैसलमेर (राजस्थान)।

(5) वरीयता प्रणाली के अंतर्गत महिला विकास के लिए इन पिछड़े जिलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नई योजना बनाते समय आधारभूत स्तरों पर सामाजिक-आर्थिक यथार्थ को मद्दे नजर रखना चाहिए।

भारत में शिक्षा का विकास 1988-90 : भारत की राष्ट्रीय रिपोर्ट (42वां अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, जेनेवा, 1990 में प्रस्तुत रिपोर्ट)

सबके लिए शिक्षा पर आयोजित सम्मेलन के लिए आधार सामग्री, उत्तरप्रदेश (6-9 नवंबर, 1990 को आयोजित)

जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन

निम्नांकित विषयों पर विशेषांक प्रकाशित किए गए

(1) तीसरी दुनिया में शिक्षा की योजना और प्रबंध : संपादन— के. जी. विरमानी और शील चंद नुना

(2) शैक्षिक योजना प्रशासन : संपादन—एन.एम. भागिया

(3) कामकाजी बच्चों की शिक्षा : संपादन—नलिनी जुनेजा

(4) दूरवर्ती शिक्षा : संपादन — एम. मुखोपाध्याय (हिंदी अनुवाद)

(5) तीसरी दुनिया में शिक्षा की योजना और प्रबंध : संपादन—के. जी. विरमानी और शील चंद नुना (हिंदी अनुवाद)

मिमियोग्राफ प्रकाशन

संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रिपोर्टों और अनुसंधान अध्ययनों के मिमियोग्राफ भी प्रकाशित किए गए।

1990-91

अध्याय 6

प्रशासन और वित्त

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार (शिक्षा विभाग) द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्था है। संस्थान के प्रमुख प्राधिकरण निम्न हैं :

(अ) अध्यक्ष
(ब) उपाध्यक्ष
(स) परिषद
(द) कार्यकारिणी समिति
(य) वित्त समिति
(र) योजना और कार्यक्रम समिति*

* नीपा की समीक्षा के लिए गठित समीक्षा समिति की संस्तुतियों और उसके बाद सर्वोच्च समिति के निर्णयों के अनुसार योजना और कार्यक्रम समिति को भी संस्थान का एक प्राधिकरण बना दिया गया है।

निदेशक संस्थान का प्रधान कार्यकारी अधिकारी होता है। उसकी नियुक्ति भारत सरकार करती है। प्रशासन, वित्त, प्रशिक्षण और अनुसंधान संबंधी मामलों में निदेशक की मदद के लिए कार्यकारी निदेशक होता है। इसे अब संयुक्त निदेशक का पदनाम दिया गया है। नीपा परिषद, वित्त समिति तथा योजना और कार्यक्रम समिति में संस्थान का कुलसचिव सचिव होता है।

परिषद

संस्थान का शीर्ष निकाय परिषद है। इसका प्रमुख अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार करती है। नीपा का निदेशक इसका उपाध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर की शिक्षा प्रणाली के सर्वोच्च अधिकारी और विख्यात शिक्षाविद् इसके सदस्य होते हैं। अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार के चार सचिव (शिक्षा, वित्त, कार्मिक और योजना आयोग), निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के छः शिक्षा सचिवों और छः निदेशकों, छः प्रसिद्ध शिक्षाविदों, कार्यकारी समिति के सभी सदस्यों तथा नीपा संकाय के एक सदस्य से नीपा परिषद का गठन होता है। समीक्षा समिति की संस्तुतियों के आधार पर नीपा संकाय के एक सदस्य के बदले अब तीन सदस्यों को परिषद में शामिल किया जाएगा। संस्थान का कुलसचिव परिषद का सचिव होता है।

संस्थान के सभी कार्यों का सामान्य पर्यवेक्षण तथा उद्देश्यों की प्राप्ति परिषद के प्रमुख कार्य हैं।

परिशिष्ट-I में 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार परिषद के सभी सदस्यों की सूची दी गई है।

कार्यकारिणी समिति

संस्थान का निदेशक कार्यकारिणी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग), वित्त और योजना आयोग के सचिवों द्वारा नामित व्यक्ति, एक राज्य का शिक्षा सचिव, एक प्रसिद्ध शिक्षाविद् और नीपा का कार्यकारी निदेशक जिसे अब संयुक्त निदेशक का पदनाम दिया गया है, इसके सदस्य होते हैं। समीक्षा समिति की संस्तुतियों और सर्वोच्च समिति के निर्णयों में कार्यकारिणी समिति को सुदृढ़ करने के लिए निम्न को शामिल करने का

प्रस्ताव रखा गया है— (1) राज्य सरकार का एक निदेशक और शैक्षिक योजना और प्रबंध के क्षेत्र में सक्रिय रूप से संबद्ध राज्य शिक्षा संस्थान का एक निदेशक,

(2) नीपा के निदेशक की मदद के लिए परिषद के संकाय के तीन सदस्यों में से दो सदस्य और नीपा के मामलों के प्रबंध में संकाय की भागीदारी।

नीपा का कुलसचिव कार्यकारिणी समिति का सचिव होता है।

परिषद के वित्तीय और अन्य मामलों के प्रबंध का उत्तर-दायित्व कार्यकारिणी समिति पर होता है। यह परिषद के सभी अधिकारों का उपयोग भी कर सकती है।

परिशिष्ट-II में 31 मार्च, 1991 की स्थिति के आधार पर कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सूची दी गई है।

वित्त समिति

वित्त समिति का गठन अध्यक्ष करता है। संस्थान के निदेशक की पदेन अध्यक्षता में इसमें 5 सदस्य होते हैं। जिनमें वित्त सलाहकार तथा अध्यक्ष द्वारा नामित परिषद के सदस्य शामिल होते हैं। नीपा का कुलसचिव इसका सचिव होता है।

वित्त समिति लेखा तथा बजट निर्धारण की जांच-पड़ताल करती है और नए व्यय तथा वित्त संबंधी अन्य मामलों के प्रस्तावों की सिफारिश करती है।

परिशिष्ट-III में 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार वित्त समिति के सदस्यों की सूची दी गई है।

कार्यक्रम सलाहकार समिति

अब कार्यक्रम सलाहकार समिति को योजना और कार्यक्रम समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति में नीपा का निदेशक पदेन अध्यक्ष होता है। इसके अन्य सदस्य हैं— मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग), योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के प्रतिनिधि और जनशिक्षा निदेशालय के निदेशक, राज्य के शिक्षा सचिव, शिक्षाविद् और नीपा के कार्यकारी निदेशक जिसे अब संयुक्त निदेशक का पदनाम दिया गया है, नीपा संकाय के दो सदस्य और कार्यकारिणी समिति द्वारा नामित अन्य सदस्य। नीपा के कुलसचिव इस समिति का सचिव होता है। नई योजना और कार्यक्रम समिति का गठन किया जा रहा है।

परिशिष्ट-IV में 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची दी गई है।

संगठनात्मक ढांचा

अकादमिक एककें

संस्थान के संकाय को निम्नांकित 8 अकादमिक एककों में गठित किया गया है :

शैक्षिक योजना

शैक्षिक प्रशासन

शैक्षिक वित्त

शैक्षिक नीति

विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा

उच्च शिक्षा

प्रादेशिक प्रणाली

अंतर्राष्ट्रीय

1990-91

शैक्षिक नीति एकक को छोड़कर सभी अकादमिक एककों के अध्यक्ष वरिष्ठ अध्येता हैं। शैक्षिक नीति एकक का अध्यक्ष अध्येता है।

संस्थान की नीतियों और अनुदान की उपलब्धता के अनुसार सभी अकादमिक एककों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विकास तथा विभिन्न प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए पूरी जिम्मेदारी से कार्य करें तथा अपने क्षेत्र में परामर्शकारी तथा सलाहकारी सेवाएं प्रदान करें।

कृतिक बल और समितियां

विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए समय-समय पर निदेशक विशेष कार्यबल तथा समितियों का गठन करता है।

अनुसंधान परियोजनाओं पर सलाह देने और उनकी प्रगति का संचारेक्षण करने के लिए विशेषज्ञों की एक परियोजना सलाहकार समितियां गठित की जाती हैं।

अध्ययन सहायता योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों पर निर्णय करने के लिए एक अनुसंधान अध्ययन सलाहकार परिषद होती है। नीपा का निदेशक इसका अध्यक्ष होता है। अकादमिक एककों के अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। नीपा का कुलसचिव इसका सचिव सदस्य होता है।

अधिरचनात्मक समर्धन सेवा

संस्थान के बहुमुखी कार्यक्रमों, अनुसंधान तथा अन्य अकादमिक गतिविधियों के विकास में संस्थान के पुस्तकालय, प्रलेखन केंद्र, प्रकाशन एकक, संगणक केंद्र, हिंदी कक्ष और मानचित्रण कक्ष एक मजबूत आधार तथा समर्थनकारी सेवाएं प्रदान करते हैं।

अध्याय 5 में प्रकाशन, पुस्तकालय तथा प्रलेखन सेवाओं के विस्तृत ब्योरे दिए गए हैं।

संगणक केंद्र

संगणक केंद्र में 4 आइ.बी.एम. विप्रो पी.सी.-ए.टी. हैं। प्रत्येक में 1 एम.बी.आर.ए.एम. 40 एम.बी. हार्ड डिस्क और 1.2 एम.बी. के 5.25" के फ्लापी ड्राइव हैं। उपर्युक्त 4 पी.सी. /ए.टी. में से 3 का प्रयोग संस्थान के अनुसंधान और प्रशिक्षण गतिविधियों से संबंधित आंकड़ों के संसाधन में किया जाता है। एक का प्रयोग डेस्क टॉप पब्लिशिंग के लिए किया जाता है। इसमें एक लेजर प्रिंटर (QMS PS 810) हैं। उसकी गति 8 पृष्ठ प्रति मिनट है। डी.टी.पी. प्रणाली में वेंतुरा पब्लिशिंग साफ्टवेअर लगा है। इससे संस्थान की सभी प्रकाशन सामग्री, वार्षिक रिपोर्ट और जर्नल का कार्य किया जाता है। इसके अलावा केंद्र में 10 पी.सी. -एक्स.टी. है। प्रत्येक में 640 के. बी. आर. ए. एम., 20 एम.बी. हार्ड डिस्क और दो 360 के. बी. फ्लापी ड्राइव है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अभ्यास के लिए इनका उपयोग किया जाता है।

केंद्र में एक एच.सी.एल/ए.टी. 386 और दो पी.सी. एक्स. टी., जिनमें एक विप्रो का और दूसरा ब्लू स्टार का है। इसमें 640 के.बी.आर.ए.एम. 20 एम.बी. हार्ड डिस्क हैं। 1.2 एम.बी. तथा 1.4 एम.बी. संग्रह क्षमता के 5.25" और 3.5" के दो फ्लापी ड्राइव हैं। संगणक केंद्र में एक एच.सी. एल. पी.सी-ए.टी. 386 भी है।

इसके अलावा संगणक केंद्र में पी.सी. आधारित नवीनतम साफ्टवेअर जैसे लोटस 1-2-3 (Rel. 3), डीबेस IV, SPSS Pct (Ver. 3) और वर्ड स्टार (Rel-6) भी हैं। कार्यक्रम संसाधन के लिए हमारे पास कोबोल, फोर्टान और पास्कल के भाषा संकलनकर्त्ता हैं।

1990-91

मानचित्रण कक्ष

मानचित्रण कक्ष अनुसंधान और प्रशिक्षण में मानचित्रण की प्रस्तुति संबंधी सुविधाएं प्रदान करता है। विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधी चित्रलेखों आंकड़ों और सूचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रस्तुतीकरण की नई विधियों से आरेख, ग्राफ, चार्ट, तालिकाएं, पारदर्शियां बनाई गईं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान केंद्र के महत्वपूर्ण कार्य निम्न थे—द्वितीय अखिल भारतीय सर्वेक्षण परियोजना सबके लिए शिक्षा—ग्राफीय प्रस्तुतीकरण के लिए विभिन्न राज्यों के संगठनात्मक ढांचे की तैयारी, विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित परियोजना, 'सबके लिए शिक्षा—उत्तर प्रदेश' के लिए आरेख, चार्ट, प्रखंड मानचित्र और पारदर्शियां विकसित की गईं।

प्रशासनिक ढांचा

प्रशासन और वित्त प्रभाग को चार अनुभागों तथा दो कक्षों में बांटा गया है। ये अनुभाग तथा कक्ष हैं—अकादमिक प्रशासन, लेखा, कार्मिक प्रशासन, सामान्य प्रशासन तथा प्रशिक्षण कक्ष और समन्वयन कक्ष। अकादमिक प्रशासन और समन्वयन कक्ष प्रत्यक्ष रूप से कुलसचिव के प्रति उत्तरदायी होता है। कार्मिक, सामान्य प्रशासन और प्रशिक्षण कक्ष का पर्यवेक्षण प्रशासनिक अधिकारी करता है। इन सभी का सर्वाधिकारी कुलसचिव होता है। वित्त अनुभाग का पर्यवेक्षण अधिकारी वित्त अधिकारी होता है। दिनांक 31.1.1991 को कुलसचिव के सेवानिवृत्त होने के कारण प्रशासनिक अधिकारी कार्यकारी कुलसचिव का पदभार संभाल रहे हैं।

संवर्ग योजना

31 मार्च, 1991 को संस्थान में संवर्ग संख्या 178 थी।

संवर्ग पद	संख्या
संकाय	35 (20%)
(निदेशक, परामर्शदाता, वरिष्ठ अध्येता, अध्येता और सह-अध्येता)	
अकादमिक सहयोग	24 (14%)
(प्रकाशन अधिकारी, पुस्तकाध्यक्ष, प्रलेखन अधिकारी, कम्प्यूटर प्रोग्रामर हिंदी संपादक, सहायक प्रकाशन अधिकारी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, पुस्तकाध्यक्ष श्रेणी-II , श्रेणी-III, प्रकाशन सहायक, हिंदी अनुवादक और पुस्तकालय सहायक)	

1990-91

संवर्ग पद	संख्या
प्रशासनिक और सचिव स्टाफ	41 (23%)
तकनीकी स्टाफ	33 (19%)
निदेशक के निजी सचिव, वरिष्ठ निजी सहायक, वरिष्ठ आशुलिपिक, मशीन चालक, कनिष्ठ आशुलिपिक, टेलीफोन संचालक, वाहन चालक, संगणक, बिजली मिस्त्री, कार्यक्रम परिचर, पुस्तकालय परिचर, वरिष्ठ तथा कनिष्ठ गेस्टेटनर (परिचालक)	
वर्ग घ (गैर तकनीकी)	45 (26%)
योग	**178**

स्टाफ परिवर्तन

श्री आर. पी. सक्सेना 31 जनवरी, 1991 को सेवानिवृत्ति हुए।

श्री के एल. दुआ ने 5 फरवरी, 1992 को कार्यवाहक कुल सचिव का पदभार संभाला।

डॉ. आरिफ हसन 31 जनवरी, 1991 को सेवामुक्त किए गए।

सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम

सुश्री वाई. जोसफीन, व.त.स. ने पेरिस (फ्रांस) में अं. शै. यो. सं. के शैक्षिक योजना और प्रशासन में उच्च प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। (20.10.89–26.5.1990)

श्री जे. एस. असवाल, क. श्रे. लि. ने दिल्ली प्रिंटर्स एसोसिएशन, प्रिंटर्स भवन, नरायणा नई दिल्ली में डेस्क टॉप पब्लिशिंग के अंशकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया (20 अगस्त 1990–12 अक्तूबर, 1990)

नीपा में आयोजित छः महीने के अंशकालिक हिंदी टंकण प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्रीमती अनिता मोहन, श्रीमती अनिता कपूर, श्री पारस नाथ प्रसाद, श्री बी. आर. पहवा, श्री सतबीर सिंह और श्री चंदर प्रकाश (क. श्रे. लि.) ने भाग लिया। (16 अगस्त, 1990–31 दिसंबर, 1990)

अध्ययन अवकाश

श्री ए. सी. मेहता सह-अध्येता ने अपना पी-एच.डी. शोध कार्य पूरा करने के बाद दिनांक 17-11-1991 को संस्थान में कार्यभार संभाला।

1990-91

श्रीमती नलिनी जुनेजा, सह-अध्येता, नीपा पी-एच.डी. शोधकार्य के लिए दिनांक 17-4-1991 से दो वर्ष के लिए अध्ययन अवकाश पर हैं।

विदेश नियुक्तियां/दौरे

प्रो. सत्यभूषण ने वरिष्ठ प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के इतालियन लोक प्रशासन विद्यालय, कैसरटा, इटली द्वारा 'प्रबंधकों के प्रशिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग' पर आयोजित बैठक में भाग लिया। (17-22 मई, 1990)

प्रो. सत्यभूषण ने अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान, पेरिस में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया। (10-14 दिसंबर, 1990)

डॉ. ब्रह्म प्रकाश, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष, शैक्षिक योजना एकक एशियाई विकास बैंक मनीला में एक दूसरी नियुक्ति पर दिनांक 19-1-1990 को परियोजना अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त हुए।

डॉ. जी.डी. शर्मा, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष, उच्च शिक्षा एकक, ने कैंब्रिज एजुकेशन कांसल्टैंट्स लिमिटेड, इंगलैंड की ओर से यूनेस्को—यू.एन.डी.पी. कार्यक्रम के तहत 'जिला स्तर का बजट और लागत तैयार करना' विषय पर घाना में दिनांक 1.3.1991 से सात सप्ताह तक सलाहकार के रूप में कार्य किया।

डॉ. जी.डी. शर्मा, वरिष्ठ अध्येता व अध्यक्ष, उच्च शिक्षा एकक ने पिट्सबर्ग में 13-22 मार्च, 1991 के दौरान उच्च शिक्षा में अनुसंधान के यूनस्को विशेषज्ञ मंच की बैठक में भाग लिया।

श्री एम.एम. कपूर, वरिष्ठ अध्येता व अध्यक्ष प्रादेशिक प्रणाली एकक ने यूनेस्को द्वारा पेरिस में 'शिक्षा के संकेतक' विषय पर दिनांक 31.1.1991 से 6.2.1991 तक आयोजित बैठक में भाग लिया।

डॉ. आर. गोविंद, वरिष्ठ अध्येता व अध्यक्ष, विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा एकक ने सहयोगी अनुसंधान परियोजना—'बेसिक शिक्षा सेवा की गुणवत्ता' के सिलसिले में दिनांक 8.2.1991 से 7.4.1991 तक अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान, पेरिस में आवासीय अध्येता का कार्यभार संभाला।

डॉ. जया इंदिरेसन, वरिष्ठ अध्येता, उच्च शिक्षा एकक ने सिओल, कोरिया में 'शैक्षिक योजना और प्रबंध में नई प्रशिक्षण रणनीतियां', विषय पर आयोजित पी. आर.ओ.ए.पी. -के.इ.डी.आई. क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया। (3-8 दिसंबर, 1990)

डॉ. (श्रीमती) कुसुम के.प्रेमी, अध्येता व अध्यक्ष, शैक्षिक नीति एकक ने पेरिस में दिनांक 15.10.1990 से 14.2.1991 तक अं.शै.यो.सं. के मानद अध्येता कार्यक्रम में भाग लिया।

डॉ. एन.वी. वर्गीस, अध्येता, ने अं.शै.यो.सं.—पी.आर.ओ.ए.पी. द्वारा शिक्षा, रोजगार और मानव संसाधन विकास पर बैंकाक में आयोजित कार्यशाला में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया। (12-26 जून, 1990)

सुश्री अनिता चोपड़ा, कोप परियोजना ने कोलंबो, श्रीलंका में आइ.एन.टी.इ.सी द्वारा विकेंद्रीकृत प्रशासन के लिए सूचना प्रणाली विषय पर आयोजित कार्यशाला में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया। (2-7 सितंबर, 1990)

परिसर सुविधाएं

संस्थान का कार्यालय चार मंजिला इमारत में है। इसका अतिथि गृह सात मंजिला है जिसमें 48 कमरे हैं। ये पूर्णतः

1990-91

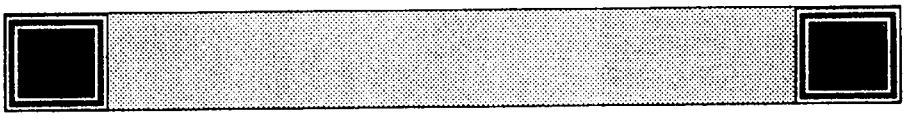

सुसज्जित हैं। प्रत्येक कमरे में शौच वगैरह जुड़ा है। एक आवासीय परिसर भी है। इसमें टाइप-I के 16, टाइप II, III और V के आठ-आठ क्वार्टर हैं। एक निदेशक आवास है। टाइप IV के आठ क्वार्टरों का निर्माण कार्य जल्दी ही पूरा होने वाला है।

हमारी संशोधित योजनाओं पर दिल्ली नगर निगम की मंजूरी मिलते ही वार्डन, मेहमान संकाय आवास सुविधा और अतिथि गृह में अतिरिक्त प्रखंड का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। संशोधित योजना पहले से ही दिल्ली नगर निगम को पेश कर दी गई हैं।

दिल्ली अग्नि शमन सेवा की सलाह पर अग्नि सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए। इस कार्य में लगभग 9.50 लाख रुपये व्यय होने की संभावना है। ड्राइ राइजर-कम-डाउन कमर, फाइबर ग्लास की पानी टंकियां और अतिथिगृह के लिए सीमेंट और कंकरीट से बनी सड़कें तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के साथ मिलकर 2 लाख लिटर धारिता वाली भूमिगत पानी टंकी आदि का प्रावधान इसमें शामिल है। इसके अलावा डी.जी. सेट, पानी आपूर्ति पंप आदि भी लगाने हैं। इनके लिए कार्य तेजी से चल रहा है और सभी कार्य शीघ्र ही पूरे होने वाले हैं। वर्ष 1990-91 के दौरान अतिथि गृह से रु. 3, 19, 575 की राशि प्राप्त हुई।

द्वितीय तल पर प्रलेखन केंद्र का नवीकरण किया गया और प्रयोक्ताओं की जरूरतों को और अधिक सुगम बनाया गया।

संस्थान में अलग से अपना विद्युत उपकेंद्र स्थापित करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की स्वीकृति से जनवरी, 1991 में कार्यवाही शुरू की गई है।

एन.सी.ई.आर.टी. के वर्तमान उपकेंद्र से नीपा की विद्युत आपूर्ति हो रही है जो कि दोनों संस्थाओं में विद्युत की बढ़ती मांग की पूर्ति करने में अपर्याप्त है।

वित्त

वर्ष 1990-91 के दौरान संस्थान ने 167.56 लाख रुपए (योजनेत्तर के तहत 98.24 लाख रुपए और योजना के तहत 69.32 लाख रुपए) प्राप्त किए जबकि वर्ष 1989-90 के दौरान यह राशि 137.50 लाख रुपये (योजनेत्तर के तहत 80.50 लाख रुपए और योजना के तहत 57.00 लाख रुपए) थी। वर्ष के शुरू में संस्थान के पास 17.44 लाख रुपए (योजनेत्तर के तहत 1.76 लाख रुपए और योजना के तहत 15.68 लाख रुपए) जमा थे। इस वर्ष ऑफिस और अतिथि गृह से 15.65 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई। इस प्रकार इस वर्ष प्राप्त कुल 200.65 लाख रुपए में सरकारी अनुदान से कुल 191.91 लाख रुपए व्यय हुए जबकि वर्ष 1989-90 के दौरान कुल व्यय 144.40 लाख रुपए था।

प्रायोजित कार्यक्रमों और अध्ययनों के लिए वर्ष के शुरू में संस्थान के पास 7.41 लाख रुपए जमा थे और वर्ष 1990-91 के दौरान इसके लिए अन्य अभिकरणों से 63.57 लाख रुपए प्राप्त हुए।

इस वर्ष प्रायोजित कार्यक्रमों और अध्ययनों पर 35.63 लाख रुपए व्यय हुए। प्रायोजित कार्यक्रमों और अध्ययनों के लिए अन्य अभिकरणों से प्राप्त राशि में भारी वृद्धि हुई है। वर्ष 1989-90 में 14.45 लाख रुपए की वृद्धि हुई थी जबकि वर्ष 1990-91 में 63.57 लाख रुपए की वृद्धि हुई है।

वर्ष 1990-91 के दौरान सरकारी अनुदान और प्रायोजित कार्यक्रमों तथा अध्ययन के लिए प्राप्त वित्तीय सहायता से कुल 227.53 लाख रुपए व्यय हुए। वर्ष 1989-90 के दौरान यह राशि मात्र 162.95 लाख रुपए थी।

1990-91

अनुबंध-I

वर्ष 1990-91 में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशिविरों/संगोष्ठियों/सम्मेलनों की सूची

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनांक और अवधि	भागीदारों की संख्या	कार्यक्रम व्यक्ति दिन
1	2	3	4	5
I.	**डिप्लोमा कार्यक्रम**			
	राष्ट्रीय डिप्लोमा (पहले से जारी)			
	*जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में दसवां डिप्लोमा कार्यक्रम (पहले से जारी) (विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा एकक)	1 नवंबर, 1989– 30 अप्रैल, 1990 (30 दिन)	26	780
	चरण-III	2–5 जुलाई, 1990 (4 दिन)	26*	104
1.	जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में ग्यारहवां डिप्लोमा (विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा एकक)	1 नवंबर 1990– 31 जनवरी, 1991 (92 दिन)	12	1104
	चरण-II	1 फरवरी-30 अप्रैल, 1991 (59 दिन)	12*	708
	योग 1	185	38*	2696
	अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम (पहले से जारी) * शैक्षिक योजना और प्रशासन में छठवां अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम (पहले से जारी) चरण-I (अंतर्राष्ट्रीय एकक)	22 जनवरी-21 अप्रैल, 1990 (21 दिन)	17	357

1990-91

1	2	3	4	5
	चरण-II	22 अप्रैल—21 जुलाई, 1990 (91 दिन)	17*	1547
2.	शैक्षिक योजना और प्रशासन में सातवां अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम (अंतर्राष्ट्रीय एकक)	21 जनवरी-20 जुलाई, 1991 (70 दिन)	26	1820
	योग 1	182	43*	3724
II.	**विषयानुसार कार्यक्रम**			
	विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के लिए कार्यक्रम			
3.	विद्यालय प्रधानाध्यापकों के प्रबंधकीय कार्य विश्लेषण पर कार्यशिविर (शै. प्र. एकक)	9-11 अप्रैल, 1990 (3 दिन)	14	42
4.	प्रारंभिक/प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के पद, प्रतिष्ठा और अधिकारों के उन्नयन और उनके प्रशिक्षण की जरूरतों की पहचान विषय पर राष्ट्रीय कार्यशिविर (वि. और अनौ. शि. एकक)	1-4 मई, 1990 (4 दिन)	28	112
5.	शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उदयपुर के विस्तार विभाग और शिक्षा विभाग, उदयपुर प्रभाग के सहयोग से बांसवारा, राजस्थान में माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए सांस्थानिक योजना और मूल्यांकन पर कार्यशिविर (नीति एकक)	20-24 अगस्त, 1990 (5 दिन)	36	180
6.	विद्यालय प्रधानाध्यापकों के कार्यनिष्पादन की सफलता के लिए योगदान देनेवाले महत्वपूर्ण संकेतकों पर कार्यशिविर (अंतर्राष्ट्रीय एकक)	31 दिसंबर, 1990— 4 जनवरी, 1991 (5 दिन)	16	80

1990-91

1	2	3	4	5
7.	आई. पी. सी. एल. वड़ौदा के संस्थानों के प्रमुखों के लिए अध्ययन दौरा कार्यक्रम (शै. प्र. एकक)	4-6 जनवरी, 1991 (3 दिन)	7	21
8.	जिला शिक्षा अधिकारियों की भूमिका और कार्यकलापों पर प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों की बैठक (वि. और अनौ. शि. एकक)	18-20 फरवरी, 1991 (3 दिन)	32	96
	योग 6	23	133	531
9.	जि. शि. प्र. सं. के योजना और प्रबंध विभाग के संकाय के लिए द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रा.प्र. एकक)	20-31 अगस्त, 1990 (12 दिन)	37	444
10.	रा. शै. अ. प्र. प. तथा प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के सहयोग से जि. शि. प्र. सं. के प्राचार्यों के प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (वि. और अनौ. शि. एकक)	21 जनवरी-9 फरवरी, 1991 (20 दिन)	35	700
11.	जि. शि. प्र. सं. के योजना और प्रबंध विभाग के संकाय के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (वि. और अनौ. शि. एकक)	18 फरवरी-2 मार्च, 1991 (13 दिन)	25	325
12.	जि. शि. प्र. सं. के प्राचार्यों के लिए जि. शि. प्र. सं. की योजना और प्रबंध पर पुस्तिका विकसित करने के लिए कार्यशिविर	6-8 जून, 1990 (3 दिन)	20	60
	योग 4	48	117	1529

1990-91

1	2	3	4	5
	विद्यालय शिक्षा की योजना और प्रबंध			
13.	वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासकों के लिए अट्ठारहवां अभिविन्यास कार्यक्रम (प्रा. प्र. एकक)	17 दिसंबर, 1990-4 जनवरी, 1991 (19 दिन)	8	152
14.	उदयपुर जिले, की सांस्थानिक योजना और मूल्यांकन पर कार्यशिविर (शै. नी. एकक)	23-27 अप्रैल, 1990 (5 दिन)	34	170
15.	बेसिक शिक्षा के कार्यान्वयन की योजना पर कार्यशिविर (शै. प्र. एकक)	14-17 मई, 1990 (4 दिन)	7	28
16.	केंद्रीय विद्यालय संगठन और केंद्रीय विद्यालयों के प्राचार्यों के प्रबंध कौशल में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण संकेतकों पर कार्यक्रम (अंतर्राष्ट्रीय एकक)	11-15 जून, 1990 (5 दिन)	24	120
17.	लैब क्षेत्र प्रणाली पर माड्यूल को अंतिम रूप देने के लिए कार्यशिविर (नी. एकक)	18-20 सितंबर, 1990 (3 दिन)	16	48
18.	'सबके लिए शिक्षा—उत्तर प्रदेश' पर संगोष्ठी (वि. और अनौ. शि. एकक)	6-9 नवंबर, 1990 (4 दिन)	68	272
19.	बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता पर विश्लेषण कार्य-शिविर (वि. और अनौ. शि. एकक)	13-15 नवंबर, 1990 (3 दिन)	9	27
	योग 7	43	166	817
	प्र. शि. सा. और व्यष्टि स्तरीय योजना			
20.	नागालैंड सरकार के सहयोग से कोहिमा में नागालैंड के वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों के लिए व्यष्टि स्तर पर शैक्षिक योजना की विकेंद्रीकृत प्रणाली में अभिविन्यास कार्यक्रम (प्रा. प्र. एकक)	4-9 जून, 1990 (6 दिन)	15	90

1990-91

1	2	3	4	5
21.	राज्य स्तर के शिक्षा विभाग में योजना/सांख्यिकी के प्रभारी अधिकारियों के लिए प्र. शि. सा. के लिए प्रतिदर्श, डिजाइन और प्रगति की निगरानी पर कार्यशिविर (प्रा. प्र. एकक)	17-19 सितंबर, 1990 (3 दिन)	13	39
22.	प्रा. शि. सा. के संचारेक्षण पर तकनीकी कार्यशिविर (प्रा. प्र. एकक)	17-19 अक्टूबर, 1990 (3 दिन)	27	81
23.	प्रा. शि. सा. के लक्ष्य की ओर कार्य की प्रगति की निगरानी पर तीसरा तकनीकी कार्यशिविर (प्रा. प्र. एकक)	14-15 दिसंबर, 1990 (2 दिन)	28	56
	योग 4	14	83	266
	विद्यालय मानचित्रण			
24.	पोर्टब्लेयर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए विद्यालय मानचित्रण पर अभिविन्यास कार्यशिविर (प्रा. प्र. एकक)	16-18 जुलाई, 1990 (3 दिन)	10	30
25.	विद्यालय मानचित्रण पर राज्य परियोजना अधिकारियों के लिए तीसरा तकनीकी कार्यशिविर (प्रा. प्र. एकक)	26-28 जुलाई, 1990 (3 दिन)	9	27
	योग 2	6	19	57
	अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा			
26.	सहायक निदेशकों (अनौपचारिक शिक्षा) के लिए हैदराबाद में क्षेत्र आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रा. प्र. एकक)	28-31 मई, 1990 (4 दिन)	30	120

1990-91

1	2	3	4	5
27.	आंध्र प्रदेश के प्रौढ़ शिक्षा के उप निदेशकों का प्रशिक्षण (वि. और अनौ. शि. एकक)	11-15 दिसंबर, 1990 (5 दिन)	20	100
28.	प्रौढ़ शिक्षा की योजना और प्रबंध में अभिविन्यास कार्यक्रम (वि. औ. अनौ. शि. एकक)	4 फरवरी-17 मार्च, 1991 (42 दिन)	40	1680
	योग 3	51	90	1900
	उच्च शिक्षा			
29.	कालेज प्राचार्यों के लिए योजना और प्रबंध में अभिविन्यास कार्यक्रम (उच्च शिक्षा एकक)	5-25 सितंबर 1990 (21 दिन)	36	756
30.	कालेजों के विकास में कालेज विकास परिषदों की भूमिका पर संगोष्ठी सहित कार्यशिविर (उच्च शिक्षा एकक)	2-4 मई, 1990 (3 दिन)	22	66
31.	अकादमिक स्टाफ कालेजों की योजना और प्रबंध पर समीक्षा बैठक (उच्च शिक्षा एकक)	9-10 अगस्त, 1990 (2 दिन)	44	88
32.	चीनी गणराज्य के वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासकों के अध्ययन दौरे के दौरान विश्वविद्यालयों के शैक्षिक प्रशासन में प्रशिक्षण और अनुसंधान (उ. शि. एकक)	18-22 मार्च, 1991 (5 दिन)	4	20
	योग 4	31	106	930
	वित्त प्रबंध			
33.	विश्वविद्यालय वित्त के प्रबंध में अभिविन्यास कार्यक्रम (शै. वि. एकक)	6-12 अक्टूबर, 1990 (5 दिन)	11	55

1	2	3	4	5
34.	लागत विश्लेषण के विशेष संदर्भ में शिक्षा में वित्त प्रबंध में अभिविन्यास कार्यक्रम (शै. वि. एकक)	22-26 अक्टूबर, 1990 (5 दिन)	8	40
	योग 2	10	19	95
	संगणक अनुप्रयोग			
35.	कालेजों में प्रभावी संगणक प्रयोग पर कालेजों के प्राचार्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम	25-29 जून, 1990 (5 दिन)	16	80
36.	कोष क्षेत्रीय कक्ष, भोपाल के मंडल क्षेत्र अधिकारियों के लिए प्रारंभिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम (कोप एकक)	8 अगस्त-10 सितंबर, 1990 (34 दिन)	5	170
37.	शैक्षिक योजना में संगणक अनुप्रयोग : लोटस 1-2-3 पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (शै. यो. एकक)	4-15 मार्च, 1991 (12 दिन)	21	252
	योग 3	51	42	502
	मात्रात्मक तकनीकी			
38.	शैक्षिक योजना की मात्रात्मक तकनीकों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (शै. यो. एकक)	18-29 जून, 1990 (12 दिन)	2	24
	योग 1	12	2	24
	लंबी अवधि की योजना/स्थानीय योजना			
39.	स्थानीय शैक्षिक योजना की प्रणाली पर प्रशिक्षण कार्यशिविर (शै. यो. एकक)	28 मई-1 जून, 1990 (5 दिन)	24	120
40.	शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान की विधि पर राष्ट्रीय संगोष्ठी (प्रा. प्र. एकक)	9-10 अगस्त, 1990 (2 दिन)	24	48

1990-91

1	2	3	4	5
41.	सन् 2000 तक की शिक्षा के दूरगामी संप्रेक्ष्य पर राष्ट्रीय संगोष्ठी (शै. यो. एकक)	26-28 नवंबर, 1990 (3 दिन)	23	69
	योग 3	10	71	237
	रोजगार योजना और व्यावसायिक शिक्षा की योजना			
42.	जिला स्तर पर शिक्षा और रोजगार योजना पर कार्यशिविर (प्रा. प्र. एकक)	11-14 दिसंबर, 1990 (4 दिन)	12	48
43.	जिला स्तर पर माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा के उपरांत समन्वयन रणनीतियां और परस्पर संबंध पर राष्ट्रीय कार्यशिविर (शै. यो. एकक)	20-22 मार्च, 1991 (3 दिन)	7	21
	योग 2	7	19	69
	वंचित वर्गों/विकलांगों/ महिलाओं की शिक्षा की योजना और प्रबंध			
44.	महिला प्रशासकों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में चौथा अभिविन्यास कार्यक्रम (अं. एकक)	7-18 जनवरी, 1991 (12 दिन)	20	240
45.	जिला आदिवासी कल्याण अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (शै. प्र. एकक)	18-22 मार्च, 1991 (5 दिन)	4	20
46.	विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए सुविधाएं जुटाने की योजना के लिए समिश्रित क्षेत्र प्रणाली पर कार्यशिविर (वि. और. अनौ. शि. एकक)	27-28 अगस्त, 1990 (2 दिन)	7	14
	योग 3	19	31	274

1990-91

1	2	3	4	5
अखिल भारतीय सर्वेक्षण				
47.	परियोजना निदेशकों के लिए द्वितीय अखिल भारतीय शैक्षिक प्रशासन सर्वेक्षण पर राष्ट्रीय कार्यशिविर (प्रा. प्र. एकक)	13-15 सितंबर, 1990 (3 दिन)	15	45
48.	परियोजना निदेशकों के लिए द्वितीय अखिल भारतीय शैक्षिक प्रशासन सर्वेक्षण पर राष्ट्रीय समीक्षा कार्यशिविर (प्रा. प्र. एकक)	15-16 अक्टूबर, 1990 (2 दिन)	6	12
	योग 2	5	21	57
	पर्यावरण शिक्षा योजना			
49.	शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के लिए पर्यावरण शिक्षा पर यूनेस्को–यू.एन. इ.पी.-अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संगोष्ठी (वि. और अनौ. शि. एकक और अं. एकक द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित)	22-26 अप्रैल, 1990 (5 दिन)	17	85
	योग 1	5	17	85
	दूरवर्ती शिक्षा			
50.	सबके लिए शिक्षा : दूरवर्ती शिक्षा की भूमिका पर कार्यशिविर (शै. प्र. एकक)	17-20 सितंबर, 1990 (4 दिन)	10	40
	योग 1	4	10	40

1990-91

1	2		3	4	5
	पुस्तकालय और सूचना प्रबंध				
51.	अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय और सूचना परामर्श केंद्र के सहयोग से सूचीकरण, सारांशीकरण और सूचना पुनः प्राप्ति की भूमिका पर अभिविन्यास कार्यक्रम (पुस्तकालय और प्रलेखन एकक)		23-28 जुलाई, 1990 (6 दिन)	28	168
	योग	1	6	28	168
	अन्य				
52.	श्रीलंका के अधिकारियों के लिए दौरा कार्यक्रम (शै. प्र. एकक)		12-16 नवंबर, 1990 (5 दिन)	5	25
	योग	1	5	5	25
	कुल योग	52	717	1060	14026

* इस सूची में पहले से जारी एक राष्ट्रीय डिप्लोमा और एक अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम को शामिल नहीं किया गया है।

1990-91

अनुबंध-II

प्रशिक्षण सामग्रियों की सूची

- भारत में शैक्षिक वित्त का प्रबंध—एक रीडर
- उच्च शिक्षा वित्तयन
- आदिवासी उपयोजना और अनु. जा. की योजना के अंग
- शिक्षा का विकास : 1989-90 भारत की राष्ट्रीय रिपोर्ट
- सबके लिए शिक्षा : उत्तरप्रदेश
- शिक्षा वित्त के कुछ पक्षों पर टिप्पणियां
- जि. शि. प्र. सं. के लिए प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की भूमिका और कार्यकलाप पर माड्यूल
- जि. शि. अ. के कार्यक्रमों पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट
- श्रीलंका समूह के लिए जि. शि. अ. के प्रशिक्षण की जरूरतें
- जि. शि. प्र. सं. के लिए प्रधानाध्यापकों की भूमिका पर माड्यूल
- जि. शि. प्र. सं. के लिए प्रारंभिक शिक्षा के प्रधानाध्यापकों के प्रशिक्षण की जरूरतों पर माड्यूल
- जि. शि. प्र. सं. के लिए सांस्थानिक योजना पर माड्यूल
- उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा का वित्तयन
- भारत में उच्च शिक्षा के वित्तयन में छात्र ऋण
- ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा और रोजगार के बीच के संबंधों के कुछ महत्वपूर्ण पक्ष
- जिला स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के उपरांत व्यावसायिक शिक्षा की योजना
- उच्च शिक्षा का निजीकरण
- आर्थिक विकास से मानव विकास तक
- शिक्षा में प्रोत्साहनों का प्रबंध
- गुणवत्ता की चाह : हस्तक्षेप और प्रभाव
- अनुसंधान प्रविधि और कार्यात्मक अनुसंधान
- प्रौढ़ साक्षरता और विकास
- क्षेत्रीय योजना में वित्तीय प्रायोजकों की भूमिका

1990-91

अनुबंध-III

नीपा विचार मंच

दिनांक	विषय	वक्ता
4 दिसंबर, 1990	एशिया और प्रशांत में शिक्षा	श्री हेदायाल अहमद निदेशक यूनेस्को एशिया और प्रशांत का प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकाक
7 जनवरी, 1991	अकादमिक व्यवसाय : तुलनात्मक संप्रेक्ष्य	श्री जी. जी. अल्टबाख निदेशक तुलनात्मक शिक्षा केंद्र न्यूयार्क, बफैलो
16 जनवरी, 1991	गरीबी हटाओ कार्यक्रम और शिक्षा की भूमिका	श्री इ जेंट अमरीका
17 जनवरी, 1991	मानव जांच पड़ताल और अनुसंधान प्रणाली : अनुसंधान डिजाइन प्रक्रिया	डॉ. जीन कुक प्रोफेसर, डायटन अमरीका
18 फरवरी, 1991	नगरीय भारत में निजी और अनुदान प्राप्त पब्लिक विद्यालयों की लागत प्रभाविता, आर्थिक क्षमता और समता प्रभाव	सुश्री गीता किंगडन आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय
16 मार्च, 1991	जन नीति प्रतिपादन : राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सर्वेक्षण	श्री एच. वी. रामाराव शोधछात्र (एम. फिल.) हैदराबाद

1990-91

अनुबंध-IV

संकाय का अकादमिक योगदान

पुस्तकें

कुसुम के. प्रेमी

अध्याय, चाइल्ड वर्क्स इन इंडिया : स्ट्रेटेजी फार एजुकेशनल डेवलपमेंट, ए. डी. मोडी (सं) **कांसेप्ट और वर्क इन इंडिया,** मनोहर पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1991

'एजुकेशनल सीचुएशन ऑफ चाइल्ड इन इंडिया' **चाइल्ड सीचुएशन इन इंडिया,** राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, 1990

एन. वी. वर्गीस

डेवलपमेंट आफ आयल इंडस्ट्री इन केम–रूम एण्ड इट्स इंप्लिकेशंस फार एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग (सह-लेखक), पेरिस, अं. शै. यो. सं., 1990

एस. सी. नुना

स्कूल एजुकेशन इन इंडिया : रीजनल डायमेंशंस, (प्रो. मुनिस रज़ा, और प्रो. ए. अहमद के साथ सहलेखन)

महिला और विकास, नीपा, 1990

आरिफ हसन

आर्गेनाइजेशनल रीसर्च इन इंडियन पर्सपेक्टिव (सं.1990) नार्थ बुक सेंटर

फैक्टर्स इंफ्लूएंसींग च्वाइस आफ लीडरशीप स्टाइल–इन आर्गेनाईजेशनल रीसर्च इन इंडिया पर्सपेक्टिव, नई दिल्ली नार्दर्न बुक सेंटर (1990)

ए. मैथ्यू

मिनिस्ट्री आफ एजुकेशन : एन आर्गेनाइजेशनल हिस्ट्री, नीपा, 1990

अध्याय– बेसिक एजुकेशन : ए हिस्ट्रीकल पर्सपेक्टिव टू द यूनीसेफ स्पासोर्ड रीसर्च स्टडी, **बेसिक एजुकेशन एण्ड नेशनल डेवलपमेंट : द इंडियन सीन,** 1990

एम. एम. रहमान

पॉलिटिकल इकॉनामी ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग इन एजुकेशनल, नई दिल्ली, 1990

प्रकाशित अनुसंधान पत्र/आलेख

जे. बी. जी. तिलक

'फायनेंसिंग हायर एजुकेशन' उच्च शिक्षा में सुधार और नवाचार पर एस. एन. डी. टी. विश्वविद्यालय, बंबई में आयोजित अनुसंधान संगोष्ठी (जनवरी, 1991)

फायनेंसिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया (एन.वी.वर्गीस के साथ) **हायर एजुकेशन,** (नीदरलैंड) विकासशील देशों पर विशेषांक, सं. जी साचरापौलॉस, जिल्द 21 सं. 1 (1991) पृ. 83-1001.

1990-91

'स्कूलिंग एण्ड इक्वीटी' (जार्ज साचरापौलॉस के साथ), **एसेज ऑन पावर्टी, इक्वीटी एण्ड ग्रोथ** (सं. जी. साचरापौलॉस) पर्गेमन प्रेस, द वर्ड बैंक, 1991 पृ. 53-78

'एक्सटर्नल डेब्ट एण्ड पब्लिक इंवेस्टमेंट इन एजुकेशन इन सब–सहारा अफ्रीका', **जर्नल ऑफ एजुकेशन फायनेंस** जिल्द 15, सं. 4 (1990), पृ. 470-86

'फेमिली एण्ड गवर्नमेंट इंवेस्टमेंट्स इन एजुकेशन' **इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट,** 12 (1991) पृ. 91-106

'स्पेंडीचर आन एजुकेशन इन इंडिया', **जर्नल आफ एजुकेशन एण्ड सोशल चेंज**, जिल्द 4, सं. 2 जुलाई-सितंबर, 1990

'सोशियो–इकॉनॉमिक कोरिलेट्स ऑफ इनफैंट मारटलिटी इन इंडिया, **रीविस्ता इंटरनेशनल दी साइंस इकॉनामिक एंड कामर्शियल** जिल्द 38, सं. 2 (फरवरी, 1991) पृ. 169-92

'कांपरेटिव डेवलपमेंट इंडिकेटर्स' (जीम कॉन के सहयोग से) **इन एसेज ऑन पावर्टी, इक्विटी एण्ड ग्रोथ** (सं. जी. साचारोपोलस) परगेमन प्रेस/विश्व बैंक, 1991,पृ. 291-339

'इंवेस्टमेंट इन इलेमेंट्री एजुकेशन' **फायनेंसीयल एक्सप्रेस** 1 जून, 1990

'ए नोट ऑन स्टूडेंट लोंस इन फायनेंसिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया', आइ. आइ. इ. पी. फोरम आन एजुकेशन लोंस इन एशिया, जेंटींग, मलएशिया, 1990

'यूनियन बजट एण्ड एजुकेशन' **एजुकेशन टेक्नॉलाजी** (11) अप्रैल, 1990 पृ. 10-11

'एजुकेशन एण्ड इकॉनामिक ग्रोथ इन चाइना, **रीविस्ता इंटरनेशनल दी साइंस इकनॉमिक्स कामर्सियल** जिल्द 37, सं. 12, दिसंबर 1990 पृ. 113-35

'रिसोर्सेज फॉर एजुकेशन फार आल' (एन.वी.वर्गीस के साथ) **जर्नल आफ एजुकेशन एण्ड सोशल चेंज** जिल्द 4, सं. 4 (जनवरी-मार्च, 1991) पृ. 24-59

'प्लानिंग टीचर एजुकेशन' (**रिसोर्स बुक ऑन टीचर एजुकेशन इन इंडिया** (सं. एल. सी. सिंह, नई दिल्ली, रा. शै. अ. प्र. प. 1990)

'एजुकेशन एण्ड अर्निंग्स : जेंडर डिफरेंसेज इन इंडिया', **इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग लिटेरेचर** जिल्द 5 सं. 4 (1990)

कुसुम प्रेमी

'एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, 1981-2011 : मेजर इसूज'; **मैन एण्ड डेवलपमेंट**, जून, (1990)

'एजुकेशन फार इक्विटी : यूनिवर्सल इलिमेंटरी एजुकेशन इन रिमोट एरियाज', **न्यू फरांटियर्स इन एजुकेशन,** जनवरी 1990, अप्रैल 1990, में प्रकाशित

'प्रोटेक्टिव डिस्क्रीमिनेशन एण्ड रीजनल डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन : द केस आफ इंडियन ट्राइब्स' **एजुकेशन एण्ड सोशल चेंज** जिल्द 4, सं. 4, जनवरी-मार्च, 1991

एन. वी. वर्गीस

'रिसोर्सेज फार एजुकेशन फार आल' (सह-लेखक), **जर्नल आफ एजुकेशन एण्ड सोशल चेंज** जिल्द 4 सं. 4, 1991 पृ. 24–59

'फायनेंसिंग आफ हायर एजुकेशन इन इंडिया' (सह लेखक) **हायर एजुकेशन** (नीदरलैंड्स) जिल्द 21 सं. 1,1991 पृ. 83-101

'मैनेजमेंट आफ चेंज इन हायर एजुकेशन : सम ट्रेंड्स, **J.E.P.A.** जिल्द 5, सं. 1, 1991 (प्रेस में)

'एजुकेशनल पर्सपेक्टिव आफ द एट्थ फाइव इयर प्लान' **एजुकेशनल टेक्नोलाजी**, जिल्द 2 सं. 12,1990 पृ. 9-10

'थियरी आफ लेबर मार्केट', सं. बी. सन्याल, **शिक्षा रोजगार और वर्क** (प्रशिक्षण कार्यशिविर की रिपोर्ट) पेरिस, आइ. आइ. इ. पी, 1990 पृ. 88-100

1990-91

'स्ट्रेटेजी फार ए बेटर मैच बिटवीन एजुकेशन एण्ड इम्पलायमेंटः ए सिंथेसीस आफ डिसकसंस एण्ड इंडिया' (सह लेखक) सं. बी. सन्याल, **एजुकेशन इंपलायमेंट एण्ड वर्क** (प्रशिक्षण कार्यशिविर की रिपोर्ट, पेरिस आइ. आइ. इ. पी., 1990 पृ. 179-188

नीपा, नई दिल्ली में शिक्षा और रोजगार योजना पर आयोजित कार्यशिविर में 'एजुकेशन एण्ड इंपलायमेंट प्लानिंग ऐट द डिस्ट्रिक्ट लेवल' विषय पर आलेख प्रस्तुत (11-14 दिसंबर, 1990)

इ. गां. रा. खु. वि., नई दिल्ली के लिए 'एस्पेक्ट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट' माड्यूल, 1990

एस. सी. नुना

रीजनल डिस्पैरिटीज इन एजुकेशनल डेवलपमेंट : पॉलिसी एण्ड प्लानिंग इंपलिकेशंस, **क्वार्टरली इकानामिक रिपोर्ट आफ द इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक ओपीनियन** जिल्द XXXII, सं. 5 पृ. 40-54

'स्पाइटल पैटर्न आफ ट्राइवल लिटेरेसी इन इंडिया' सं. आशीष बोस, **डिमोग्राफी आफ ट्राइवल डेवलपमेंट**, बी. आर. पब्लिशिंग कार्पोरेशन पृ. 273-296 (मुनिस रज़ा और ए. अहमद के साथ)

प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन आफ वर्किंग चिल्ड्रेनः ऐन अप्रोच', **जे. इ. पी. ए.** जिल्द 4, सं. 1 पृ. 93-104 (नलिनी जुनेजा के साथ)

'डेवलपमेंट आफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया : सम प्राबलंम्स आफ मिजरमेंट सं. मुनिस रज़ा **एजुकेशन डेवलपमेंट एण्ड सोसायटी,** विकास, 1990 पृ. 95-120 (मुनिस रज़ा के साथ)

अंजना मंगलागिरि

'द स्ट्रक्चर एण्ड कांटेक्सट आफ एजुकेशनल डेवलपमेंट : ए कांपरेटिव पर्सपेक्टिव' **जे. इ. पी. ए.** जिल्द 4 सं. 3, जुलाई, 1990

रंजना श्रीवास्तव

रीमूव एबीरेशंस, ओवर हॉलिंग नॉट नीड इन कुरुक्षेत्र 1-15 जनवरी, 1996 (शिक्षा विशेषांक : नई शिक्षा नीति 1986 समीक्षा समिति संप्रेक्ष्य पत्र

पुस्तक समीक्षा, **'माइक्रो कंप्यूटर इन स्कूल एजुकेशन**—हैंडबुक फार टीचर्स' एजुकेशनल टेक्नॉलाजी, जिल्द 3 सं., 1991

बी. एच. श्रीधर

'कंप्यूटर्स इन सोशल साइंस रीसर्च' **जर्नल आफ सोशल रीसर्च** जिल्द XXXI, सं. I & II

पुस्तक समीक्षाएं

जे. बी. जी. तिलक

'कम्यूनीटी फायनेंसिंग आफ एजुकेशन' जर्नल आफ एजुकेशन फायनेंस जिल्द 15, सं. 3 (1990)

'ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन द थर्ड वर्ल्ड' **किकलॉस** जिल्द 43 सं. 2 (1990) पृ. 330-31

'द कालेज ट्यूशन स्पाइरल (एण्ड) 'द ट्यूशन डिलेमा' **जे. इ. पी. ए.** जिल्द 4 सं. 4 (अक्टूबर,1990) प्रेस में

फायनेंशियल सपोर्ट फार स्टूडेंट्स' **हायर एजुकेशन रिव्यू** जिल्द **23 सं. 2** (स्प्रींग 1991) पृ. 83-84

'एजुकेशन, वर्क एण्ड पे इन इस्ट अफ्रीका', एजुकेशन प्राडक्टिविटी **एण्ड इनइक्वलिटी' जे. इ. पी. ए.** जिल्द 5 सं. 1 (जनवरी 1991)

1990-91

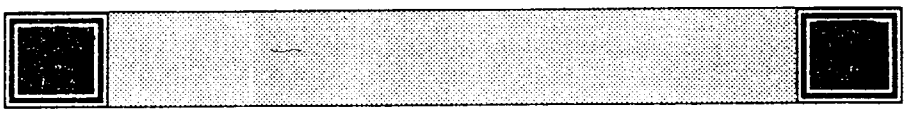

संस्थान के बाहर नीपा संकाय की भागीदारी

सत्रों की अध्यक्षता/उद्घाटन/समापन इत्यादि

सत्यभूषण

अकादमिक स्टाफ कालेज, हिमाचल विश्वविद्यालय, शिमला द्वारा आयोजित संगोष्ठी का उद्घाटन किया (11-12 मई, 1990)

भारतीय समाज संस्थान, नई दिल्ली द्वारा 'सबके लिए शिक्षा' पर आयोजित आइ. एल. वाइ. कार्यशिविर का उद्घाटन किया। (17 जुलाई, 1990)

विदेश व्यापार संस्थान में 'शैक्षिक प्रौद्योगिकी' सत्र की अध्यक्षता की। (1 नवंबर, 1990)

भारतीय शिक्षा परिषद द्वारा संसद भवन के हाल में 'सबके लिए शिक्षा' विषय पर आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। (27-28 अप्रैल, 1990)

एम. मुखोपाध्याय

कालीकट विश्वविद्यालय के स्नातक छात्रों के एक समूह के समक्ष 'शैक्षिक प्रौद्योगिकी' विषय पर व्याख्यान दिया। (5 अप्रैल, 1990)

नई दिल्ली में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के राज्य सम्मेलन के समापन समारोह सत्र की अध्यक्षता की। (23 सितंबर,1990)

श्रीप्रकाश

अकादमिक स्टाफ कालेज, इलाहाबाद में निर्गत-आगत तकनीक और योजना के मॉडल पर आयोजित संगोष्ठी की अध्यक्षता की और मुख्य व्याख्यान दिया। (13 जुलाई, 1990)

एम. एम. कपूर

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में शैक्षिक सूचना प्रणाली परियोजना के मार्गदर्शन के लिए संसाधन व्यक्ति की भूमिका अदा की। (7 जनवरी, 1991)

एन. वी . वर्गीस

आइ. ए. एम. आर. नई दिल्ली में आयोजित शिक्षा और मानव शक्ति सत्र की अध्यक्षता की। (15 फरवरी,1991)

आर. एस. शर्मा

अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन में 'विशेष शिक्षा और शैक्षिक प्रौद्योगिकी' सत्र की अध्यक्षता की। (31 अक्टूबर, 1990)

दिए गए व्याख्यान

सत्यभूषण

उच्च शिक्षा व्यावसायिक विकास केंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यशिविर में 'ज्ञान का प्रतिपादन और प्रचार-प्रसार, विषय पर व्याख्यान दिया। (14 मई, 1990)

केसर्टा, इटली में प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के इतालिय लोक प्रशासन विद्यालय द्वारा प्रबंधकों के प्रशिक्षण विषय पर आयोजित सम्मेलन में 'अंतर्राष्ट्रीय सहयोग' विषय पर एक व्याख्यान दिया (17-22 मई, 1990)

सीमा सुरक्षाबल निदेशालय, नई दिल्ली में शिक्षा की नई चुनौतियां और प्रवृत्तियां विषय पर व्याख्यान दिया। (5 जून, 1990)

1990-91

रा. शै. अ. प्र. प. नई दिल्ली में 'शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों की भूमिका' विषय पर व्याख्यान दिया। (17 सितंबर, 1990)

आइ. आइ. पी. ए., नई दिल्ली में सी. ए. जी. द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 'ग्राम विकास' पर एक व्याख्यान दिया। (5 अक्टूबर, 1990)

राजकीय वरिष्ठ बालिका माध्यमिक विद्यालय, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली में सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम में समापन भाषण दिया। (5 जनवरी, 1991)

उत्तर क्षेत्रीय समाज केंद्र, नायोडा, उत्तरप्रदेश में समापन भाषण दिया। (12 जनवरी, 1991)

अकादमिक स्टाफ कालेज, जम्मू विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान दिया। (11-12 मार्च, 1991)

पत्राचार शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय में 'दूरवर्ती शिक्षा' पर एक व्याख्यान दिया। (27 मार्च, 1991)

जी. डी. शर्मा

उच्च शिक्षा व्यावसायिक विकास केंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय में 'भौतिकवादी व्यवस्था में शिक्षकों की सेवाओं की स्थितियां' विषय पर व्याख्यान दिया (5 और 8 मई, 1990)

उच्च शिक्षा विकास केंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान दिया। (16 अक्टूबर, 1990)

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय भोपाल में 1990-2000 के दौरान शिक्षा की चुनौतियां, विषय पर व्याख्यान दिया। (15 और 16 नवंबर, 1990)

एम. मुखोपाध्याय

मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली में आयोजित तेरहवें कार्यशिविर में 'मेडिकल शिक्षा में अनुशिक्षणात्मक प्रौद्योगिकी' विषय पर अध्यक्षीय भाषण दिया। (23 अप्रैल, 1990)

राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी, हैदराबाद में अनुशिक्षणात्मक प्रौद्योगिकी पर मुख्य व्याख्यान दिया। (4 जून, 1990)

इ. गा. रा. खु. वि. के क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद में 'शैक्षिक प्रौद्योगिकी की नई प्रवृत्तियां' विषय पर व्याख्यान दिया। (5 जून 1990)

ग्रामीण शिक्षक केंद्र हावड़ा में 'संगणक परिचय' पर व्याख्यान दिया। (11 जुलाई, 1990)

दिल्ली पुलिस, दिल्ली के कार्यक्रम में प्रबंधकीय कौशल का विश्लेषण' विषय व्याख्यान दिया। (5 सितंबर, 1990)

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में 'उच्च शिक्षा के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी' और 'बढ़िया कक्षा शिक्षण के लिए विश्लेषण' पर व्याख्यान दिए। (10 सितंबर,1990)

उलबेरिया में शैक्षिक प्रौद्योगिक से संबंधित अध्यक्षीय भाषण दिया। (22 सितंबर, 1990)

नई दिल्ली में शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के भविष्य पर अध्यक्षीय भाषण दिया। (अक्टूबर, 1990)

अमृतसर, पंजाब में शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर आयोजित विश्व सम्मेलन में मुख्य व्याख्यान दिया (11 नवंबर, 1990)

अकादमिक स्टाफ कालेज, कलकत्ता विश्वविद्यालय कलकत्ता में शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर एक व्याख्यान दिया। (19 दिसंबर, 1990)

नवोदय विद्यालय समिति नई दिल्ली के प्रधानाचार्यों की बैठक में शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर एक व्याख्यान दिया। (26 दिसंबर, 1990)

शैक्षिक विकास में एन. जी. ओ. की भूमिका पर एक व्याख्यान दिया (8 फरवरी, 1991)

1990-91

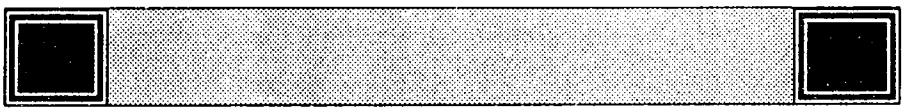

आर गोविंद

उच्च शिक्षा व्यावसायिक विकास केंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली में 'ज्ञान संप्रेषण-परियोजना प्रणाली' पर व्याख्यान दिया। (8 मई, 1990)

के. शै. प्रौ. सं., नई दिल्ली में जिला संसाधन इकाई और शैक्षिक प्रौद्योगिकी विषय पर व्याख्यान दिया। (19 जून, 1990)

सी. सु. बल के विद्यालयों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'सांस्थानिक योजना और मूल्यांकन' पर एक व्याख्यान दिया। (21 जून, 1990)

विश्व युवक केंद्र, नई दिल्ली में 'गतिशील और उपयोगी तकनीकें' विषय पर एक व्याख्यान दिया। (25 जुलाई, 1990)

के. शै. प्रौ. स. (रा. शै. अ. प्र. प.) नई दिल्ली में 'शैक्षिक प्रौद्योगिक और जिला संसाधन केंद्र, विषय पर व्याख्यान दिया। (7 अगस्त, 1990)

उच्च शिक्षा व्यावसायिक विकास केंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय में व्याख्यान विधि द्वारा ज्ञान संप्रेषण, विषय पर व्याख्यान दिया। (13 अक्टूबर, 1990)

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल में 'अनौपचारिक शिक्षा' पर व्याख्यान दिया। (17 नवंबर, 1990)

के. जी. विरमानी

एफ. ओ. आर. इ., नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों के लिए 'प्रबंध विषय' पर एक व्याख्यान दिया। (27-28 अप्रैल, 16,22 और 29 जून, 1990)

के. लो. नि. वि. प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में अधिकारियों के समक्ष 'प्रबंध विषय' पर व्याख्यान दिया। (16-17 मई, 1990)

सी. स. ब. के विद्यालयों के लिए आयोजित कार्यक्रम में 'प्रभावी अनुशिक्षण के लिए शिक्षक की गतिशीलता' विषय पर व्याख्यान दिया। (8 जून, 1990)

हिपा, चंडीगढ़ और नीपा, नई दिल्ली में हरियाणा के अधिकारियों के लिए 'विकास प्रतिबद्धता और अनुपालन' विषय पर व्याख्यान दिया। (16 और 27 जून, 1990)

संगठनात्मक अनुसंधान और शिक्षा फाउंडेशन, नई दिल्ली में 'प्रभावी नेतृत्व और गतिशीलता' विषय पर व्याख्यान दिया। (7, 19 और 20 जुलाई, 1990)

के. लो. नि. वि. प्र. सं., नई दिल्ली में मानव संसाधन विकास पुनर्निवेशन पाठ्यक्रम में के. लो. नि. वि. के अधिकारियों के लिए 'नेतृत्व और कार्य संस्कृति' विषय पर एक व्याख्यान दिया। (10-11 जुलाई, 1990)

नई दिल्ली में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 'प्रबंध के अंतर्विरोध' विषय पर व्याख्यान दिया। (17 और 20 अगस्त, 1990)

नई दिल्ली में दिल्ली पुलिस के पुनर्वास अधिकारियों के लिए व्यावहारिक विज्ञान में प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'कार्यदल नेतृत्व' विषय पर व्याख्यान दिया। (5 सितंबर, 1990)

खेती कापर कांपलेक्स के प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम में 'कार्यदल नेतृत्व और मार्थक रुख' विषय पर व्याख्यान दिया। (12-13 सितंबर, 1990)

के. लो. नि. वि. के अधिकारियों के समक्ष नई दिल्ली में शैक्षिक प्रबंध विषय पर व्याख्यान दिया। (10-11 अक्टूबर, 1990)

कोडइ केनाल में प्राचार्यों और नई दिल्ली में केंद्रीय विद्यालयों के प्राचार्यों के लिए 'शैक्षिक प्रबंध' विषय पर व्याख्यान दिया। (19-21 अक्टूबर, 1990 और 17-19 दिसंबर, 1990)

दिल्ली में निजी संगठनों के अधिकारियों के समक्ष 'गत्यात्मक उपलब्धि और प्रबंध' विषय पर व्याख्यान दिया। (26,27,30 नवंबर, 1990)

1990-91

खेत्री कापर कांपलेक्स, राजस्थान में प्रबंध विषय पर व्याख्यान दिया। (7-8 दिसंबर, 1990)

हीपा, चण्डीगढ़ और फरीदाबाद में हरियाणा सरकार के अधिकारियों के लिए 'कार्यसंस्कृति की समझ' विषय पर व्याख्यान दिया। (3 और 12 दिसंबर, 1990)

पुरी में सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए 'परियोजना प्रबंध की कार्य संस्कृति और कार्यदल निर्माण का नेतृत्व' विषय पर व्याख्यान दिया। (24 दिसंबर, 1990)

नई दिल्ली में नई महिला प्रबंधकों पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में सांगठनिक अनुसंधान और शिक्षा की नींव, विषय पर व्याख्यान दिया। (8 जनवरी, 1991)

के. लो. नि. वि. के अधिकारियों के समक्ष प्रबंध विषय पर व्याख्यान दिया। (8 जनवरी, 1991)

तमिलनाडु और पांडिचेरी के प्रधानाध्यापकों के लिए शैक्षिक नेतृत्व पर एक व्याख्यान दिया। (14-15 जनवरी, 1991)

अकादमिक स्टाफ कालेज, जे. एन. यू. नई दिल्ली में शिक्षा नेतृत्व पर व्याख्यान दिया। (18 जनवरी, 1991)

नई दिल्ली में निजी प्रतिष्ठानों के अधिकारियों/वैज्ञानिकों के समक्ष 'उपलब्धि गतिशीलता' पर व्याख्यान दिया। (31 जनवरी, 1991)

श्रीप्रकाश

उच्च शिक्षा व्यावसायिक विकास केंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली में 'रोजगार शिक्षा संबंध' और शिक्षा और आर्थिक विकास' विषय पर व्याख्यान दिए। (23 मई, 1990)

अकादमिक स्टाफ कालेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में 'आगत-निर्गत अर्थव्यवस्था : अर्थ, स्वरूप और परिकल्पित स्थाई मॉडल, और लावनटफ गति मॉडल, विषय पर व्याख्यान दिया। (13-14 जुलाई, 1990)

आई. ए. एम. आर., नई दिल्ली में 'पूंजी सिद्धांत आधारित आर्थिक विकास' में व्याख्यान दिया। (18 सितंबर, 1990)

आई. ए. एम. आर., नई दिल्ली में 'शैक्षिक योजना प्रणाली' पर व्याख्यान दिया। (19 सितंबर, 1990)

भा. सा. सं., नई दिल्ली में 'आर्थिक विकास में औद्योगीकरण, पर व्याख्यान दिया। (16 जनवरी, 1991)

आई. ए. एम. आर., नई दिल्ली में 'मानव शक्ति योजना के आगत-निर्गत मॉडल' पर व्याख्यान दिया (4-5 फरवरी, 1991)

आई. ए. एम. आर., नई दिल्ली में 'शैक्षिक योजना में संगणक अनुपयोग पर व्याख्यान दिया। (5 फरवरी, 1991)

एम. एम. कपूर

रा. शै. अ. प्र. प. नई दिल्ली में महिला और विकास पर आयोजित कार्यक्रम में 'शिक्षा में परियोजना प्रतिपादन' और 'शिक्षा में संचारेक्षण मूल्यांकन, विषयों पर व्याख्यान दिए। (11-13 सितंबर, 1990)

जि. शि. प्र. सं. मोतीनगर, नई दिल्ली में प्रधानाध्यापकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 'प्रा. शि. सा. के लिए व्यष्टि स्तरीय योजना' पर व्याख्यान दिया। (10 नवंबर, 1990)

जि. शि. प्र. सं. राजेंद्रनगर, नई दिल्ली में 'प्रा. शि. सा. के लिए व्यष्टि स्तरीय योजना, पर व्याख्यान दिया। (1 दिसंबर, 1990)

उत्तर क्षेत्रीय विकास केंद्र, नावोग, उत्तरप्रदेश द्वारा आयोजित कार्यक्रम में व्यष्टि स्तरीय योजना पर एक व्याख्यान दिया। (9 जनवरी, 1991)

जे. बी. जी. तिलक

रा. शि. नी. की समीक्षा समिति में नई दिल्ली में 'उच्च शिक्षा वित्तयन' पर व्याख्यान दिया। (12 अगस्त, 1990)

बंबई विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 'शिक्षा और आर्थिक विकास' पर एक व्याख्यान दिया। (4 जनवरी, 1991)

1990-91

आई. ए. एम. आर. नई दिल्ली में 'भारत में शिक्षा की लागत' पर एक व्याख्यान दिया। (14 फरवरी, 1991)

जया इंदिरेसन

नई दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय समिति के प्राचार्यों के लिए स्वॉट विश्लेषण पर व्याख्यान दिया। (15 जून, 1990)

नई दिल्ली में दिल्ली पुलिस सेवा के पुनर्वास अधिकारियों के लिए 'कार्य का अर्थ' विषय पर व्याख्यान दिया। (3 सितंबर, 1990)

कुसुम प्रेमी

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर द्वारा लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में 'उत्तरप्रदेश के आश्रम विद्यालय के प्रधानाचार्य' विषय पर व्याख्यान दिया। (26-27 जुलाई, 1990)

राष्ट्रीय शै. अ. प्र. प., नई दिल्ली में महिला और विकास पर आयोजित कार्यक्रम में 'महिला विकास के सूचक' विषय पर व्याख्यान दिया। (27 अगस्त, 1990)

राष्ट्रीय शै. अ. प्र. प. नई दिल्ली में जि. शि. प्र. सं. के लिए आयोजित कार्यक्रम में 'अनुसंधान विधि' पर एक व्याख्यान दिया। (30 सितंबर, 1990)

सुषमा भागिया

उत्तर क्षेत्रीय विकास केंद्र, नायोडा, उत्तरप्रदेश में आयोजित कार्यक्रम में 'प्रशिक्षण कार्यक्रम की डिजाइन' विषय पर व्याख्यान दिया। (11 जनवरी, 1991)

के. सुधाराव

मदुराई कामराज विश्वविद्यालय मदुराई में प्रभावी शिक्षण के लिए 'संप्रेषण कौशल और शिक्षकों का उत्तरदायित्व' विषय पर व्याख्यान दिया। (29-30 मई, 1990)

श्री वेंकटाश्वरैया विश्वविद्यालय में 'उत्तरदायित्व : संस्थान और शिक्षक' तथा 'प्रभावी शिक्षण : संप्रेक्षण की भूमिका' विषय पर व्याख्यान दिए। (14-15 जून, 1990)

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर राजस्थान में 'स्वायत्तता और उत्तरदायित्व' विषय पर व्याख्यान दिया। (22 जून, 1990)

आर. एस. शर्मा

जि. शि. प्र. सं. राजेंद्र नगर, नई दिल्ली में 'सांस्थानिक योजना और प्रबंध' विषय पर व्याख्यान दिया। (30 नवंबर, 1990)

जि. शि. प्र. सं., राजेंद्र नगर और मोतीबाग, नई दिल्ली में प्रा. शि. के प्रधानाध्यापकों के लिए 'सांस्थानिक क्षमता का मजबूतीकरण' विषय पर व्याख्यान दिया। (15-16 नवंबर, 1990)

एन. वी. वर्गीस

रा. शै. अ. प्र. प., नई दिल्ली में महिला प्रशासकों के समक्ष 'स्वातंत्र्योत्तर शैक्षिक विकास' पर व्याख्यान दिया। (8 जुलाई, 1990)

आइ. ए. एम. आर., नई दिल्ली में 'अर्थव्यवस्था और शैक्षिक योजना' विषय पर एक व्याख्यान दिया। (9 अगस्त, 1990)

रा. शै. अ. प्र. प., नई दिल्ली द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जि. शि. प्र. सं. के प्राचार्यों के लिए विकेंद्रीकृत योजना पर व्याख्यान दिया। (29 जनवरी, 1991)

आरिफ हसन

जि. शि. प्र. सं., राजेंद्र नगर, नई दिल्ली में 'प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की भूमिका और कार्यकलाप' पर व्याख्यान दिया। (9 और 17 नवंबर, 1990)

1990-91

जि. शि. प्र. सं., राजेंद्र नगर, नई दिल्ली में 'विद्यालय अग्रदूत के रूप में प्रधानाध्यापक' विषय पर व्याख्यान दिया। (16 नवंबर, 1990)

जि. शि. प्र. सं. राजेंद्र नगर, नई दिल्ली में 'प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की भूमिका और कार्यकलाप' पर व्याख्यान दिया। (1 दिसंबर, 1990)

विश्वविद्यालय प्रशासक परिसंघ द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'निर्णय लेना' विषय पर व्याख्यान दिया। (13 दिसंबर, 1990)

ए. मैथ्यू

रा. शै. अ. प्र. प., नई दिल्ली में 'भारत में शिक्षा : ऐतिहासिक सिंहावलोकन' विषय पर व्याख्यान दिया। (21 अगस्त, 1990)

बी. एच. श्रीधर

अनुप्रयुक्त मानवशक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'शैक्षिक योजना पर संगणक मॉडल' विषय पर व्याख्यान दिया। (30 अगस्त 1990)

रा. शै. अ. प्र. प., नई दिल्ली में महिला प्रशासकों के लिए आयोजित कार्यक्रम में 'आंकड़ा आधारित प्रबंध प्रणाली और उनके अनुप्रयोग' विषय पर व्याख्यान दिया। (4-5 अक्टूबर, 1990)

दिल्ली विश्वविद्यालय में आर्थिक व्यापार के परास्नातक के छात्रों के समक्ष 9 जनवरी, 1991 से 12 सप्ताह तक 'प्रणाली विश्लेषण, डिजाइन, और प्रोग्रामिंग' विषय पर 12 व्याख्यान दिए।

रा. शै. अ. प्र.प. नई दिल्ली में जि. शि. प्र. सं. के प्राचार्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'प्रबंध में संगणक का अनुप्रयोग' विषय पर व्याख्यान दिया। (31 जनवरी, 1991)

प्रमिला मेनन

रा. शै. अ. प्र. प. नई दिल्ली के महिला कक्ष द्वारा महिला कार्मिकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में योजना कार्यक्रम में समुदाय की भागीदारी' विषय पर व्याख्यान दिया। (सितंबर, 1990)

जि. शि. प्र. सं., लारेंस रोड, नई दिल्ली में 'विद्यालय समुदाय के साथ विकास का संबंध' विषय पर व्याख्यान दिया। (15 नवंबर, 1990)

जि. शि. प्र. सं., नई दिल्ली में योजना और प्रबंध विभाग के लिए 'लैब क्षेत्र प्रणाली' पर व्याख्यान दिया। (12 जनवरी, 1991)

बी. के. पंडा

जि. शि. प्र. सं., राजेंद्र नगर, नई दिल्ली में' दि. न. नि. के विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के विशेष संदर्भ में प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के कार्य और कौशल की भूमिका' विषय पर व्याख्यान दिया। (19 नवंबर, 1990)

जि. शि. प्र. सं., नई दिल्ली में 'प्रारंभिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के प्रशिक्षण की जरूरतें और कौशल और कार्यों की भूमिका' पर व्याख्यान दिया। (26-28 नवंबर,1990)

संगोष्ठियों में भागीदारी

सत्यभूषण

आई. ए. एम. आर., नई दिल्ली द्वारा 'अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम' पर आयोजित परिचर्चा में भाग लिया। (10 अक्टूबर, 1990)

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में 'प्रौढ़ साक्षरता और विकास' पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया। (20 नवंबर, 1990)

आइ. आइ. इ. पी., पेरिस में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया। (10-14 दिसंबर, 1990)

1990-91

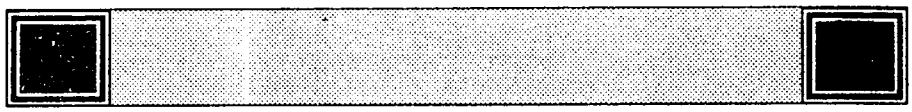

जी. डी. शर्मा

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के XVIII A SOP पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। (23 अप्रैल, 1990)

अकादमिक स्टाफ कालेज, पटना में कालेज प्राचार्यों के लिए आयोजित कार्यशिविर में भाग लिया और मुख्य भाषण दिया। (18-20 जुलाई, 1990)

राज्य शै. अ. प्र. प., हैदराबाद, आंध्रप्रदेश के प्रबंध कार्यशिविर में भाग लिया (19 सितंबर, 1990)

आर. गोविंद

ए. आइ. एम. ए. सी. एस. के तत्वाधान में बंबई में 'बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता' पर आयोजित संगोष्ठी में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया। (2-4 जून, 1990)

भारत समाज विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में 'सबके लिए शिक्षा' पर आयोजित संगोष्ठी में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया। (21-29 जुलाई, 1990)

रा. शै. अ. प्र. प., अहमदाबाद में 'अधिगम के न्यूनतम स्तर' पर आयोजित कार्यशिविर में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया। (21-29 जुलाई, 1990)

बैंकाक और मनीला में अनौपचारिक शिक्षा में साक्षरता की योजना और प्रबंध पर आयोजित यूनेस्को कार्यशिविर में भाग लिया। (15 अगस्त-15 सितंबर, 1990)

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में 'शिक्षा और विकास पर भारत-चीन अध्ययन' पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया। (20 सितंबर, 1990)

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) द्वारा शिक्षाकर्मी परियोजना पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया। (3 दिसंबर, 1990)

एम. एम. कपूर

आइ. ए. एम. आर. नई दिल्ली में 'प्रधानाध्यापकों के पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम की डिजाइन' पर आयोजित कार्यशिविर में भाग लिया। (19 अगस्त, 1990)

कांस्टीच्यूशन क्लब, नई दिल्ली में भारतीय शिक्षा मंडल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया। (18 नवंबर, 1990)

लखनऊ में वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासकों के लिए 'विद्यालय मानचित्रण और व्यष्टि स्तरीय योजना' पर आयोजित कार्य शिविर में भाग लिया। (18-19 जनवरी, 1991)

जे. बी. जी. तिलक

आइ. आइ. इ. पी. द्वारा 'एशिया में शैक्षिक मंच और छात्र ऋण' विषय पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। (6-8 नवंबर, 1990)

नई दिल्ली में विश्व बैंक द्वारा 'सबके लिए शिक्षा' पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया। (9 नवंबर, 1990)

'भारत में लंबी अवधि की शैक्षिक योजना' पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। (26-28 नवंबर, 1990)

एस. यू. एन. वाई और एस. एन. डी. टी. महिला विश्वविद्यालय, बंबई द्वारा 'भारतीय उच्च शिक्षा में सुधार और नवाचार' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया। (जनवरी, 1991)

जया इंदिरेसन

मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कोडइ केनाल की संगोष्ठी में भाग लिया। (21 अप्रैल, 1990)

संप्रेषण अध्ययन केंद्र द्वारा 'विकास के लिए विकास संप्रेषण का प्रबंध' पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया। (10 मई, 1990)

1990-91

कुसुम प्रेमी

'क्षेत्रीय विषमताएं मापने के उपकरण' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया। (9-10 अगस्त, 1990)

सुषमा भागिया

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय नई दिल्ली द्वारा केंद्र आधारित प्रणाली के विरुद्ध वैयक्तिक शिक्षार्थी प्रणाली पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया। (15 जनवरी, 1991)

जे. एन. यू., नई दिल्ली में 'प्रौढ़ शिक्षा के सिद्धांत और राजनीति : सन 1947 से पहले और बाद के भारतीय' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया। (21 जनवरी, 1991)

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली द्वारा परासाक्षरता सामग्री की योजना पर आयोजित कार्यशिविर में भाग लिया। (20-23 मार्च, 1991)

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में 'मुज्जफरपुर पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम' पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। (28 जनवरी, 1991)

आर. एस. शर्मा

राष्ट्रीय शै. अ. प्र. प., नई दिल्ली में जि. शि. प्र. सं. के प्राचार्यों के प्रवेश प्रशिक्षण की सामग्रियों के विकास पर आयोजित कार्यशिविर में भाग लिया। (3-5 सितंबर, 1990)

'शिक्षा प्रबंध की प्रणाली में प्रेरक तकनीक की भूमिका' पर आयोजित कार्यशिविर में भाग लिया। (31 अक्टूबर, 1991)

के. सुधाराव.

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में ' भवितव्यता की सुनिश्चितता : भारत की चुनौती' पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया और ' मानव संसाधन विकास' पर एक पत्र प्रस्तुत किया। (26-29 अप्रैल, 1990)

एन. वी. वर्गीस

आइ. आइ. इ. पी.- पी. आर. ओ. ए. पी. द्वारा बैंकाक, पेरिस में शिक्षा, रोजगार और मानव संसाधन विकास' पर आयोजित कार्यशिविर में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया। (12-26 जून, 1990)

सुदेश मुखोपाध्याय

जि. शि. प्र. सं. राजेंद्रनगर, नई दिल्ली के सांस्थानिक योजना अभ्यास में भाग लिया। (27 जून, 1990)

नई दिल्ली में पी. आइ. इ. डी— नगरीय बेसिक सेवा के कार्यक्रम में भाग लिया। (30 जून, 1990)

के. सुजाता

राष्ट्रीय शै. अ. प्र. प., नई दिल्ली में 'बाबा साहेब आंबेडकर और भारतीय समाज की असमानता दूर करने की रणनीतियों पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया और 'जनजातीय शिक्षा में सांस्कृतिक प्रणाली' पर पत्र प्रस्तुत किया। (18-19 दिसंबर, 1990)

राष्ट्रीय शै. अ. प्र. प. नई दिल्ली में 'बाबा साहेब आंबेडकर और भारतीय समाज की असमानताएं दूर करने की रणनीतियां' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया। (16 जनवरी, 1991)

एस. सी. नुना

12 वां भूगोल कांग्रेस, राजकोट में भाग लिया और 'महिला विकास : विकास और समाज कल्याण के स्तरों के बीच संबंध' विषय पर अपना आलेख पढ़ा। (27-29 दिसंबर, 1990)

आरिफ हसन

गया कालेज, गया के व्यापार प्रशासन विभाग द्वारा सांगठनिक

1990-91

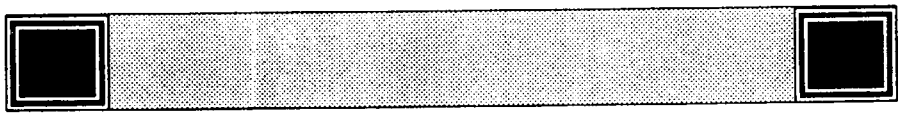

प्रभाविता, पर आयोजित कार्यशिविर में भाग लिया। (4-6 अगस्त, 1990)

रंजना श्रीवास्तव

नई दिल्ली में 'अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी : भविष्य' पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। (31 अक्टूबर, 3 नवंबर, 1990)

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में 'विकास के लिए प्रौढ़ शिक्षा' पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया। (20-22 नवंबर, 1990)

प्रमिला मेनन

अखिल भारतीय कैथोलिक विद्यालय परिसंघ, द्वारा सबके लिए शिक्षा पर आयोजित कार्यशिविर में भाग लिया। (17-21 जुलाई, 1990)

रा. शै. अ. प्र. प. नई दिल्ली में 'प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या' पर आयोजित कार्यशिविर में भाग लिया। (10-14 सितंबर, 1990)

रा. शि. सं., नई दिल्ली में जि. शि. प्र. सं. के प्राचार्यों के प्रवेश प्रशिक्षण पर आयोजित कार्यशिविर में भाग लिया। (सितंबर, 1990)

जयश्री जलाली

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में 'संस्कृति द्वारा शांति' पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। (28 नवंबर, 1990)

आइ. आइ. सी. नई दिल्ली में मा. सं. वि. मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा जन साक्षरता अभियान पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया। (1 फरवरी, 1991)

1990-91

परिशिष्ट I

नीपा परिषद के सदस्य

(31 मार्च, 1991)

अध्यक्ष

रिक्त

उपाध्यक्ष

प्रोफेसर सत्यभूषण
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना
और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

पदेन सदस्य

डॉ. मनमोहन सिंह	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली
श्री अनिल बोर्डिया	शिक्षा सचिव, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
वित्त सलाहकार	वित्त सलाहकार, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
श्री ए. आर. बंधोपाध्याय	अतिरिक्त सचिव, जन शिकायत और प्रशासनिक सुधार मंत्रालय, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली
श्री एम. आर. कोल्हाटकर	सलाहकार (शिक्षा), योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली
श्री के. गोपालन	निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली

1990-91

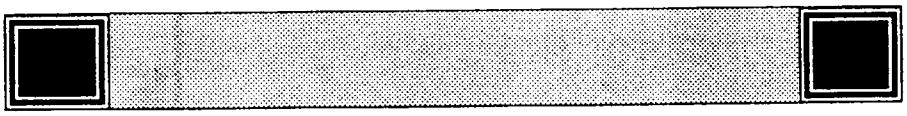

शिक्षा सचिव

श्री एम. एल. मालसावना	शिक्षा सचिव, शिक्षा विभाग, मिज़ोरम सरकार, एजवाल
श्री वी. टोबडेन	शिक्षा सचिव, शिक्षा विभाग, सिक्किम सरकार, ताशिलिंग एक्सटेंशन, गंगटोक
सुश्री सुषमा चौधरी	शिक्षा सचिव, शिक्षा विभाग, सिविल सचिवालय, जम्मू और कश्मीर सरकार, श्रीनगर, जम्मू तवी
सुश्री कुमुद बंसल	तकनीकी शिक्षा सचिव, महाराष्ट्र सरकार, बंबई—400032
श्री बी. के. भट्टाचार्या	आयुक्त और सचिव, शिक्षा विभाग, कर्नाटक सरकार, सचिवालय — II, डा. बी. आर. अम्बेडकर रोड, बैंगलौर
श्री प्रदीप सिंह	समाहर्ता और विकास आयुक्त, लक्षद्वीप, कवारती

शिक्षा निदेशक/डी.पी. आई.

श्री एस.बी. विश्वास	विद्यालय निदेशक, त्रिपुरा सरकार, अगरतला
डा. घनश्याम दास	निदेशक (उच्च शिक्षा सचिवालय), उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर
श्री पी. एस. भूपल	निदेशक, जन शिक्षा (प्राथमिक), सेक्टर — 17 सी, चंडीगढ़
श्री ललित के. पवार	निदेशक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, बीकानेर
तिरू वी. ए. शिवाज्ञानम्	निदेशक (अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा), कालेज रोड, डी.पी.आई. परिसर, मद्रास
श्री बेअंत सिंह	निदेशक (शिक्षा प्रशासन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह), पोर्ट ब्लेयर

विख्यात शिक्षाविद

डा. के. वेंकटासुब्रामनियम	भूतपूर्व उपकुलपति, 2, जज जुंबिलीनगर रोड, माइलोपुर, मद्रास-600004

1990-91

डा. एन. आर. सेठ	भूतपूर्व निदेशक, भारतीय प्रबन्ध संस्थान, वस्त्रपुर, अहमदाबाद
डा. एस. पी. अहलूवालिया	प्रोफेसर, अध्यक्ष और डीन, सागर विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश — 470003
डा. पी. डी. शुक्ला	ए, 14/15 वसंत विहार, नई दिल्ली
प्रोफेसर अबाद अहमद	निदेशक, दिल्ली विश्वविद्यालय, साऊथ कैंपस, नई दिल्ली
डा. मंगल दुबे	बी.बी./35, अधिकारी फ्लैट, शास्त्री नगर, पटना

कार्यकारी समिति के सदस्य

डॉ. आर. वी. वैद्यनाथ अय्यर	संयुक्त सचिव (योजना),.मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (शिक्षा विभाग), नई दिल्ली
संयुक्त निदेशक	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

संकाय सदस्य

डा. के. जी. विरमानी	वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

सचिव

के. एल. दुआ	कार्यकारी कुलसचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

1990-91

परिशिष्ट II

कार्यकारी समिति के सदस्य

(31 मार्च 1991)

1. प्रोफसर सत्यभूषण — अध्यक्ष
   निदेशक
   राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
   नई दिल्ली

2. वित्त सलाहकार
   मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   (शिक्षा विभाग)
   नई दिल्ली

3. डॉ. आर. वी. वैद्यनाथ अय्यर
   संयुक्त सचिव (योजना)
   मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   शिक्षा विभाग
   नई दिल्ली

4. श्री एम.आर. कोलहाटकर
   सलाहकार (शिक्षा)
   योजना आयोग
   योजना भवन
   नई दिल्ली

5. सुश्री कुमुद बंसल
   तकनीकी शिक्षा सचिव
   महाराष्ट्र सरकार
   बंबई

6. डॉ. एन. आर. सेठ
भूतपूर्व निदेशक
भारतीय प्रबन्ध संस्थान
वस्त्रपुर
अहमदाबाद 380015

7. संयुक्त निदेशक
नीपा
नई दिल्ली

8. श्री के. एल. दुआ — सचिव
कार्यकारी कुलसचिव
नीपा
नई दिल्ली

1990-91

परिशिष्ट III

वित्त समिति के सदस्य

(31 मार्च 1991)

1. प्रो. सत्यभूषण — अध्यक्ष
   निदेशक
   राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
   नई दिल्ली

2. वित्त सलाहकार
   मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   शिक्षा विभाग
   नई दिल्ली

3. डॉ. आर. वी. वैद्यनाथ अय्यर
   संयुक्त सचिव (योजना)
   मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   शिक्षा विभाग
   नई दिल्ली

4. डॉ. घनश्याम दास
   निदेशक (उच्च शिक्षा सचिवालय)
   उड़ीसा सरकार
   भुवनेश्वर — 751001

5. संयुक्त निदेशक
   राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
   प्रशासन संस्थान
   नई दिल्ली

6. श्री के. एल. दुआ — सचिव
   कार्यकारी कुल सचिव
   राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
   नई दिल्ली

1990-91

परिशिष्ट IV

कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्य

(31 मार्च 1991)

1. प्रो. सत्यभूषण — अध्यक्ष
   निदेशक
   राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
   दिल्ली

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

2. प्रो. जे. एस. राजपूत
   संयुक्त सचिव सलाहकार
   (प्रारंभिक शिक्षा ब्यूरो)
   मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   शिक्षा विभाग, नई दिल्ली

3. डॉ आर. वी. वैद्यनाथ अय्यर
   संयुक्त सचिव (योजना)
   मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   शिक्षा विभाग
   नई दिल्ली

4. श्री एल. मिश्रा
   संयुक्त सचिव और महानिदेशक
   राष्ट्रीय साक्षरता मिशन
   मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   शिक्षा विभाग
   नई दिल्ली

1990-91

योजना आयोग

5. श्री एम. आर. कोलहाटकर
सलाहकार (शिक्षा)
योजना आयोग
नई दिल्ली

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

6. श्री टी. एन. चतुर्वेदी
सचिव
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली - 110002

राज्य शिक्षा सचिव और जन शिक्षा निदेशक

7. सुश्री ए. के. आहुजा
आयुक्त और सचिव (राजस्थान)
शिक्षा विभाग, जयपुर
राजस्थान - 302004

8. श्री टी. वेंका रेड्डी, भा.प्रशा.से.
निदेशक (विद्यालय शिक्षा)
आंध्र प्रदेश
हैदराबाद - 500004

अकादमिक सदस्य

9. प्रो. इकबाल नारायण
कुलपति
नार्थ ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय
लोवर लाक्यूमियर
शिलांग - 793001

10. डॉ. डी. डी. नरूला
अवैतनिक वरिष्ठ अध्येता
विकास अध्ययन संस्थान
डी. 124 ए. मंगल मार्ग
बापू नगर मंगल जयपुर
राजस्थान

11. डॉ. पी. आर. पंचमुखी
भूतपूर्व निदेशक
भारतीय शिक्षा संस्थान
128/2, कार्वे रोड, कोतरूड
पुणे - 411007, महाराष्ट्र

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

12. प्रो. एम. के. रैना
अध्यापक शिक्षा विभाग
विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
नई दिल्ली

संकाय सदस्य

13. डॉ. एम. मुखोपाध्याय
वरिष्ठ अध्येता
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

14. डॉ. आर. गोविन्द
वरिष्ठ अध्येता
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

15. डॉ. जी. डी. शर्मा
वरिष्ठ अध्येता
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

16. श्री के. एल. दुआ — सचिव
कार्यकारी कुलसचिव
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

1990-91

परिशिष्ट V

संकाय तथा प्रशासनिक स्टाफ

(31 मार्च 1991)

सत्यभूषण, निदेशक

शैक्षिक प्रशासन एकक

एम. एम. मुखोपाध्याय वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
सी. मेहता, अध्येता (अवकाश पर विदेश में)
के. सुजाता, अध्येता
ए. मैथ्यू, सह-अध्येता
मंजू नरूला, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

शैक्षिक वित्त एकक

जे. वी. जी. तिलक, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
वीरा गुप्ता, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

शैक्षिक योजना एकक

श्रीप्रकाश, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
ब्रह्म प्रकाश, वरिष्ठ अध्येता (इ. ओ. एल. पर विदेश में)
अरुण सी. मेहता, सह-अध्येता
रंजना श्रीवास्तव, सह-अध्येता
एस. एम. आई. ए. ज़ैदी, सह-अध्येता
प्रभा देवी अग्रवाल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

शैक्षिक नीति एकक

सुश्री कुसुम के. प्रेमी, अध्येता और अध्यक्ष
प्रमिला मेनन, सह-अध्येता
नलिनी जुनेजा सह-अध्येता (अध्ययन अवकाश पर)
एम. मलिक, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

1990-91

उच्च शिक्षा एकक

जी. डी. शर्मा, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
जयलक्ष्मी इंदिरेसन, वरिष्ठ अध्येता
के. सुधा राव, अध्येता
आशा मीना, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

अंतर्राष्ट्रीय एकक

के. जी. विरमानी, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
अंजना मंगलागिरि, सह-अध्येता
सुनीता चुग, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा एकक

आर. गोविंद, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
सुषमा भागिया, अध्येता
वाई.पी. अग्रवाल, अध्येता
सुदेश मुखोपाध्याय, अध्येता
वी. के. पांडा, वरिष्ठ तकनीकी सहायक
वी. पी. एस. राजू, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

प्रादेशिक प्रणाली एकक

एम. एम. कपूर, अध्येता और अध्यक्ष
आर. एस. शर्मा, अध्येता
एस. सी. नुना, अध्येता
एन. वी वर्गीस, अध्येता
जयश्री जलाली, सह-अध्येता

हिंदी कक्ष

एस. बी. राय, हिंदी संपादक

1990-91

प्रकाशन एकक

एम. एम. अजवानी, सहायक प्रकाशन अधिकारी

मानचित्रण कक्ष

पी. एन. त्यागी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

समन्वयन

कौसर विजारत, वरिष्ठ तकनीकी सहायक पुस्तकाध्यक्ष

इलेक्ट्रानिक डेटा प्रोसेसिंग और रिप्रोग्राफिक एकक

श्री बी. एच. श्रीधर, कम्प्यूटर प्रोग्रामर

पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र एकक

निर्मल मल्होत्रा, पुस्तकाध्यक्ष
एन. डी. कांडपाल, प्रलेखन अधिकारी
दीपक मकोल, पुस्तकाध्यक्ष ग्रेड II

प्रशिक्षण कक्ष

योगेश्वर प्रसाद, प्रशिक्षण सहायक

अनुसंधान परियोजना स्टाफ

एस. सी. बेहर, परामर्शदाता
ए. एन अब्रोल, परियोजना अध्येता
जे. सी. गोयल, परियोजना अध्येता
एल. सी. सिंह, परियोजना अध्येता
ए . चोपड़ा, परियोजना स्टाफ-I
एम. एम. रहमान, परियोजना सह-अध्येता
आर. के. सोलंकी, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी
आर. एस. त्यागी, परियोजना सह-अध्येता
नीरा धर, परियोजना सह-अध्येता
जी. पी. सिंह, परियोजना सह-अध्येता

एस. मजमुदार, परियोजना सह-अध्येता
वी. त्रिवेदी, प्रशिक्षण अधिकारी
भारत भूषण, परियोजना मानचित्रकार

परियोजना सहायक

पुष्पा कथूरिया
सुमित्रा चौधरी
तरु ज्योति बुढ़ागोहाइ
विश्वनाथ आलोक
जमालुद्दीन फारूकी
बासोची सरकार
सारिका सिंबु
ए. के. सिन्हा
जार्ज मैथ्यू
अशोक कुमार
राजेंद्रपाल
बी. डी. दामले
अंजना सलूजा
मु. जमीर
विधु ग्रोवर
कमलकांत विस्वाल
डी. के. दक्षिणमूर्ति
संगीता सिंह

कार्यालय प्रशासन

के. एल. दुआ, का. कुलसचिव
ओ. पी. शर्मा, वित्त अधिकारी
जी. एस. भारद्वाज, अनुभाग अधिकारी
टी. आर. ध्यानी, अनुभाग अधिकारी
एम. एल. शर्मा, अनुभाग अधिकारी
एस. आर. चौधरी, अनुभाग अधिकारी
पी. मणि, निदेशक के निजी सचिव
सुषमा असीजा, वरिष्ठ निजी सहायक
आर. सी. शर्मा, लेखाकार

1990-91

परिशिष्ट - VI

वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट

1990-91

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान : नई दिल्ली
वर्ष 1990-91 का वार्षिक लेखा
1.4.1990 से 31.3.91 तक की प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा

प्राप्तियां		
अर्थ शेष		
हस्तगत रोकड़ा	1,137.00	
अग्रदाय	1,000.00	
बैंक में रोकड़	2,507,403.53	2,509,540.53
भारत सरकार से प्राप्त सहायता		
योजनेतर	9,824,000.00	
योजना	6,932,000.00	16,756.000.00
कार्यालय प्राप्तियां		
लाइसेंस शुल्क	47,529.00	
पानी तथा बिजली बिल	5,221.00	
इ. डी. पी. आर. प्राप्तियाँ	500.00	
फोटोकापी प्राप्तियां	62,403.50	
प्रकाशन रायलटी	7,965.50	
अन्य विविध प्राप्तियां	12,119.90	
अवकाश वेतन और पेंशन	47,956.00	
नियोक्ता अंश सी.पी.एफ. अर्थदंड	8,759.00	

1990-91

भुगतान

संस्थागत व्यय

(योजनेतर)		
वेतन	5,898,963.00	
पेंशन और उपदान	495,496.00	
नियोक्ता अंश और जी.पी.एफ. तथा सी.पी.एफ.	355,410.00	
अवकाश वेतन और पेंश्न	21,541.00	
यात्रा व्यय	37,628.00	6,809,038.00
(योजना)		
वेतन	46,219.00	46,219.00
कार्यालय व्यय		
योजनेतर	1,718,603.90	
योजना	1,000,000.00	2,718,603.90
छात्रावास		
आवर्ती व्यय (योजनेतर)	198,441.00	
गैर आवर्ती व्यय-योजना	23,019.00	221,460.00

1990-91

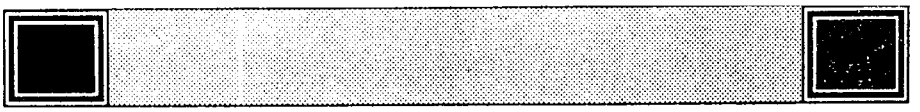

प्राप्तियां

पेंशनकर्ता का अर्थ से संबंधित मूल्य	69,975.00	
कार्यक्रम प्राप्तियां	151,268.97	413,697.87
छात्रावास किराया		319,575.00
उपहार तथा चंदे के माध्यम से प्राप्त (पुस्तकालय की पुस्तकें)		325.00
ब्याज		
ब्याज वाली पेशगियों पर ब्याज	44,342.00	
अल्पकालिक जमा राशि पर ब्याज	109,835.57	
बचत बैंक लेखा पर ब्याज	43,680.00	
जी.पी.एफ./सी.पी.एफ. निवेश पर ब्याज	249,883.00	447,740.57
प्रतिभागियों से प्राप्त राशि		5,585.70
जमा		
उचंत लेखा	39,884.00	39,884.00
सुरक्षा जमा		9,500.00
प्रायोजित कार्यक्रम और अध्ययन		
कार्यक्रम और अध्ययन प्राप्तियां		6,357,325.00

1990-91

भुगतान		
अकादमिक गतिविधियां (योजनेतर)		
कार्यक्रम व्यय	1,109,531.00	
अनुसंधान अध्ययन	746,731.00	
प्रकाशन	241,364.00	2,097,626.00
स्टाफ प्रशिक्षण (योजनेतर)		9,750.00
अकादमिक गतिविधियां (योजना)		
कार्यक्रम व्यय	8,344.00	
अनुसंधान अध्ययन	750,406.00	
सहायता योजना	100,770.00	
विश्व बैंक संगोष्ठी	190,745.00	1,050,265.00
पुस्तकालय पुस्तकें उपहार स्वरूप प्राप्त	250,506.00	
	325.00	250,831.00
पूंजी व्यय (योजना)		
फर्नीचर और फिक्सचर	211,275.00	
अन्य कार्यालय उपकरण	20,258.00	231,533.00
जमा		
के.लो.नि.वि. के पास जमा (योजना)		5,394,813.00
उचंत लेखा		9,838.00
सुरक्षा जमा वापसी		7,500.00
जी.एस.एल.आई. योजना		1,652.00

1990-91

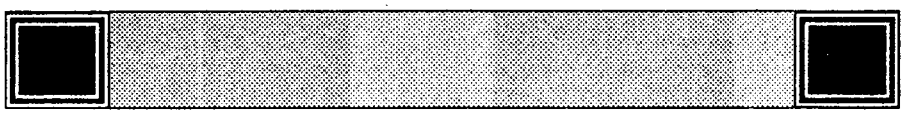

प्राप्तियां

वसूली योग्य पेशगियां

साइकिल पेशगी	9,130.00	
स्कूटर पेशगी	40,535.00	
त्यौहार पेशगी	25,780.00	
मोटरकार पेशगी	166,808.00	
भवन निर्माण पेशगी	127,680.00	
पंखा पेशगी	1,000.00	
संगणक पेशगी	7,200.00	378,133.00
विविध पेशगी (एन.सी.टी.-II)		297.00

प्रेषित रकम

जी.एस.एल.आई. योजना	1,904.00

योग :	**27,239,507.67**

ह.
(ओ.पी. शर्मा)
वित्त अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली - 110 016

1990-91

भुगतान		
प्रायोजित कार्यक्रम और अध्ययन		
कार्यक्रम और अध्ययन व्यय	3,562,568.57	3,562,568.57
वसूली योग्य पेशगियां		
साइकिल पेशगी	6,000.00	
स्कूटर पेशगी	11,000.00	
त्यौहार पेशगी	28,400.00	
भवन निर्माण पेशगी	83,200.00	
मोटरकार पेशगी	188,000.00	
पंखा पेशगी	840.00	
संगणक पेशगी	37,600.00	355,040.00
विविध पेशगी		3,595.00
रोकड़ बाकी		
हस्तगत रोकड़	5,599.00	
अग्रदाय	1,000.00	
बैंक में रोकड़	4,462,576.20	4,469,175.20
योग :		**27,239,507.67**

ह.
(सत्यभूषण)
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली - 110 016

1990-91

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
रोकड़ बाकी का विवरण (31 मार्च 1991)

	शीर्ष	रोकड़ जमा	अनुदान
1.	योजनेतर	176,250.52	9,824,000.00
2.	योजना	1,567,815.78	6,932,000.00
3.	प्रायोजित कार्यक्रम/अध्ययन	741,175.06	6,357,325.00
4.	उचंत लेखा	26,203.17	—
5.	जमा	—	—
6.	प्रेषित राशि (-)	(-) 1,904.00	—
	योग	2,509,540.53	23,113,325.00

ह.
(ओ.पी. शर्मा)
वित्त अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना
और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली - 110 016

1990-91

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
रोकड़ बाकी का विवरण (31 मार्च 1991)

अन्य प्राप्तियां	योग	भुगतान	शेष
1,565,057.14	11,565,307.66	11,193,745.90	371,561.76
—	8,499,815.78	7,996,680.00	503,135.78
297.00	7,098,797.06	3,562,568.57	3,536,228.49
39,884.00	66,087.17	9,838.00	56,249.17
9,500.00	9,500.00	7,500.00	2,000.00
1,904.00	शून्य	—	—
1,616,642.14	27,239,507.67	22,770,332.47	4,469,175.20

ह.
(सत्यभूषण)
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना
और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली - 110 016

1990-91

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
वर्ष 1990-91 का आय और व्यय लेखा

व्यय	
स्थापना व्यय	6,855,257.00
कार्यालय व्यय	2,718,603.90
स्टाफ प्रशिक्षण	9,750.00
छात्रावास व्यय	198,441.00
अकादमिक गतिविधियां	3,147,891.00
आय से अधिक व्यय	
व्यय से अधिक आय	4,510,712.54
योग	17,440,655.44

ह.
(ओ.पी. शर्मा)
वित्त अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना
और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

1990-91

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
वर्ष 1990-91 का आय और व्यय लेखा

आय		
सहायता अनुदान	16, 756, 000.00	
सहायता अनुदान को छोड़कर पूंजीकृत आय		
कार्यालय वस्तुएं	254, 552.00	
पुस्तकालयों की पुस्तकें	250, 506.00	16, 250, 942.00
कार्यालय प्राप्तियाँ		413, 697.87
हॉस्टल किराया	319,575.00	
उपचय किराया	8,700.00	328, 275.00
ब्याज		447, 740.57
योग		17, 440, 655.44

ह.
(सत्यभूषण)
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना
और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान : नई दिल्ली
तुलनपत्र (31 मार्च 1991)

देयताएं		
पूंजीकृत अनुदान		
पिछली तालिका के अनुसार शेष राशि	22,979,037.84	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	505,058.00	
परिवर्धन (समायोजन)	2,173,160.07	
परिवर्धन संशोधन	0.05	
घटाएं पूंजीनिवेश बट्टे खाते में	18,488.63	25,638,767.33
प्रायोजित कार्यक्रम प्राप्तियां		
पूंजीकृत प्राप्तियां	720,693.00	720,693.00
पूंजीकृत प्रायोजित कार्यक्रम (सी. ओ. पी. ई./एम. आई. एस.)	611,600.00	611,600.00
व्यय से अधिक आय		
पिछली तालिका के अनुसार शेष राशि	5,546,944.89	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	4,510,712.54	
घटाएं (समायोजन)	2,173,160.07	
घटाएं (संशोधन)	0.05	7,884,497.31

1990-91

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान : नई दिल्ली
तुलनपत्र (31 मार्च, 1991)

परिसंपत्तियां

भूमि तथा भवन

पिछली तालिका के अनुसार	13,613,016.66	
शेष राशि		
परिवर्धन (समायोजन)	2,173,160.07	
वर्ष के दौरान अन्य परिवर्धन	0.05	
के. लो. नि. वि. की वापसी घटाएं	—	15,786,176.78
स्टाफ मोटरकार, टंकण संगणक आदि सहित फर्नीचर और फिक्सचर		
पिछली तालिका के अनुसार		
शेष राशि	8,500,705.93	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	254,552.00	
घटाएं : बट्टे खाते में (1988-89)	—	8,755,257.93

पुस्तकालय की पुस्तकें

पिछली तालिका के अनुसार		
शेष राशि	2,202,245.56	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	250,506.00	
उपहारों और चंदे के द्वारा परिवर्धन	325.00	
घटाएं : बट्टे खाते में	18,488.63	2,434,587.93

भविष्य निधि निवेश

पिछली तालिका के अनुसार शेष राशि	2,630,000.00	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	200,000.00	2,830,000.00

1990-91

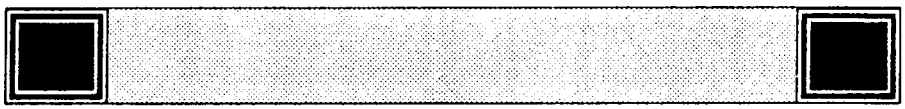

देयताएं

निर्धारित कार्यक्रम और अध्ययन

पिछली तालिका के अनुसार शेष राशि	765,935.96	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	6,357,325.00	
घटाएं वर्ष के दौरान व्यय	3,562,568.57	3,560,692.39

भविष्य निधि

पिछली तालिका के अनुसार शेष राशि	2,904,888.00	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,829,990.00	
घटाएं वर्ष के दौरान निकाली गई राशि	1,541,367.00	3,193,511.00

उचंत लेखा

पिछली तालिका के अनुसार शेष राशि	26,203.17	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	39,884.00	
घटाएं वर्ष के दौरान समाशोधन	9,838.00	56,249.17

1990-91

परिसंपत्तियां

जमा

पिछली तालिका के अनुसार शेष राशि	52,990.00	52,990.00

के. लो. नि. वि. के पास जमा

पिछली तालिका के अनुसार शेष राशि	2,630,555.89	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	5,394,813.00	
घटाएं : वापसी	2,173,160.07	
घटाएं समायोजन	0.05	5,852,208.77

वसूली योग्य पेशगियां

मोटरकार पेशगी	412,820.00	
भवन निर्माण पेशगी	455,544.00	
त्यौहार पेशगी	19.980.00	
साइकिल पेशगी	3,940.00	
स्कूटर पेशगी	72,230.00	
संगणक पेशगी	117,485.00	
पंखा पेशगी	280.00	
विविध पेशगी (नीपा)	6,970.00	
स्थानांतरण पेशगी	7,000.00	1,096,249.00
विविध पेशगी (एन.सी.टी.-II)		24,463.90

1990-91

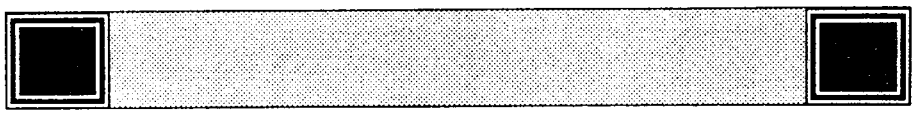

देयताएं

उपहार और दान

पिछली तालिका के अनुसार शेष राशि	4,637.31	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	325.00	4,962.31

जमा

पिछली तालिका के अनुसार शेष राशि	2,500.00	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	4,500.00	
वर्ष के दौरान समाशोधन	2,500.00	4,500.00
योग		41,675,472.51

ह.
(ओ. पी. शर्मा)
वित्त अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

1990-91

परिसंपत्तियां

प्रेषित राशि

जी. एस. एल. आई. योजना		
पिछले वर्ष के अनुसार शेष राशि	1,904.00	
घटाएं वर्ष के दौरान समाशोधन	252.00	1,652.00
छात्रावास किराए पर उपचय आय		8,700.00

विविध देनदार

पिछली तालिका के अनुसार शेष राशि	6,085.70	
घटाएं वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	5,585.70	
वर्ष के दौरान समाशोधन		500.00

शेष रोकड़

हस्तगत रोकड़	5,599.00	
अग्रदाय	1,000.00	
चालू खाता	4,462,576.20	
जी. पी. एफ./सी. पी. एफ. लेखा	363,511.00	4,832,686.20
	योग	41,675,472.51

ह.

(सत्यभूषण)

निदेशक

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और

प्रशासन संस्थान

नई दिल्ली

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान : नई दिल्ली
31 मार्च 1991 के निर्धारित कार्यक्रम/अध्ययन का लेखा प्रपत्र

क्र.सं.	कार्यक्रम/अध्ययन का नाम	अर्थ शेष 1.4.90	प्राप्तियां	योग	व्यय	शेष
1	2	3	4	5	6	7
	भारत सरकार					
1.	गृह मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) • अ. जा. के शैक्षिक विकास की अध्ययन इकाई	(-) 116,398.25	-	(-) 116,398.25	-	(-) 116,398.25
2.	राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-II • केंद्रीय तकनीकी एकक • आयोग दौरे का संगठन	128,963.55	-	128,963.55	250.00	128,713.55
3.	प्रायोगिक परियोजना : अनौपचारिक शिक्षा—मूल्यांकन अध्ययन (शिक्षा मंत्रालय)	24,923.36	-	24,923.36	-	24,923.36
4.	केब समिति-शिक्षकों का स्थानांतरण	35,558.00	-	35,558.00	2,204.00	33,354.00
5.	अनौपचारिक शिक्षा सहित प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा का प्रायोगिक और नवीन कार्यक्रम	33,594.40	630,000.00	663,594.40	397,308.00	266,286.40

क्र.सं.	कार्यक्रम/अध्ययन का नाम	अर्थ शेष 1.4.90	प्राप्तियां	योग	व्यय	शेष
1	2	3	4	5	6	7
6.	जिला शिक्षा अधिकारी के लिए एम. आई. एस. (एस. दासगुप्ता)	(-) 26,431.10	1,399,210.00	1,372,778.90	128,293.00	1,244,485.90
	योजना आयोग					
7.	शिक्षा और रोजगार के बीच लाभदायक संबंधों का अध्ययन	13,372.90	-	13,372.90	-	13,372.90
8.	वर्तमान सुविधाओं का बेहतर उपयोग	8,116.00	-	8,116.00	16,579.00	(-) 8,463.00
	आई. सी. एस. एस. आर., नई दिल्ली					
9.	भारत में सामाजिक विज्ञान से संबंधित अनुसंधान के लिए वित्त व्यवस्था पर अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत एकत्रित आंकड़ों के विश्लेषणात्मक मोनोग्राफ का निर्माण	9,269.60	-	9,269.60	9,269.60	0.00
	अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम और अध्ययन					
10.	शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा	462,104.64	1,258,355.00	1,720,459.64	919,251.00	801,208.64
11.	उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय सहयोग कार्यक्रम : शिक्षण प्रविधि	17,579.15	-	17,579.15	17,579.15	0.00

क्र.सं.	कार्यक्रम/अध्ययन का नाम	अर्थ शेष 1.4.90	प्राप्तियां	योग	व्यय	शेष
1	2	3	4	5	6	7
12.	पर्यावरण शिक्षा पर परामर्श-कारी बैठक	10,136.75	-	10,136.75	10,136.75	0.00
13.	व्यष्टि स्तरीय शैक्षिक योजना पर क्षेत्रीय विकास कार्यशिविर	29,777.67	-	29,777.67	29,777.67	0.00
14.	माध्यमिक शिक्षा पर ए. पी. ई. आई. डी. योजना मंडल बैठक	3,775.40	-	3,775.40	3,775.40	0.00
15.	उच्च शिक्षा में समता, गुणवत्ता और व्यय पर अध्ययन	20,954.13	-	20,954.13	0.00	20,954.13
16.	उच्च शिक्षा में संसाधन की प्रविधि पर एक परियोजना	(-) 10,560.00	22,560.00	12,000.00	0.00	12,000.00
17.	संगणकों का प्रभावी उपयोग (वि.अ.अ.)	32,000.00	0.00	32.000.00	0.00	32,000.00
18.	विकेंद्रीकरण के लिए व्यष्टि स्तरीय शैक्षिक योजना और प्रबंध (डॉ. ब्रह्मप्रकाश)	8,944.61	0.00	8.944.61	0.00	8,944.61
19.	(अ) पर्यावरण शिक्षा, यूनेस्को पर अंतर्क्षेत्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (डॉ. आर. गोविंद)	85,559.15	136,800.00	222,359.15	209,970.00	12,389.15
	(ब) पर्यावरण पर शैक्षिक योजनाकारों के लिए हैंडबुक	0.00	51,900.00	51,900.00	0.00	51,900.00

क्र.सं.	कार्यक्रम/अध्ययन का नाम	अर्थ शेष 1.4.90	प्राप्तियां	योग	व्यय	शेष
1	2	3	4	5	6	7
20.	जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए छः सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रौढ़ शिक्षा)	(-) 5,304.00	271,500.00	266,296.00	264,015.00	2,181.00
21.	नई शिक्षा नीति पर पुनरीक्षण समिति	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,352,743.00	147,257.00
22.	शिक्षा के लिए प्रतिदर्श सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग	0.00	0.00	0.00	12,600.00	(-) 12,600.00
23.	प्रारंभिक शिक्षा की प्रविधि का संचारेक्षण	0.00	200,000.00	200,000.00	127,945.00	72,055.00
24.	उत्तर प्रदेश में सबके लिए शिक्षा—विश्व बैंक सहायता पूर्व परियोजना गतिविधियां (इटावा)	0.00	200,000.00	200,000.00	57,542.00	142,458.00
25.	शैक्षिक तकनीक योजना का मूल्यांकन अध्ययन	0.00	672,000.00	672,000.00	60.00	671,940.00
26.	अध्येता यूनेस्को-चीन	0.00	15,000.00	15,000.00	3,270.00	11,730.00
	योग	765,935.96	6,357,325.00	7,123,260.96	3,562,568.57	3,560,692.39

ह.
(ओ. पी. शर्मा)
वित्त अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

ह.
(सत्यभूषण)
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान : नई दिल्ली
वर्ष 1990-91 के लिए जी. पी. एफ./सी. पी. एफ. की प्राप्तियां और भुगतान लेखा

प्राप्तियां		भुगतान		
अर्थ शेष	274,888.00	पेशगियां और निकासी	1,541,367.00	
अंशदायी और पेशगियों की वापसी	1,469,110.00	जमा में निवेश	200,000.00	
कर्मचारी द्वारा नियोक्ता का भुगतान	5,470.00	निकासी घटाएं		1,741,367.00
ब्याज, नियोक्ताओं का अंशदान आदि	355,410.00	अंतः शेष		363,511.00
योग	2,104,878.00			2,104,878.00

ह.
(ओ. पी. शर्मा)
वित्त अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

ह.
(सत्यभूषण)
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र

मैंने राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली, के 31 मार्च 1991 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के आगत और भुगतान लेखा/आय और व्यय लेखा तथा 31 मार्च, 1991 के तुलन पत्र की जांच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं तथा संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभियुक्तियों के आधार पर अपनी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरी राय में तथा मेरी जानकारी और मुझे दिए गए स्पष्टीकरण एवं संस्थान की बहियों में दर्शाए गए विवरणों के अनुसार ये लेखे और तुलनपत्र उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं तथा संस्थान के कार्यकलापों का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14.02.1992

ह.
महानिदेशक, लेखा परीक्षा
केंद्रीय राजस्व

लेखा परीक्षा रिपोर्ट

(वर्ष 1990-91 के लिए)

1. प्रस्तावना

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (नीपा) पहले शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के राष्ट्रीय स्टाफ कालेज के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना एक स्वायत्त संस्था के रूप में हुई थी और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1980 के अंतर्गत इसे पंजीकृत किया गया था। प्रारंभ में दिनांक 31 दिसंबर, 1970 को इसे राष्ट्रीय स्टाफ कालेज के नाम से पंजीकृत किया गया था। 31 मई, 1979 को इसे वर्तमान नाम से पंजीकृत किया गया। संस्थान का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक योजना और प्रशासन के विविध क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान के कार्यों का मार्गदर्शन करना तथा अनुदान तथा सह-अनुसंधान के माध्यम से इन क्षेत्रों के कार्यों में पर्याप्त रूप से विकास करना है।

संस्थान की वित्तीय व्यवस्था मुख्य रूप से केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए अनुदान पर आधारित है। वर्ष 1990-91 के दौरान नीपा ने 167.56 लाख रुपए (योजनेतर के अंतर्गत 98.24 लाख रुपए और योजना के अंतर्गत 69.32 लाख रुपए) प्राप्त किए। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 की धारा 20 (1) (कार्य, शक्ति और सेवाशर्तें) के तहत इस संस्थान की लेखा का अंकेक्षण किया गया है।

2. लेखा संबंधी टिप्पणियां

2.1 पुस्तकालय की पुस्तकों का भौतिक सत्यापन

संस्थान के पुस्तकालय में 55080 पुस्तकें हैं। नियम के मुताबिक पचास हजार से अधिक पुस्तकों वाले पुस्तकालय में 5

वर्ष के अंतराल पर नियमित रूप से पुस्तकों का भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। संस्थान ने पुस्तकालय की पुस्तकों का भौतिक सत्यापन नहीं किया था। मार्च, 1986 के बाद वर्ष 1990-91 में पुस्तकों का अगला भौतिक सत्यापन किया जाना था, जो कि नहीं किया गया था।

जनवरी, 1992 में संस्थान ने बताया कि पुस्तकों के भौतिक सत्यापन का कार्य चल रहा है।

2.2 बकाया विविध पेशगी – 0.24 लाख रुपए

राष्ट्रीय अध्यापक आयोग-II के संबंध में शिक्षा विभाग ने संस्थान को कार्यशिविर आयोजित करने का कार्य सौंपा था। इसके लिए संस्थान ने वर्ष 1983-84 में विभिन्न विश्वविद्यालयों और शोधकर्त्ताओं को 2.95 लाख रुपए बतौर पेशगी दिए। 31 मार्च, 1991 तक उपर्युक्त रकम में से 0.24 लाख रुपए विभिन्न विश्वविद्यालयों/शोधकर्ताओं पर बकाया है।

संस्थान ने अक्टूबर 1991 और जनवरी 1992 में बताया कि उक्त रकम की अदायगी/समायोजन के लिए काफी जोर शोर से प्रयास किए जा रहे हैं।

2.3 केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में बकाया जमा राशि (कें. लो. नि. वि.)

(अ) 31 मार्च, 1991 तक 42 निर्माण कार्यों के लिए लो. नि. वि. के पास 58.52 लाख रुपए बकाया जमा राशि थी। वर्ष 1983-84 से बकाया राशि संबंधी विवरण निम्न थे :

जमा वर्ष	बकाया राशि (लाखों में)
1983-84	0.79
1984-85	0.24
1987-88	(-) 1.66
1988-89	4.24
1989-90	5.69
1990-91	49.22
योग	**58.52**

(ब) लेखा में दिए गए 58.52 लाख रुपए की प्रामाणिकता सत्यापित नहीं की जा सकी, क्योंकि जमाराशि का रजिस्टर ठीक प्रकार से तैयार नहीं किया गया था। संस्थान ने अक्टूबर 1991 में बताया कि रजिस्टर को अद्यतन बनाया जा रहा है ताकि समायोजनों को ठीक प्रकार से पेश किया जा सके।

(स) 13 निर्माण कार्यों के लिए कुल 8.92 लाख रुपए (यह रकम कुल 58.52 लाख रुपए की रकम में शामिल है) जमा किया गया था। ये कार्य पूरे हो चुके थे मगर अभी तक जमा राशियों का समायोजन नहीं किया गया था।

जनवरी, 1992 में संस्थान ने बताया कि इन जमाराशियों का समायोजन करके बकाया रकम को नए निर्माण कार्यों के लिए जमा कर दिया जाएगा या कें. सा. नि. वि. की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के बाद बकाया रकम प्राप्त कर ली जाएगी।

(द) संस्थान में 500 के. वी. ए. के एक सब स्टेशन स्थापित करने के लिए मार्च 1991 में के. सा. नि. वि. (विद्युत प्रभाग XIII) को 22.65 लाख रुपए की पेशगी राशि दी गई थी। मगर दिल्ली नगर निगम के अनापत्ति प्रमाणपत्र और दि. वि. प्र. सं. से विद्युत प्रभार की स्वीकृति न मिल पाने के कारण यह कार्य शुरू नहीं हुआ। औपचारिकताएं पूरी करने से पूर्व जमा राशि का भुगतान उचित नहीं था। इससे अनुदान सहायता राशि के उपयोग में अनियमितता की तस्वीर सामने आती है।

जनवरी 1992 में संस्थान ने बताया कि इस कार्य के लिए संबंधित विभागों से लगातार संपर्क किया जा रहा था। जमा राशि का भुगतान इसलिए कर दिया गया था कि कार्य तेजी से हो सके। क्योंकि दि. वि. प्र. सं. ने तार काटने की धमकी दी थी और अतिरिक्त भार के विद्युत व्यय के कारण संस्थान के विरुद्ध अभियोग भी लगा रहा था।

2.4 भेंट में प्राप्त पुस्तकों के मूल्य न निर्धारित करना

संस्थान को 31 मार्च, 1991 तक 2,005 पुस्तकें भेंट में मिली हैं। मगर अभी तक इन पुस्तकों को कीमतें निर्धारित नहीं की गई हैं। इन पुस्तकों की कीमतों को न तो परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है और न ही तुलनपत्र के तहत इन्हें 'भेंट तथा चंदा के मद में दर्शाया गया है।'

संस्थान ने एक समिति के समक्ष भेंट में प्राप्त पुस्तकों और दस्तावेजों के मूल्य निर्धारित करने के मसले को रखा था। संस्थान ने अक्टूबर, 1991 में बताया कि पुस्तकालय को भेंट में प्राप्त पुस्तकों और दस्तावेजों के मूल्य निर्धारित करने से किसी मकसद की खास पूर्ति नहीं दिखाई पड़ रही है।

संस्थान का तर्क सही नहीं है। अगर इन पुस्तकों और दस्तावेजों को कोई इस्तेमाल के लिए ले जाता है और खो देता है तो संस्थान इनकी कीमतें नहीं वसूल कर सकता। इसके अलावा तुलनपत्र में परिसंपत्तियों की वास्तविक कीमत भी प्रदर्शित नहीं हो पाती है।

जनवरी, 1992 में संस्थान ने बताया कि अगले वित्तीय वर्ष में भेंट में प्राप्त पुस्तकों और दस्तावेजों के मूल्य संबंधी ब्यौरे भी शामिल कर लिए जाएंगे।

2.5 उचंत लेखा

31 मार्च, 1991 के तुलनपत्र की देयताएं के तहत प्रदर्शित 0.56 लाख रुपए के उचंत लेखा की रकम के वर्षवार ब्यौरे निम्न हैं :

वर्ष	मदों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)
1987-88	1	0.04
1988-89	1	0.01
1989-90	2	0.11
1990-91	2	0.40
योग	**6**	**0.56**

संस्थान ने अक्टूबर, 1991 में बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में उचंत लेखा को शून्य कर दिया जाएगा।

संस्थान ने जनवरी 1992 में स्पष्ट किया कि रु. 54684 की रकम का स्पष्टीकरण हो गया है तथा इसे वर्ष 1991-92 में जमा कर दिया जाएगा।

3. नियत कार्यक्रम/अध्ययन पर हुए 1.37 लाख रुपए के अतिरिक्त व्यय की अप्रतिपूर्ति

संस्थान ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रायोजित कई अध्ययन संचालित किए। यह संस्थान विभिन्न अभिकरणों से उनके द्वारा प्रयोजित किए जाने वाले अनुसंधान अध्ययनों के एवज में अनुदान प्राप्त करता है। संस्थान के रिकार्डों की छानबीन से पता चला कि संस्थान ने तीन कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए 1.37 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय वहन किया है। इनमें से 1.16 लाख रुपए पिछले पांच वर्षों से कल्याण मंत्रालय पर बकाया है।

संस्थान ने जनवरी, 1992 में स्पष्ट किया था कि कल्याण मंत्रालय से रु. 21,963.00 की रकम प्राप्त हुई है और उस पर अभी 1.16 लाख रुपए बकाया है। इसकी वसूली के लिए मंत्रालय से बातचीत चल रही है।

4. अधिकारियों को दी गई विविध पेशगियों के समायोजन में अनियत विलंब

वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान संस्थान के अधिकारियों को दी गई विविध पेशगियों की छानबीन से पता चला कि 23 मामलों के तहत 0.56 लाख की बकाया रकम है। एक से सात महीने तक 0.09 लाख की रकम रखने के बाद ही अधिकारियों से पूरी रकम की वसूली हो पाई थी।

30 मामलों के तहत 1.16 लाख रुपए बकाया था जिनका भुगतान एक से लेकर 6 महीने तक विलंब से हुआ।

अनेक मामलों में यह भी देखा गया कि पहली पेशगी के भुगतान के पहले दूसरी पेशगी दे दी गई।

पेशगियों की पूरी अदायगी और जमा में नियमितता न होने के कारण अधिकारियों पर गैर जरूरी अनुदानों का भुगतान किया गया।

संस्थान ने जनवरी, 1992 में स्पष्ट किया कि लेखापरीक्षा के निरीक्षण के अनुपालन के लिए पहली पेशगी की अदायगी के बगैर दूसरी पेशगी का भुगतान नहीं किया जाएगा।

5. आंतरिक लेखा परीक्षा

वर्ष 1990-91 के दौरान संस्थान का कुल व्यय 129.30 लाख रुपए था। फिर भी आदान-प्रदान की जांच, रिकार्डों के रख-रखाव और नियमों तथा आदेशों के पर्यावेक्षण के लिए संस्थान में आंतरिक लेखापरीक्षण की व्यवस्था नहीं है। अतः यह बता दिया गया कि जनवरी 1991 से आंतरिक लेखा प्रणाली शुरू कर दी गई है तथा इस कार्य को करने के लिए एक लेखाकार नियुक्त किया गया है। इसमें लेखाकार के निम्न कार्य हैं : बजट और संशोधित बजट की तैयारी, अनुदान और वित्तीय सहायता वाले परियोजनाओं तथा नीपा के परियोजनाओं के संबंध में पत्राचार और अनुभाग अधिकारी तथा वित्त अधिकारी के समक्ष बिल रखने से पूर्व नियमों और आदेशों के आधार पर बिल की गहरी छानबीन।

आंतरिक लेखा परीक्षण के कार्य में स्वतंत्रता होनी चाहिए। अतः संस्थान में प्रभावी आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए उस पर उन जिम्मेवारियों को नहीं सौंपना चाहिए जिनकी लेखा परीक्षा बाद में होनी है। इस प्रकार की व्यवस्था से एक प्रभावी आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली विकसित हो सकती है। इस प्रकार की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली संस्थान में पहले से नहीं थी।

लेखा परीक्षा/निरीक्षण रिपोर्टों के बगैर कार्रवाई के आरोप

मार्च, 1991 में 3 निरीक्षण रिपोर्टों के 5 अनुच्छेदों पर संस्थान द्वारा कार्रवाई की जानी थीं। इनका वर्षवार विवरण निम्न है :

वर्ष	बगैर कार्रवाई वाले अनुच्छेदों की संख्या
1986-87	1
1987-88	2
1988-89	2
योग	**5**

इन आरोपों के समाधान की दिशा में संस्थान ने प्रभावी कदम नहीं उठाए।

ह.

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14.2.1992

महानिदेशक, लेखा परीक्षा
केंद्रीय राजस्व

वर्ष 1990-91 की अंकेक्षण रिपोर्ट की अनुच्छेदवार टिप्पणियां

अनुच्छेद 1 : प्रस्तावना : कोई टिप्पणी नहीं।

अनुच्छेद 2 : लेखा संबंधी टिप्पणियां

अनुच्छेद 2.1 : पुस्तकालय की पुस्तकों का भौतिक सत्यापन : संस्थान ने पुस्तकों के भौतिक सत्यापन संबंधी रिकार्ड तैयार कर लिए हैं। इन्हें आगामी अंकेक्षण में पेश किया जाएगा।

अनुच्छेद 2.2 : बकाया विविध पेशगियां : 2.40 लाख रुपए :

बकाया पेशगियों के समायोजन संबंधी निष्कर्ष आगामी अंकेक्षण में पेश किया जाएगा

अनुच्छेद 2.3 : केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के पास बकाया राशि : (अ) और (ब) से संबंधित बकाया राशि औऔर समायोजन संबंधी पूरे विवरण वाले रजिस्टर आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापन के लिए पेश कर दिए जाएंगे। (स) कें. सा. नि. वि. के पास बकाया रकम का समायोजन करके शेष रकम को नए निर्माण कार्य की पेशगी के रूप में जमा ककरा दिया जाएगा या के. सा. नि. वि. की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने पर बाकी रकम वसूल ली जाएगी। (द) दि. वि. प्र. र सं. द्वारा बिजली काटने की धमकी और अतिरिक्त भार की बिजली खर्च करने के कारण संस्थान पर अभियोग लगाने र के कारण जल्दी से सब-स्टेशन लगाने के लिए कें. सा. लो. नि. वि. की पेशगी दी गई थी। सब-स्टेशन के लिए जरूरी उपकरणों की खरीद की जा चुकी है। इस संबंध में पेशगी और व्यय का पूरा ब्यौरा आगामी अंकेक्षण में पेश किकया जाएगा।

अनुच्छेद 2.4 : भेंट में प्राप्त पुस्तकों के मूल्य न लगाना :

भेंट की पुस्तकों की कीमतें तय कर दी गई हैं। अगले वर्ष के तुलनपत्र में इसका उल्लेख किया जाएगा।

अनुच्छेद 2.5 : उचंत खाता : वर्ष 1991-92 के दौरान जमा राशि का हिसाब कर दिया जाएगा।

अनुच्छेद 3 : नियत कार्यक्रम/अध्ययन पर हुए 1.37 लाख रुपए के अतिरिक्त व्यय की अप्रतिपूर्ति : कल्याण मंत्रालय ा से 1.16 लाख रुपए की बकाया रकम की वसूली के लिए काफी प्रयास किया जा रहा है।

अनुच्छेद 4 : अधिकारियों की दी गई विविध पेशगियों के समायोजन में अनियत विलंब : लेखा परीक्षा के निरीक्षणों प पर ध्यान दिया गया है तथा यथाशीघ्र इन्हें समायोजित करने का प्रयास किया जा रहा है।

अनुच्छेद 5 : आंतरिक लेखापरीक्षा : लेखा परीक्षा की रिपोर्ट पर गौर किया गया है और आंतरिक लेखा परीक्षा के लिलेए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

अनुच्छेद 6 : अंकेक्षण आरोपों/निरीक्षण रिपोर्टों के बगैर कार्रवाई वाले आरोप :
इन आरोपों के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

नीपा पुस्तकालय का एक कोना

संस्थान के संगणक कक्ष का एक भाग

'अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम' का एक सत्र

पर्यावरण शिक्षा पर संस्थान द्वारा आयोजित और यूनेस्को द्वारा प्रायोजित शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों की प्रशिक्षण संगोष्ठी का एक दृश्य